राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

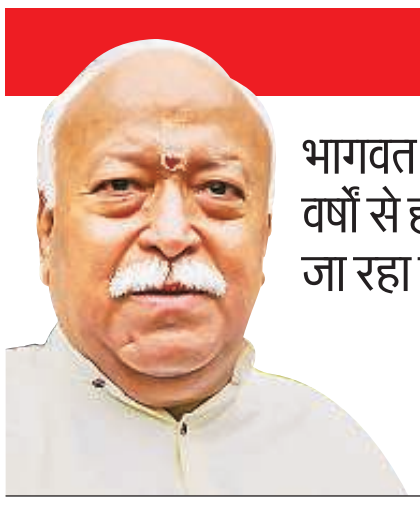

भागवत बोले, नब्बे वर्षों से हमें बनाया जा रहा है निशाना

>> 4

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 134

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 22 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

औरंगाबाद के अभिषेक ने कृषि को दिया कॉरपोरेट रूप

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद के कई गांवों में लेमनग्रास, मोरिंगा और तुलसी की खेती लहलहा रही है। इनके सम्मिश्रण से ग्रीन-टी बनाई जाती है, जो दूसरे सूबों में पहचान बना चुकी है। यहां खेती किसानी को कॉरपोरेट रूप दे दिया गया है और इसका श्रेय जाता है औरंगाबाद के ही अभिषेक को। (पेज-10)

जागरण विशेष

झारखंड सेंट्रल जेल में मौत का सौदागर बांट रहा जिंदगी

गिरिडीह : झारखंड सेंट्रल जेल (गिरिडीह) में हत्या समेत कई वारदात को अंजाम देने के मामले में बंद रामचरण आज लोगों को जिंदगी दे रहा है। आयुर्वेद पर उसकी गहरी पकड़ है। वह जेल में कैदियों और अधिकारियों-कर्मचारियों का उपचार करने लगा है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

संसद का शीत सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक

नई दिल्ली : संसद का शीत सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने यह जानकारी लोकसभा व राज्यसभा के सचिवालय को भेज दी है। इस सत्र में सरकार कई अहम बिल पास कराने का प्रयास करेगी, जबकि विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

कमलेश हत्याकांड में छापेमारी सात युवक हिरासत में

बरेली : हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के हत्यारोपितों शेख अशफाक हुसैन और पठान मोईनुद्दीन अहमद और उनके मददगारों की तलाश में बरेली मंडल में एसटीएफ व एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर से सात युवकों को हिरासत में लिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ताइवान के एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता : चीन

बीजिंग : चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे ने ताइवान के चीन के साथ एकीकरण का आह्वान करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रहे चीन स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। गृहयुद्ध के बाद यह द्वीपीय क्षेत्र 1949 में चीन से अलग हो गया था। बीजिंग यह धमकी भी दे चुका है कि ताइवान अगर चीन में नहीं मिला तो बल प्रयोग कर हासिल किया जाएगा।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

शमी-उमेश की गेंदबाजी से टेस्ट मैच भारत की मुट्ठी में

रांची : भारत के तेज गेंदबाजों मुहम्मद शमी और उमेश यादव ने शानदार प्रदर्शन कर भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जीत के द्वार पर ला खड़ा किया है। झारखंड के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के तीसरे दिन खेल समाप्त होने तक मेहमान टीम दूसरी पारी में आठ विकेट खोकर 132 रन बना संघर्ष कर रही है। उसे पारी की हार से बचने के लिए 203 रन बनाने हैं।

एक्जिट पोल में महाराष्ट्र-हरियाणा में फिर कमल

लोकतंत्र का पर्व ▶ दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान, 24 को आएंगे नतीजे

भाजपा को हरियाणा में तीन चौथाई और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ दो तिहाई सीटें मिलने का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा फिर परचम लहराती दिख रही है। सोमवार को मतदान के तुरंत बाद आए ज्यादातर एक्जिट पोल ने दोनों राज्यों में भाजपा की जबर्दस्त जीत का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को दो-तिहाई सीटें मिलने का संकेत है। वहीं, हरियाणा में सीटों का आंकड़ा तीन चौथाई तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। दोनों राज्यों का चुनाव परिणाम 24 को आएगा।

एक्जिट पोल के आंकड़े फिलहाल यह दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक से लेकर रोजगार व अन्य मुद्दों पर भाजपा को घेरने की विपक्षी दलों की कोशिश रंग नहीं ला पाई। जानकार इस नतीजे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की लोकप्रियता से भी जोड़ रहे हैं। हरियाणा में भी जाट बनाम गैर जाट से लेकर अन्य कोई भी मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना पाया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भी भाजपा के पक्ष में जाता दिखा है।

मतदान के बाद जारी हुए सभी एक्जिट पोल के अनुसार, दोनों राज्यों में भाजपा सरकार बनना तय दिख रहा है। इंडिया टुडे-एक्सिस के एक्जिट पोल में महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को 166 से 194 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को 72 से 90 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18-इप्सॉस ने महाराष्ट्र में अकेले भाजपा को 142 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। शिवसेना 102 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस और एनसीपी को क्रमशः 17 और 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य एक्जिट पोल में भी नतीजे कमोबेश ऐसे ही दिखे। 2014 में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना को क्रमशः 122 और 63 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी की संख्या क्रमशः 42 और 41 रही थी।

हरियाणा में भाजपा और भी मजबूत होती दिख रही है। एबीपी-सी वोटर के एक्जिट पोल में हरियाणा में भाजपा को 72 और कांग्रेस को आठ सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यहां तकरीबन सभी एक्जिट पोल में भाजपा को 90 में से 70 या इससे ज्यादा सीटें जीतते दिखाया गया है। 2014 के चुनाव में हरियाणा में भाजपा को 47, इनेलो को 19 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं।

इसलिए अहम हैं ये चुनाव

- प्रधानमंत्री के तौर पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी के बाद पहले विधानसभा चुनाव
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद देश में पहला चुनाव
- 2014 में नए चेहरों के रूप में देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल को कमान देने की जो पहल भाजपा ने की थी, उसे भी कसौटी पर कसा जाना है
- अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे और सोनिया के फिर कमान संभालने के बाद कांग्रेस के सामने राजनीति वापसी की चुनौती

एक्जिट पोल के नतीजे मिले-जुले रहे हैं

मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं का रुख दिखाने वाले विभिन्न एक्जिट पोल को नतीजों का पूर्वानुमान माना जाता है। विगत में कई बार इनके अनुमान असल नतीजों के बहुत करीब रहे हैं, तो कभी-कभी इनकी सटीकता पर सवाल भी उठे हैं।

हरियाणा के हिसार जिले में सोमवार को एक केंद्र पर मतदान करने के लिए कतार में खड़ी महिला मतदाता। जागरण

शुरुआती सुस्ती के बाद घरों से निकले मतदाता

महाराष्ट्र और हरियाणा में सुबह मतदान में सुस्ती दिखी। हालांकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ता गया। महाराष्ट्र में 60.46 फीसद मतदान हुआ। 2014 में लगभग 63 फीसद मतदान हुआ था। खास बात यह रही इस बार फिल्मी सितारों और गणमान्य हस्तियों ने मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। हरियाणा में मत प्रतिशत में बड़ी गिरावट दिखी। यहां 65 फीसद लोगों ने वोट दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां 76.54 फीसद वोट पड़े थे।

चुनाव पर विशेष >> पेज 4

90 सीटों के लिए हरियाणा व 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में वोटिंग

3/4 सीटें हरियाणा और दो तिहाई महाराष्ट्र में भाजपा को मिलने का अनुमान

एक्जिट पोल

हरियाणा (कुल सीटें 90)			
न्यूज चैनल्स/एजेंसियां	भाजपा	कांग्रेस	अन्य
टाइम्स नाउ	71	11	8
टीवी 9 भारतवर्ष-सीआइसीईआरओ	69	11	10
सीएनएन न्यूज 18-इप्सॉस	75	10	5
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया	–	–	–
रिपब्लिक टीवी- जन की बात	57	17	16
एबीपी-सी वोटर	72	8	10
न्यूज एक्स-पोलस्टार	75-80	9-12	1-3
2014 में सीटें	**47**	**15**	**28**

महाराष्ट्र (कुल सीटें 288)			
न्यूज चैनल्स/एजेंसियां	भाजपा+	कांग्रेस+	अन्य
टाइम्स नाउ	230	48	10
टीवी 9 भारतवर्ष-सीआइसीईआरओ	197	75	16
सीएनएन न्यूज 18-इप्सॉस	244	39	5
इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया	166-194	72-90	22-34
रिपब्लिक टीवी- जन की बात	216-230	59-50	12-8
एबीपी-सी वोटर	204	69	15
न्यूज एक्स-पोलस्टार	188-200	74-89	6-10
2014 में सीटें	**185**	**83**	**20**

भारत करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान से समझौता करने को तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कल दस्तखत के आसार, श्रद्धालुओं से 20 डॉलर शुल्क लेने पर अड़ा पाक
- भारत ने जताई निराशा, फिर किया शुल्क वापस लेने का अनुरोध
- हाल के वर्षों में पहली बार दोनों देशों के बीच होगा कोई समझौता

करतारपुर कॉरिडोर की सेवा गुरु नानकदेव के 550वें जन्मदिवस के ठीक पहले नौ नवंबर, 2019 से शुरू करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर, 2019 को एक समझौता होने जा रहा है। भारत ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति के बारे में पाकिस्तान सरकार को बता दिया है। हालांकि भारत ने इस बात पर निराशा जताई है कि उसके आग्रह के बावजूद पाकिस्तान सरकार हर तीर्थ यात्री से 20 डॉलर का सेवा शुल्क लेने पर अड़ी हुई है। भारत ने पाकिस्तान से इस शुल्क को वापस लेने का फिर आग्रह किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा और बुधवार को यह समझौता हो गया तो दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में किया गया यह पहला समझौता होगा। दोनों पड़ोसी देशों में पहले से ही कई मुद्दों पर तनाव व्याप्त है, लेकिन जब से भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है तब से हालात काफी बिगड़े हुए हैं।

विदेश मंत्रालय की तरफ से सूचना दी गई है, 'भारत ने पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब में भारतीय और भारतीय मूल के नागरिकों (आइओसी) की यात्रा में सहूलियत के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर में अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया है। लेकिन यह बेहद निराशा की बात है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ तीर्थयात्रियों को सुविधा देने के लिए शेष सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी भी 20 डॉलर का सेवा शुल्क लेने पर अडिग है। हम पाकिस्तान से अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि तीर्थयात्रियों के हितों को देखते हुए इस तरह का शुल्क नहीं लेना चाहिए। तीर्थयात्रियों की बहुत पुरानी मांग है कि उन्हें करतारपुर बगैर किसी वीजा शुल्क के जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। भारत इस बारे में समझौते में संशोधन करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए 23 अक्टूबर को समझौता करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।'

कॉरिडोर से रोजाना 1.5 करोड़ रुपये कमाएगा पाक

नई दिल्ली : करतारपुर कॉरिडोर पर हर श्रद्धालु से 20 डॉलर का शुल्क आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत होगी। अनुमान है कि हर श्रद्धालु से 20 डॉलर की फीस से पाकिस्तानी खजाने में सालाना 561 करोड़ से अधिक का इजाफा होगा। दरअसल, पाक ने एक दिन में 5,000 श्रद्धालुओं के आने की अनुमति दी है। वहां एक डॉलर की कीमत 156 रुपये है। 20 डॉलर के हिसाब से उसे रोजाना 1.56 करोड़ रुपये (भारतीय मुद्रा में करीब 71 लाख रुपये) की कमाई होगी। (पेज-6)

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ चार किलोमीटर दूर स्थित डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा है। यहां जाने के लिए कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने अपनी सीमा के पास यात्रियों की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे वाली ढांचागत व्यवस्था तैयार की है। फिलहाल पाक रोजाना सिर्फ 5,000 यात्रियों को इजाजत दे रहा है। बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है।

सनद रहे कि कारगिल युद्ध से ठीक पहले भारत-पाक के बीच लाहौर-दिल्ली बेस सेवा, उसके बाद मुनाबाव-खोखरापार रेल लिंक और श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा के लिए समझौता हुआ था। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने एकतरफा फैसला करते हुए दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस) को रद कर दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया, हिंदू पक्ष को दे दिया वैकल्पिक राहत का नोट

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक राहत का जो नोट उन्होंने सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंपा था उसे हिंदू पक्ष को भी दे दिया गया है। शीर्ष अदालत ने इस जानकारी को अपने रिकॉर्ड पर ले लिया। बाद में मुस्लिम पक्ष ने अपने इस नोट को सार्वजनिक कर दिया। सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता एजाज मकबूल ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि छह मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट में सील बंद लिफाफे में दिए गए नोट पर दूसरे (हिंदू) पक्ष की ओर से एतराज जताया गया था जिस पर उन लोगों ने रविवार को दूसरे पक्ष को भी उसकी प्रति दे दी है। (पेज-5)

हटाए गए स्थान पर ही बनेगा रविदास मंदिर

- सुप्रीम कोर्ट ने माना केंद्र का प्रस्ताव, 400 वर्गमीटर जमीन देगी सरकार
- छह हफ्ते में निर्माण निगरानी समिति गठित करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण का केंद्र सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंदिर का पुनर्निर्माण तुगलकाबाद वन क्षेत्र की उसी संरक्षित जमीन पर होगा जहां उसे अगस्त में शीर्ष अदालत के आदेश पर हटा दिया गया था।

जस्टिस अरुण मिश्रा और एस. रविंद्र भट की पीठ ने रविदास मंदिर के लिए आवंटित की जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार 400 वर्गमीटर जमीन आवंटित करने को तैयार है। केंद्र सरकार ने श्रद्धालुओं और सरकारी अधिकारियों समेत सभी संबंधित पक्षों से वार्ता के बाद संवेदनशीलता व आस्था के मद्देनजर जमीन देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के भीतर मंदिर के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए समिति का गठन करे। शांति बनाए रखने की अपील करते हुए शीर्ष अदालत ने उन सभी लोगों को पर्सनल बांड पर रिहा करने का आदेश भी दिया जिन्हें

मंदिर पुनर्निर्माण की मांग के समर्थन में किए गए प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि मंदिर और आसपास कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि नहीं होगी, इसमें पेड (शुल्क वाली) पार्किंग भी शामिल है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 10 अगस्त को रविदास मंदिर हटा दिया था। इसका काफी विरोध हुआ था। चूंकि संत रविदास के भजनों का गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णन है, इसलिए सिखों में भी आक्रोश था। लिहाजा चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों (मंदिर पुनर्निर्माण की मांग करने वाले) को अटॉर्नी जनरल से वार्ता करके कोई सर्वसम्मत समाधान लेकर आने के लिए कहा था।

रविदास मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप ने किया स्वागत पेज>>2

'जमीन संत रविदास समिति को ट्रांसफर होने तक जारी रहेगी लड़ाई'

नई दिल्ली, एएनआइ : रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कहा, 'हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक सिकंदर लोधी की जमीन पूरी तरह संत रविदास समिति को न दे दी जाएगी।' याचिकाकर्ताओं में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी शामिल हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक राजेश लिलोथिया ने डीडीए के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।

दिग्गज आइटी कंपनी इन्फोसिस के शीर्ष अधिकारी आरोपों के घेरे में

- कंपनी के सीईओ और सीएफओ पर अनुचित कारोबारी गतिविधियों का लगा आरोप
- व्हिसलब्लोअर की शिकायत पर कंपनी ने कहा कि मामला ऑडिट बोर्ड को सौंपा गया

बेंगलुरु, आइएएनएस : देश की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी इन्फोसिस के कुछ अज्ञात कर्मचारियों (व्हिसलब्लोअर्स) ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। इस शिकायत में कंपनी के सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ निलंजन रॉय पर व्यापार में मुनाफा दिखाने के लिए अनुचित तरीके अपनाने की बात कही है। कंपनी ने इसके जवाब में कहा है कि व्हिसलब्लोअर की शिकायत को नियमों के मुताबिक ऑडिट कमेटी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। वहां व्हिसिलब्लोअर नियमों के मुताबिक इसका समाधान किया जाएगा।

स्वयं को एथिकल एंप्लॉई कहने वाले इन कर्मचारियों ने कंपनी के बोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि आरोपितों के ई-मेल और वॉइस रिकॉर्डिंग से साफ होता है कि ये कई तिमाहियों से अनुचित कारोबारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। कंपनी बोर्ड को यह पत्र 20 सितंबर को लिखा गया था। बोर्ड की ओर से पत्र का जवाब नहीं मिलने पर इन कर्मचारियों ने तीन अक्टूबर को अमेरिका स्थित ऑफिस ऑफ द व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को इस मामले से अवगत कराया था।

सीईओ-सीएफओ ने ऐसा कहा था... : व्हिसलब्लोअर्स के मुताबिक सीईओ और सीएफओ ने कहा कि बोर्ड के सदस्य तकनीकी बातों को नहीं समझते। जब तक शेयर की कीमत ऊपर रहेगी, वे खुश रहेंगे। वे लोग बेकार के तर्क रखेंगे, इसके लिए आप सिर्फ सिर हिलाते रहिए बाकी सब नजरंदाज कर दीजिए।

ये हैं आरोप

- जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान अधिक मुनाफा दिखाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स से वीजा लागतों को कम करने के लिए कहा गया
- 353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को भी नजरंदाज करने के लिए दबाव डाले जाने की बात कही गई है
- अफसरों ने मुनाफा बढ़ाकर स्टॉक्स की ऊंची कीमत बनाए रखने के लिए गैरकानूनी कदम उठाए
- वेरिजॉन, इंटेल और संयुक्त उपक्रमों में हेराफेरी की गई, ऑडिटर्स व कंपनी बोर्ड से जानकारियां छिपाई गईं
- पारेख ने कर्मियों से कहा था, बोर्ड के सामने बड़ी डील के आंकड़े व महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां नहीं रखी जाएं

सुधरे पाक वरना गुलाम कश्मीर में घुसकर मारेंगे : मलिक

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाक को आतंकी शिविरों आतंकवाद को बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वह (पाक) बाज नहीं आया तो हम गुलाम कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे। उन्होंने कश्मीरी युवाओं से बंदूक और बर्बादी का रास्ता छोड़ कर सूबे की बेहतरी के लिए काम करने को प्रेरित करते हुए कहा, क एक नवंबर से नया कश्मीर होगा। (पेज-6)

विमानन को टैक्स के बोझ से मुक्ति दे सरकार : स्पाइसजेट

वाशिंगटन : देश की अग्रणी निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने कहा है कि भारत नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा बाजार बनकर उभरा है। यह सही समय है जब सरकार को इस सेक्टर में टैक्स दरें घटाने सहित दूसरे सुधार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में सिविल एविएशन सेक्टर में टैक्स दरें बहुत अधिक हैं, जिससे यह ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पर रहा है। (पेज-12)

नई तकनीक

आइआरडीई ने बनाया लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, मिसाइल को नहीं छका पाएंगे दुश्मन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के बाद इस तकनीक को हासिल करने वाला भारत चौथा देश, टी-90 टैंक को और अचूक बनाएगी उन्नत ड्राइवर और कमांडर साइट

सेकंड के 1000वें भाग में शूट होगा दुश्मन का लड़ाकू विमान

सुमन सेमवाल, देहरादून

अगस्त में जिस क्यूआरसैम मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया था, अब उसका निशाना अचूक बनाने की तैयारी भी कर ली गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के देहरादून स्थित यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आइआरडीई) ने इस मिसाइल के लिए लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज तैयार किया है। जल्द इसे मिसाइल में फिट कर दिया जाएगा। आइआरडीई में ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स विषय पर चल रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में रक्षा विशेषज्ञों के समक्ष महज 2.7 किलोग्राम के इस फ्यूज का प्रदर्शन किया गया।

आइआरडीई के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. पुनीत वशिष्ठ ने बताया कि अभी देश की मिसाइलों में दुश्मन के लड़ाकू और टोही विमान को पकड़ने के लिए रेडियो तरंगों वाले फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। कई दफा ये तरंगें अलग-अलग दिशा से आने वाले एयरक्राफ्ट को पकड़ने में असफल रहती हैं। इसी के मद्देनजर लेजर तरंग आधारित फ्यूज बनाने की दिशा में काम शुरू किया गया। दो साल के गहन

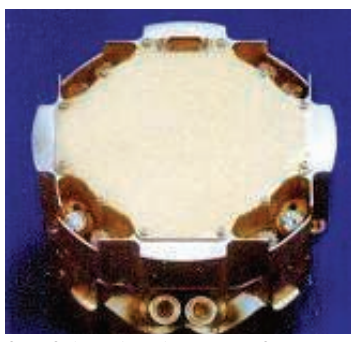

डीआरडीओ द्वारा तैयार लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज।

अनुसंधान के बाद अब इस फ्यूज को तैयार कर लिया गया है। जल्द कुछ और ट्रायल के बाद इसका उपयोग किया जा सकेगा।

इस तरह मिसाइल का टारगेट बनेगा अचूक : पुनीत वशिष्ठ के अनुसार, मिसाइल में फिट होने के बाद लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से 5000 पल्स प्रति सेकंड की दर से तरंगें निकलेंगी, जो मिसाइल छोड़ने पर टारगेट किए गए एयरक्राफ्ट की निगरानी करने लगेंगी। तरंगें मिसाइल के भीतर लगे फ्यूज को यह संकेत भेजेंगी कि टारगेट कितनी दूरी पर है और उसकी रफ्तार कितनी है। इस सबका आकलन एक सेकंड के 1000वें हिस्से के भीतर कर लिया जाएगा। इसके लिए फ्यूज के भीतर फील्ड प्रोगामेबल गेट आर्रे चिप लगाई गई है। जैसे ही टारगेट 20 मीटर की परिधि में आ जाएगा, मिसाइल उसे ध्वस्त कर देगी। अभी मिसाइल की टारगेट क्षमता को अचूक बनाने की तकनीक सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और रूस तीन देशों के पास ही है।

आकाश मिसाइल के लिए सेना को दस हजार करोड़ देगा रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली : पाकिस्तान और चीन सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र से विमानों और टोही विमानों की घुसपैठ रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय आकाश मिसाइल के दो रेजिमेंट खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहा है। आकाश मिसाइलों को 15000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। इसे पाक और चीन सीमा से सटे लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। (पेज-3)

10 करोड़ के वेपन जांच सिस्टम को एक करोड़ में बनाया : रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी में आइआरडीई ने टी-90 टैंक के वेपन की जांच के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित सिमुलेटेड टेस्ट एंड इंटेरोगेटर किट तैयार की है। अब तक टी-90 टैंक के वेपन सिस्टम व अन्य तरह के फॉल्ट की जांच के लिए जो सिस्टम जोड़ा जाता है, उसकी लागत 10 करोड़ रुपये आती है। नए सिस्टम की लागत महज एक करोड़ रुपये आ रही है।

अंधेरे में और साफ देखेगा टी-90 टैंक : अब टी-90 टैंक की नजर अंधेरे में भी दुश्मन को पकड़ लेगी। आइआरडीई ने टैंक की उन्नत किस्म की ड्राइवर और कमांडर साइट तैयार की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और देहरादून स्थित ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को 3700 यूनिट तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। अब तक की साइट चांदनी रात में तो बेहतर काम करती थी, लेकिन धुंध व अंधेरी रात में इसका प्रदर्शन कमजोर हो जाता था। नई तकनीक के जरिए कमांडर साइट से पांच किमी तक की दूरी पर बैठे दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। वहीं, ड्राइवर साइट पर 200 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देखा जा सकेगा।

जल्द तय होंगे पुलिस के काम के घंटे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 90 फीसद पुलिसकर्मी करते हैं प्रतिदिन 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी : शाह
- पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के बलिदान को किया याद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिसकर्मियों को चरणबद्ध रूप से कामकाज का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का भरोसा देते हुए कहा है कि जल्द ही उनके (पुलिसकर्मियों) काम के घंटे तय होंगे। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिले।

अमित शाह सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस पर अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कामकाज के मौजूदा अत्यधिक बोझ को कम करने की जरूरत बताते हुए कहा, भारत के महाशक्ति बनने के मुकाम तक पहुंचाने में पुलिसकर्मियों का अहम योगदान है। शाह ने कहा, मौजूदा समय में एक लाख की जनसंख्या पर 144 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, जबकि इनकी संख्या 222 होनी चाहिए। यही कारण है कि 90 फीसद पुलिसकर्मियों को रोजाना 12 घंटे से भी अधिक समय तक काम करना पड़ रहा है। दो-तिहाई से अधिक पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जिन्हें साप्ताहिक अवकाश तक मयस्सर नहीं हो रहा है। सरकार पुलिसकर्मियों की इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास कर रही है।

आंतरिक सुरक्षा में पुलिसकर्मियों के योगदान को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा, आजादी के बाद से अभी तक 35 हजार से अधिक पुलिसकर्मी शहादत दे चुके हैं। सामान्य तौर पर पुलिस का काम अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह दिखता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा हो या सड़क पर ट्रैफिक नियम का पालन कराना, ड्रग्स व हवाला कारोबार से देश के अर्थतंत्र को खत्म करने वाले और देश की नई पीढ़ी को खोखला करने वालों के खिलाफ लड़ाई हो, सारी जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों के कंधों पर ही होती है। यही नहीं, देश में सांप्रदायिक दंगों को रोकने, पूर्वोत्तर के उग्रवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास सुनिश्चित करने में भी पुलिस और अर्धसैनिक बल अहम भूमिका निभा रहे हैं।

30 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा वार्षिक दीक्षा समारोह। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस अवसर पर मणिपुर की राज्यपाल और जामिया की चांसलर डा. नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद रहेंगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 22 अक्टूबर 2019

पूरी दिल्ली परिवार की तरह दिवाली मनाएगी : केजरीवाल

बड़ा कदम ▸ पराली से हो रहे प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया निर्णय, कनॉट प्लेस में 26 से 29 तक होगा मेगा लेजर शो

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन, सीएम परिवार के साथ होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस साल कनॉट प्लेस में सभी दिल्लीवासियों के साथ सामूहिक रूप से दिवाली मनाने की घोषणा की है। इसके लिए दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस में मेगा लेजर शो का आयोजन करेगी। इस बात की जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उपस्थित थे।

केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से हो रहे प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पहली बार चार दिन का लेजर शो करने का निर्णय लिया है। मेगा लेजर शो का आयोजन कनॉट प्लेस में 26 से 29 अक्टूबर तक होगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी कि इस बार हम सारी दिल्ली के लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलकर एक साथ कनॉट प्लेस में प्रदूषणरहित दिवाली मनाएंगे। सामूहिक रूप से दिवाली मनाने से त्योहार का

दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। संजय

आनंद बढ़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं आ रहा है इसलिए शहर को आंतरिक प्रदूषण को कम रखने के लिए हरसंभव कोशिश करनी होगी। इसमें जनता का सहयोग जरूरी है। दिल्ली के सभी लोग इन चार दिनों तक हर शाम छह से 10 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। फूड कोर्ट में लोग लजीज भोजन का आनंद उठा सकेंगे। कार्यक्रम में सीएम अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे।

प्रवेश के लिए पास की जरूरत नहीं : इस आयोजन में पास या टिकट की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की पहली सामूहिक दिवाली सभी के लिए है। दिवाली हम सभी का त्योहार है। किसी को भी किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के सभी लोग आएं और मेरे साथ दिवाली मनाएं।

26 अक्टूबर को उपराज्यपाल करेंगे लेजर शो का उद्घाटन : छोटी दिवाली के दिन 26 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में लेजर शो का उद्घाटन उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस साल एक जगह ही लेजर शो का आयोजन हो रहा है। इसके बेहतर परिणाम आने के बाद अगले साल से दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी आयोजन होगा।

सीपी में व्यापार घटेगा नहीं, बढ़ेगा : लेजर शो के आयोजन से व्यापारियों के व्यापार पर असर पर जब प्रश्न किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लेजर शो का आनंद लेने पूरी दिल्ली कनॉट प्लेस आ रही है। इससे उस दौरान कनॉट प्लेस में व्यापार घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। वहां के व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा।

चार दिन तक इनर सर्कल में वाहन रहेंगे प्रतिबंधित : दिल्ली सरकार के दिवाली समारोह के कारण 26 से 29 अक्टूबर तक कनॉट प्लेस (सीपी) के इनर सर्कल में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। उन्होंने कहा कि लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवाजी पार्क व अन्य जगहों पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां से लोगों को ले जाने के लिए सरकार की तरफ से आंतरिक परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। सिसोदिया ने कहा कि जो मजा पटाखा जलाकर दिवाली मनाने में आता है, उससे ज्यादा आनंद लेजर शो देखने में आएगा। दिवाली पर जलाने वाले पटाखों से प्रदूषण होता है। हर साल दिवाली के बाद खबर आती है कि इतने का पटाखा जला। इतना प्रदूषण बढ़ गया। अब ऐसा न हो इसके लिए लेजर शो का आनंद लें। मैं पिछली बार सिग्नेचर ब्रिज गया था। मैंने देखा कि लोग दिवाली में पूजा करने के बाद वहां आए थे। इस बार कनॉट प्लेस आएं और साथ में दिवाली मनाएं।

कनॉट प्लेस की जगह सरकार कहीं और मना ले दिवाली : एनडीटीए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कनॉट प्लेस में दीपावली मनाने के दिल्ली सरकार के निर्णय का यहां के दुकानदारों ने विरोध किया है। कारोबारियों के संगठन नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने कहा कि इस आयोजन से कनॉट प्लेस के कारोबारियों का कारोबार प्रभावित होगा। इसके चलते जाम और वायु प्रदूषण की समस्या भी बढ़ेगी। एनडीटीए ने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) व जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। उसने सरकार से आग्रह किया है कि वह यह आयोजन कहीं और कर ले। दिल्ली में कई उपयुक्त स्थान हैं। एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने सोमवार को बैठक भी की। एनडीटीए के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि सरकार ने कनॉट प्लेस के कारोबारियों से राय भी नहीं ली। कारोबारियों को इस आयोजन से दिक्कत नहीं है, लेकिन यह कहीं और होना चाहिए। इंडिया गेट, लाल किला, रामलीला मैदान, बुद्धा गार्डन जैसे स्थलों के साथ दिल्ली में कई सारे स्टेडियम भी हैं, जहां इसका आयोजन भव्य तरीके से किया जा सकता है। भार्गव ने कहार कि दीपावली से दुकानदारों को काफी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि इन दिनों काफी संख्या में खरीदार आते हैं। इस कारण वाहनों और लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। उसमें इस तरह के आयोजन से कारोबार काफी प्रभावित होगा।

पांच साल में इस बार डेंगू का प्रकोप सबसे कम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू किए जागरूकता अभियान में लोगों द्वारा दिए गए योगदान की तारीफ की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले पांच साल में इस बार डेंगू के अब तक सबसे कम मामले सामने आए हैं क्योंकि दिल्ली के लोग इस बार डेंगू को परास्त करने की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से 15 नवंबर तक सतर्क रहने की अपील की है क्योंकि यह देखा गया है कि नवंबर के मध्य तक डेंगू का प्रकोप अधिक रहता है। इसके बाद मौसम में ठंड बढ़ने के साथ डेंगू का प्रकोप खत्म हो जाता है।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 644 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले साल 1020 मामले सामने आए थे और चार लोगों की मौत हुई थी। इस साल डेंगू से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2015 में यहां डेंगू से 60 मरीजों की मौत हुई थी। डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के समक्ष इस बार डेंगू का प्रकोप अधिक होने की आशंका जाहिर की थी। लेकिन सभी आशंकाओं के बावजूद इस बार दिल्ली में डेंगू नियंत्रित है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए '10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट' अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक रविवार को लोगों को अपने घर में सफाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

न्यूज गैलरी

सीबीएसई पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगी बोर्ड परीक्षा

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड के सभी छात्रों को परीक्षा के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम से तैयारी करने की बात कही है। बोर्ड के छात्र हर बार एनसीईआरटी की किताबों से ही परीक्षा की तैयारी करते आए हैं। लेकिन सीबीएसई ने अब छात्रों को केवल अपने शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम से ही पढ़ने को कहा है न कि एनसीईआरटी की किताबों से। सीबीएसई हमेशा परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की किताबों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित करता है। लेकिन बोर्ड ने देखा कि किताबों में कहीं-कहीं पर लिखा है कि यह जानकारी परीक्षा या मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं है। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि एनसीईआरटी पुस्तकों में लिखी गई यह जानकारी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू नहीं है। छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से तैयारी करने की सलाह दी गई है। (जासं)

छात्रों के लिए खुला रहेगा जेएनयू की पार्थसारथी चट्टान का रास्ता

नई दिल्ली : जेएनयू प्रशासन ने अफवाहों को दूर करते हुए कहा कि छात्रों के लिए परिसर की मुख्य घूमने वाली जगहों में से एक पार्थसारथी चट्टान का रास्ता खुला रहेगा। प्रशासन ने वहां प्रवेश के लिए समय निर्धारण किया है। छात्रों को वहां जाने के लिए आइकार्ड दिखाना होगा। ऐसा सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। जेएनयू प्रशासन ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पार्थसारथी चट्टान के पास मरम्मत का काम चल रहा है इसलिए रास्ता बंद किया गया है। कुछ लोगों ने शनिवार देर रात ताला तोड़कर गेट उखाड़ दिया था, जा कि अपराध है। उन लोगों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। पार्थसारथी चट्टान की ओर जाने का रास्ता सुबह साढ़े पांच बजे से शाम साढ़े सात बजे तक खुला रहेगा। (जासं)

एशिया बुक ऑफ में रिकार्ड में दर्ज हुआ वेस्ट से बना चरखा

नोएडा : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शहर में प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया चरखा एशिया बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज कराने में सफल हो गया है। मंगलवार को एशिया बुक ऑफ रिकार्ड की टीम नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी को रिकार्ड से संबंधित प्रमाणपत्र, पैन व बैच सौंपेगी। इसके बाद अब गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज होने की संभावना है। टीम 25 अक्टूबर को चरखा देखने के लिए नोएडा आ सकती है। इससे पहले चरखे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। इस चरखे को बनाने में 1250 किलोग्राम प्लास्टिक की जरूरत पड़ी थी। (जासं)

सुसाइड नोट में मां-बेटे ने 11 लोगों को जिम्मेदार ठहराया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ प्रोफेसर और उनकी मां की मौत के मामले में केरल जाएगी पुलिस

सेंट स्टीफंस के प्रोफेसर एलन और उनकी मां लिसी की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस जल्द ही केरल के लिए रवाना होगी। दरअसल मां-बेटे ने सुसाइड नोट में लिसी के दूसरे पति के परिजनों सहित कुल 11 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इसमें दूसरे पति की मौत के मामले की जांच कर रही अधिकारी भी शामिल हैं। ये सभी लोग केरल के ही रहने वाले हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुसाइड नोट में प्रोफेसर व उनकी मां ने दूसरे पति की मौत के मामले की जांच कर रहे एसएचओ एवं एसआइ के अलावा लिसी के सौतेले बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ये लोग लगातार दोनों को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब पुलिस टीम को केरल रवाना किया जाएगा ताकि सुसाइड नोट के तथ्यों की जांच की जा सके और उनमें नामजद लोगों से पूछताछ की जा सके। वहीं सोमवार को पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

प्रोफेसर की मां लिसी के दूसरे पति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केरल में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों ने कोर्ट से जमानत ले रखी थी। बताया जाता है कि मामला दर्ज होने के बाद दोनों बेहद तनाव में चल रहे थे। इसे ही दोनों की मौत की वजह मानी जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच के लिए एलन के लैपटॉप व कुछ डायरी कब्जे में ली हैं। इसके आधार पर पुलिस जांच की दिशा को आगे बढ़ाने में लगी है। लिसी का पंखे से लटका हुआ शव पीतमपुरा स्थित आशियान अपार्टमेंट के उनके फ्लैट में शनिवार को मिला था, जबकि एलन का शव उसी दिन सराय रोहिल्ला स्टेशन के निकट रेलवे लाइन पर मिला था। लिसी के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। ऐसे में उनकी मौत को लेकर रानी बाग थाने में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि मां की हत्या के बाद एलन ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकशी की है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिल्ली सरकार ने की लागू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली के नौ हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत पात्र किसान को हर साल छह हजार रुपये मिलेंगे। दिल्ली के किसानों को यह राशि पहली बार मिलने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने नियम व शर्तों के आधार पर सूची तैयार कर केंद्र सरकार के पास भेज दी है।

इस योजना के तहत संपूर्ण राशि केंद्र से आनी है, जो किसानों के खाते में जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना को लागू करने की कुछ माह पहले ही मंत्री गोपाल राय ने अनुमति दे दी थी। इसके बाद से दिल्ली के किसानों से इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन मांगे गए थे। दिल्ली में 20 हजार किसान हैं, लेकिन योजना की शर्तों के चलते इसमें दिल्ली के नौ हजार किसान ही शामिल हो पाए हैं। योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या जो आयकर के दायरे में आते हैं।

भूमि अधिग्रहण मामले में लागू रहेगा यथास्थिति का आदेश : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ नोएडा के बदौली बांगर गांव में 2013 में किया था किसानों की जमीन का अधिग्रहण

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बदौली बांगर गांव मे 2013 में हुए अधिग्रहण के मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिग्रहण रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नोएडा अथारिटी की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है। बदौली बांगर गांव का यह क्षेत्र नोएडा सेक्टर-146, 147 और 157 में आता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पांच जनवरी 2017 को अधिग्रहण रद कर दिया था। इसके खिलाफ नोएडा अथारिटी ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील दाखिल की। हाई कोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण कानून की धारा-छह मे जारी नोटिस रद किया था और धारा-चार का नोटिस बहाल रखा था, जबकि कुछ मामलों में धारा-चार और छह दोनों के तहत जारी नोटिस रद कर दिया था। अथारिटी ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है। पिछली सुनवाई 13 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों को मामले मे यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए अथारिटी से कहा था कि वह सभी मामलों के बारे मे अलग-अलग मुकदमा सार दाखिल करे ताकि कोर्ट मामले पर विस्तृत सुनवाई कर सके।

गत 15 अक्टूबर को जब मामला सुनवाई पर आया तो अथारिटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग पक्षकारों के बारे मे मुकदमा सार दाखिल नहीं किया है, बल्कि एक मुख्य मामले मे ही सबका ब्योरा दे दिया है। इस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सभी मामलों में अलग-अलग सार दाखिल करने का आदेश दिया। तभी भू स्वामी किसानों के वकील डाक्टर राजीव शर्मा ने कोर्ट से कहा कि अदालत के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद अथारिटी वहां की जमीन आवंटित कर रही है। उन्होंने अथारिटी द्वारा वहां कब्जा किए जाने आदि का आरोप लगाते हुए कोर्ट मे कुछ फोटो भी दिखाए। इस पर सुनवाई कर रही पीठ के न्यायाधीश संजय किशन कौल और केएम जोसेफ ने कहा कि वह फोटुओं के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी को शिकायत है तो वह अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथारिटी को सभी मामलों में अलग मुकदमा सार दाखिल करने का समय देते हुए याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली। साथ ही कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश स्थाई कर दिया यानी जब तक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता यथास्थिति कायम रहेगी।

यह मामला 2013 के अधिग्रहण का है। इसमें भूस्वामी किसानों को जुलाई 2016 मे अवार्ड दे दिया गया था, लेकिन किसानों ने अधिग्रहण के खिलाफ सुनवाई का मौका नहीं दिए जाने के आधार पर अधिग्रहण को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने पांच जनवरी 2017 को किसानों की याचिका स्वीकार करते हुए अधिग्रहण रद कर दिया था। यह मामला कुल 81.8193 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का है।

हवा रही खराब, आज हो सकती है बहुत खराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच पराली का धुआं भी तेजी से दिल्ली पहुंच रहा है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने से इसकी मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि सोमवार को प्रदूषण का स्तर जहां खराब श्रेणी में था, वहीं मंगलवार को यह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 249 रहा। गाजियाबाद का 284, ग्रेटर नोएडा का 243, गुरुग्राम का 201 और नोएडा का 260 दर्ज किया गया। इस श्रेणी की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। सफर के मुताबिक सोमवार को पराली का प्रदूषण दिल्ली में 12 फीसद रहा, जबकि मंगलवार को यह बढ़कर 14 फीसद हो जाएगा। सफर के अनुसार अब हवा उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है। इससे पराली का धुआं भी दिल्ली-एनसीआर को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। मंगलवार से हवा और ज्यादा खराब हो सकती है। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर इंडिया के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और सीमावर्ती हिस्सों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। इसके धुएं का व्यापक प्रभाव दिल्ली की हवा में दिखने लगा है। नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली का दम घुट सकता है।

दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से दिल्ली में तेज हवा चलेगी। इसकी वजह से कुछ समय के लिए लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिल सकती हैं। माह के अंत तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इस दौरान हवा की गति काफी कम हो जाएगी लिहाजा नवंबर में आसार अच्छे नहीं हैं। उधर, सोमवार को सुबह ही धूप निकल आई थी, लेकिन तापमान में कमी और हल्की धुंध के चलते इसकी चमक कम रही। अधिकतम तापमान 31.8, जबकि न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। दोनों ही सामान्य से एक डिग्री कम हैं।

एप से रखी जाएगी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर अब मोबाइल एप की भी नजर रहेगी। इस खास एप को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने तैयार करवाया है। इसकी मदद से संबंधित अधिकारी औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के समय लाइव वीडियो के जरिये उच्चाधिकारियों से जुड़े रहेंगे। सीपीसीबी के अनुसार इस एप का मकसद फॉलोअप निरीक्षणों में कमी लाना हैं। अभी छोटी सी भी कमी मिलने के बाद होने वाले फॉलोअप निरीक्षण की संख्या काफी अधिक है। अब इस एप के जरिये संबंधित औद्योगिक इकाइयों का ई इंस्पेक्शन संभव हो सकेगा। इस एप को सीपीसीबी की आइटी शाखा ने विकसित किया है। एप में रिमोट के जरिये लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो की सुविधा का लाभ लेते हुए निरीक्षण संभव हो सकेगा। हालांकि इस एप का इस्तेमाल अन्य प्रकार की जांच जैसे उद्योगों के कचरे और धूल आदि में भी हो सकेगा।

प्रदूषण के खिलाफ नगर निगमों ने किए 3240 चालान

जासं, नई दिल्ली : वायु प्रदूषण को लेकर निगम सख्त दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि रोज दिल्ली में करीब 500-600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निगमों का उद्देश्य धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकना है इसलिए विशेष रूप से निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण किया जा रहा है और उनका चालान किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से लेकर अब तक दिल्ली के तीनों नगर निगम ने 3200 से अधिक लोगों कि खिलाफ चालान किया गया है। कार्रवाई करने में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सबसे आगे है। 3240 में से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अब तक 2064 लोगों पर कार्रवाई की है। दक्षिणी निगम ने प्रगति मैदान में चल रहे निर्माण कार्य की कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के विभागों पर भी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर मलबा होने पर भी चालान काटा गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 1019 लोगों पर कार्रवाई की है। इन पर भी निगम ने भारी जुर्माना लगाया है। निगम ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों से मलबा उठाने की एवज में शुल्क भी वसूल किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण खत्म करेगा 1688 डंपिंग ग्राउंड

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

लैंडफिल साइट्स का समाधान भले न निकल पा रहा हो, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही दिल्ली के 16 सौ से अधिक डंपिंग ग्राउंड अवश्य खत्म करने जा रहा है। अब यहां कचरा नहीं डाला जा सकेगा। डीडीए ने यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध भी कर दिए हैं। इस दिशा में सारा प्लान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डीडीए का यह प्लान एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। पिछले साल सर्दियों में ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा था कि दिल्ली में पराली से कहीं अधिक प्रदूषण खुले में कचरा, रबड़ और प्लास्टिक जलाने की वजह से फैलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्लास्टिक, जूते के सोल, तारें सभी कुछ जलाया जा रहा है। इसके बाद सीपीसीबी ने सभी सरकारी विभागों से उनकी खाली जगहों की सूची मांगी थी, जिससे इन स्थानों पर खुले में कचरा जलाने की घटनाओं को रोका जा सके।

इसके बाद डीडीए ने पिछले दिनों ईपीसीए और सीपीसीबी को अपने 1688 खाली प्लॉटों की सूची सौंप दी थी। इस पर सीपीसीबी ने इन प्लॉटों पर उचित निगरानी के डीडीए को निर्देश दिए थे। इसके लिए यहां सुरक्षा गार्ड तैनात करने, सीसीटीवी लगाने या फिर प्लॉटों को ऊंची चारदीवारी से कवर करवाने के लिए कहा था, जिससे यहां कूड़ा डंप न किया जा सके।

उक्त निर्देशों की अनुपालना में डीडीए ने इन सभी खाली प्लॉटों, जिन्हें लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। उनकी निगरानी के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। छोटे प्लॉट के लिए एक जबकि बड़े प्लॉट के लिए दो गार्ड तैनात किए गए हैं। सभी गार्ड निजी सुरक्षा एजेंसियों से लिए गए हैं। इसके अलावा खाली प्लॉटों की चारदीवारी भी कराई जा रही है। जिन प्लॉटों में कचरा पड़ा है, वह भी इसी सप्ताह साफ करा दिया जाएगा।

खुले में कचरा जलाने की सबसे अधिक शिकायतें उत्तरी जोन, पूर्वी जोन, द्वारका और रोहिणी क्षेत्रों के अलावा नरेला, बवाना आदि से आती रही हैं। ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल के अनुसार यदि धूल और खुले में कचरा जलाने की घटनाओं को नियंत्रित कर लिया जाए तो दिल्ली- एनसीआर के वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

> ईपीसीए और सीपीसीबी के निर्देशों की अनुपालना में खाली प्लॉटों को डंपिंग ग्राउंड बनने से रोकने के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। अब डीडीए के किसी भी खाली प्लॉट पर कचरा जलाना तो बहुत दूर की बात, कचरा डालना भी संभव नहीं हो सकेगा।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

अपराधों की भी राजधानी है दिल्ली

जांस, नई दिल्ली : दिल्ली अपराध के जघन्य मामलों में देश के कई शहरों की तुलना में अव्वल बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2017 के आकड़ों के मुताबिक राजधानी में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हत्या, लूटपाट व डकैती जैसी वारदात ज्यादा हुई। वहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं की संख्या भी काफी रही। उस दौरान दिल्ली में रोड रेज और गैंगवार के ज्यादा मामले भी सामने आए। एनसीआरबी ने 2017 के आंकड़े सोमवार रात जारी किए। इसके मुताबिक इस वर्ष देशभर में सबसे ज्यादा 310084 अपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 288879, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में 269512, चौथे स्थान पर केरल में 235846 और पांचवें स्थान पर दिल्ली में 232066 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। इस दौरान हत्या के सर्वाधिक 25 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए।

डकैती और लूटपाट के मामले भी सबसे अधिक 16 दिल्ली में सामने आए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध सबसे अधिक पटना में 25 दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर दिल्ली में 14 मामले दर्ज किए गए। अवैध संबंध में होने वाली घटनाएं भी सबसे अधिक राजधानी में रिपोर्ट की गईं। यहां 29 मामले दर्ज किए गए। 14 मामलों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के मामले में ओडिशा 5220 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली में 1124 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर है।

पड़ेगी मार

डीएमआरसी की कैब योजना से यात्रियों की ढीली होगी जेब

गंतव्य तक जाने के लिए किराये पर कैब उपलब्ध कराने की है योजना, मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो व ग्रामीण सेवा की आवाजाही कम की जाएगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मेट्रो किराया दोगुना होने से यात्री पहले से ही परेशान हैं। अब उन्हें मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद घर व दफ्तर पहुंचने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। ई-रिक्शा व इलेक्ट्रिकल मेट्रो फीडर बस जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की किफायती सुविधाएं तो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन मेट्रो स्टेशनों से गंतव्य तक जाने के लिए किराये पर कैब उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए डीएमआरसी ने कैब संचालक कंपनी से करार किया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की यह योजना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकती है।

लोगों को प्रतिदिन भारी भरकम रकम मेट्रो व कैब के किराये पर खर्च करनी पड़ सकती है। जिन इलाकों में मेट्रो की सुविधा एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, वहां के यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा समय में डीएमआरसी सिर्फ 174 मेट्रो फीडर बसों का परिचालन कर रहा है। इन मेट्रो फीडर बसों का किराया पांच-दस रुपये है। फीडर बसों की संख्या कम होने की वजह से डीएमआरसी ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उबर कैब से करार किया है, जिसे 210 स्टेशनों पर जगह उपलब्ध कराई गई है। इन स्टेशनों पर कैब संचालक कंपनी करीब 400 जगहों पर अपना कियोस्क लगाएगी। वहां यात्री कैब बुक करा सकेंगे। डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों पर कैब की पार्किंग के लिए जगह भी उपलब्ध कराएगा। हालांकि कैब की सुविधा लेना या न लेना यात्रियों की इच्छा पर है, लेकिन इस योजना का एक मकसद यह भी है कि मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो व ग्रामीण सेवा की आवाजाही कम की जाए।

मेट्रो फीडर बसें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, ई-रिक्शा योजना भी परवान नहीं चढ़ीं ऐसे में यदि मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो व ग्रामीण सेवा को खड़ी होने की जगह उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो यात्रियों को मजबूरी में कैब का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में तीन से चार किलोमीटर के सफर के लिए भी यात्रियों को व्यस्त समय में 100-110 रुपया किराया कैब को भुगतान करना पड़ सकता है।

यह भी तब जबकि पहले हुए सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि मेट्रो में 15000 से 25,000 रुपये कमाने वाले लोग ही अधिक सफर करते हैं। दिल्ली व एनसीआर के शहरों के बीच आवागमन के लिए यात्री मेट्रो में एक तरफ से 60 रुपये व दोनों तरफ से 120 रुपये किराया भुगतान करने को मजबूर हैं। यदि मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद मजबूरी में कैब लेनी पड़ी तो यात्रियों का बजट बिगड़ना तय है।

लंबे समय से अधर में है फीडर बस खरीदने की योजना

डीएमआरसी ने 427 मेट्रो फीडर बस खरीदने की योजना बनाई है, जो करीब दो साल से अधर में लटकी पड़ी है। बजट के अभाव में एक बार टेंडर रद भी किया जा चुका है। अब डीएमआरसी ने नए सिरे से 100 इलेक्ट्रिकल फीडर बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है।

फाइल फोटो

यात्रियों को किराये में नहीं मिलेगी कोई छूट

डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो स्टेशनों पर एप आधारित कैब की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी किया गया था। इसके तहत तीन साल के लिए लीज पर कैब संचालक कंपनी को स्टेशनों पर जगह उपलब्ध कराई जा रही है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। हालांकि कियोस्क से कैब बुक करने पर मेट्रो के यात्रियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। मेट्रो के अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि इससे ऑटो वालों की मनमानी रुकेगी।

रविदास मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप ने किया स्वागत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर के लिए जमीन देने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में एससी व एसटी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह खुशी की बात है कि संत रविदास मंदिर को फिर से उसी स्थान पर 400 वर्गमीटर में बनाए जाने की शीर्ष अदालत ने अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दिल्ली की समस्त जनता के साथ ही देशभर में संत रविदास जी के 40 करोड़ अनुयायियों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने न सिर्फ इन लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया, बल्कि इन्हें गुमराह भी किया था।

पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेसवार्ता में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने जानबूझकर देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र संत रविदास जी के मंदिर को तुड़वाया था।

विहिप ने हिंदू समाज की जीत बताया : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इसे हिंदू समाज के संघर्ष की जीत बताया है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद अब न सिर्फ गुरु रविदास का मंदिर वहीं बनेगा बल्कि वहां के पवित्र सरोवर को भी पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ हो गया है। संतों की समाधियों की देखभाल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं मंदिर के लिए संघर्ष के दौरान जितने भी आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए थे, वे सब रिहा होंगे। उन पर मुकदमे भी वापस होंगे। विहिप कार्याध्यक्ष ने इसी वर्ष 4 जुलाई को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर मंदिर को बचाने की मांग की थी। न्यायालय के आदेश पर मंदिर को गिराए जाने से नाराज विहिप दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल और बाद में आलोक कुमार एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इसी माह हरदीप पुरी से मिले थे।

2016 में विश्वविद्यालयों,कॉलेजों व उनसे जुड़े संस्थानों के परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाने की शुरुआत हुई थी। यूजीसी ने परीक्षाओं में मोबाइल या इस तरह की डिवाइस के जरिये होने वाली नकल पर रोकथाम लगाने के लिए यह अनुमति दी थी।

न्यूज गैलरी

तेदेपा के नेता आदिनारायणन रेड्डी भाजपा में हुए शामिल

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (दायें) के साथ आदिनारायण रेड्डी। प्रेट्र

नई दिल्ली : एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) के नेता आदिनारायण रेड्डी सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में रेड्डी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रेड्डी ने अनुछेद-370 को खत्म करने और तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने पर पार्टी की प्रशंसा करते हुए कहा, कहा, 'मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी एक राष्ट्र, एक संविधान में विश्वास करती है। साथ ही पार्टी विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।' रेड्डी ने पिछले महीने तेदेपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वह तीन बार विधायक रहने के साथ ही प्रदेश की पिछली नायडू सरकार में मंत्री भी थे। बता दें कि इस साल अप्रैल में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में तेदेपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब से चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी के कई नेता पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। (एएनआइ)

जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति पर 25 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें जस्टिस अकील कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन उसके इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए इस मामले का उल्लेख किया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 मई के अपने प्रस्ताव में बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी को प्रोन्नत करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में अपने फैसले को संशोधित करते हुए उन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। (एएनआइ)

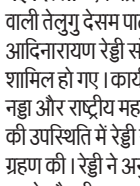

आकाश मिसाइल के लिए सेना को 10,000 करोड़ देगा रक्षा मंत्रालय

पाक, चीन सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र से विमानों की घुसपैठ रोकने के लिए तैनात की जाएगी मिसाइल

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तान और चीन सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र से विमानों की घुसपैठ रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय आकाश मिसाइल के दो रेजिमेंट खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहा है। आकाश मिसाइलों को 15000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। नई आकाश मिसाइल पूर्व की मिसाइल की तुलना में ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसे पाक और चीन सीमा से सटे लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है।

सरकारी सूत्रों ने बताया, 'रक्षा मंत्रालय आकाश प्राइम या बेहतर प्रदर्शन वाली आकाश मिसाइल की दो रेजिमेंट के लिए सेना के 10,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर विचार करने जा रहा है। आकाश प्राइम मिसाइल सेना में पहले से मौजूद मिसाइल प्रणाली का उन्नत रूप है।' सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख से लौटने के बाद सोमवार को होने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री लद्दाख में दुरबुक व दौलत बेग ओल्डिए के बीच बने कोल चेवांग रिनचेन पुल का उद्घाटन करने गए हैं। सेना के पास मिसाइल की दो रेजिमेंट पहले से ही है और वह दो और रेजिमेंट लेना चाहती है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति ने वायुसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है।

पीएम ने प्रायोगिक विमान बनाने वाले अन्वेषक से की भेंट

युवा अन्वेषक अमोल यादव ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से निर्मित छोटे विमान उड़ाने के प्रोजेक्ट की राह की नियामक अड़चनों को दूर करने में जुट गए हैं। यह जानकारी सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। रविवार को प्रधानमंत्री ने युवा अन्वेषक अमोल यादव से मुलाकात की। पेशे से पायलट यादव ने भारत में छोटे विमान बनाने की पहल की है।

फरवरी 2016 में मुंबई में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दौरान यादव ने पूरी तरह से स्वदेशी छोटा प्रायोगिक विमान बनाने का अपना विचार पेश किया था। पीएमओ ने ट्वीट किया है,'प्रायोगिक प्रोजेक्ट के लिए राइट टू फ्लाई हासिल करने सहित कई रुकावटें पैदा होने से देरी हुई।' देरी की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सभी नियामक अड़चनें दूर करने के लिए कहा गया। मोदी का विचार है कि कैप्टन यादव जैसे प्रतिबद्ध लोग न्यू इंडिया के लिए उत्साह हैं। पीएमओ ने यादव द्वारा विकसित सिंगल इंजन विमान की तस्वीर भी पोस्ट की है।

सिंघवी ने की सावरकर की तारीफ कहा-वह देश के लिए जेल गए

वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की की मांग का कांग्रेस पार्टी ने किया है विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर को भारत रत्न देने की महाराष्ट्र भाजपा की मांग पर पैदा हुए विवाद के बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी तारीफ की है। सिंघवी ने सोमवार को कहा कि सावरकर ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई बल्कि देश के लिए जेल भी गए। सिंघवी का यह बयान ऐसे में आया है, जब कांग्रेस ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की आलोचना की है।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सिंघवी ने सोमवार को ट्वीट किया, 'निजी तौर पर मैं सावरकर की विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह एक कुशल व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, दलित अधिकारों के लिए लड़े और देश के लिए जेल गए।'

ज्ञात हो, पिछले हफ्ते मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी सावरकर की सराहना की थी। उन्होंने कहा था, 'हम सावरकर जी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उस हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ हैं, जिसके साथ सावरकर जी खड़े थे।' उन्होंने यह भी कहा था कि इंदिरा गांधी ने पीएम रहते हुए सावरकर की याद में डाक टिकट जारी किया था। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र में कहा था-पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो वह केंद्र सरकार से सावरकर और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग करेगी। इस मांग की कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। कांग्रेस ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सावरकर के खिलाफ भी केस मामला चला था, भले ही वो बरी हो गए थे। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने कहा कि सिंघवी के बयान से पार्टी बेचैन हो गई। कांग्रेस को सिंघवी से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। पार्टी ने उनसे तुरंत अपने ट्वीट को स्पष्ट करने को कहा, अन्यथा पार्टी को नुकसान होगा।

सिंघवी ने लिया यू-टर्न : सिंघवी ने तुरंत यू-टर्न लिया। उन्होंने तुरंत दूसरा ट्वीट किया और कहा, 'वह सावरकर के अंधराष्ट्रवाद और गांधीवाद के विरोध से सहमत नहीं हो सकते।' कोई यह तो मान सकता है कि सावरकर राष्ट्रवादी उद्देश्यों से प्रेरित थे।

मुंबई की 32 कंपनियों के एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई स्थित 32 कंपनियों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल, अक्टूबर 2016 में शीर्ष अदालत ने फर्जी व्यापार गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में इन कंपनियों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन किसी कंपनी ने इसे नहीं भरा। शुक्रवार को रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

32 डिफॉल्टर कंपनियों की लिस्ट में अक्षर मर्केंटाइल, बीटा ट्रेडिंग, विनय मर्केंटाइल, अनूप मल्टीट्रेड, अंशुल मर्केंटाइल, एवरफेम ट्रेडिंग, हाईजोन ट्रेडिंग, इनऑर्बिट, ट्रेडिंग कंपनी, लक्ष्या मर्केंटाइल, मैगीनॉट ट्रेडिंग, मांट्रियल ट्रेडिंग, न्यूट्री मर्केंटाइल, सर्वेश्वर ट्रेडिंग आदि का नाम है। शीर्ष अदालत ने 2016 के अपने फैसले में इन कंपनियों पर फर्जी व्यापार गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में जुर्माना लगाया था।

बाजार नियामक सेबी के आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने इन सभी कंपनियों को तुरंत भुगतान करने के लिए कहा था। जब डिफॉल्टरों ने जुर्माना नहीं भरा तो सेबी ने 2017 में अदालत की अवमानना करने के आरोप में याचिका दायर की। पीठ ने डिफॉल्टर कंपनियों को आदेश का अनुपालन करने के लिए समय दिया, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों ने जुर्माना राशि अदा नहीं की।

परीक्षा केंद्रों पर अब मनमर्जी से नहीं लगाए जा सकेंगे जैमर

- यूजीसी ने विवि और कॉलेजों को तय गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश
- कहा, जैमर वहीं लगाए जाएं जहां सौ मीटर के दायरे में नहीं हो कोई भी मोबाइल टावर

प्रतीकात्मक फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अब मनमर्जी से जैमर नहीं लगाए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से इसे लेकर तय गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही कहा है कि जैमर वहीं लगाए जाएं जहां सौ मीटर के दायरे में कोई भी मोबाइल टावर (बीटीएस) न हो। साथ ही ऐसे जैमर का इस्तेमाल किया जाए, जिसका दायरा सिर्फ परीक्षा कक्ष तक ही सीमित हो।

यूजीसी ने यह निर्देश ऐसे समय दिया है, जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जैमर के बढ़ते इस्तेमाल से उसके आस-पास रहने वाले आम लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी थीं। परीक्षा के दौरान संस्थानों के आसपास रहने वाले लोगों के मोबाइल फोन और इंटरनेट घंटों बंद हो जा रहे थे। हालांकि यह उजागर तब हुआ, जब आम लोगों ने मोबाइल कंपनियों से खराब नेटवर्क की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मोबाइल कंपनियों ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई और जैमर के इस्तेमाल को लेकर तय गाइड लाइन का पालन न करने की शिकायत की। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने इसे लेकर जारी निर्देश में संस्थानों से तय नियमों के तहत जैमर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ ही उनसे जुड़े संस्थानों के परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाने की यह शुरुआत 2016 में हुई थी। उस समय यूजीसी ने परीक्षाओं में मोबाइल या इस तरह की डिवाइस के जरिये होने वाली नकल पर रोकथाम लगाने के लिए यह अनुमति दी थी। हालांकि इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से जैमर के इस्तेमाल को लेकर तय गाइड लाइन का पालन करने को कहा था। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल शुरू हुआ है, उससे एक नई तरह की समस्या खड़ी हो रही थी।

संगठन के नीतिगत ढांचे पर निर्णय आरटीआइ के दायरे में नहीं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के एक फैसले को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत इसकी परिकल्पना नहीं की गई है कि वह किसी संगठन के नीतिगत ढांचे पर निर्णय दे। बाल श्री योजना के तहत मेधावी छात्रों के चयन के लिए वर्तमान नीति को संशोधित करने के संबंध में सीआइसी ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने 11 नवंबर 2018 को सीआइसी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को दिए गए आदेश को रद करते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से यह निर्देश वैधानिक ढांचे और शक्तियों से परे है।

मंत्रालय ने अपील याचिका दायर कर कहा था कि सीआइसी का आदेश कानूनी रूप से ठीक नहीं है। यह अधिनियम के दायरे से बाहर है। इस तर्क से पीठ ने भी सहमति जताई। सीआइसी ने यह आदेश आवेदक द्वारा बाल भवन की सदस्यता के लिए आयु सीमा के बारे में जानकारी मांगने पर दिया था।

यह कहा था सीआइसी ने: सीआइसी ने आदेश में कहा था कि बाल श्री योजना के तहत मेधावी छात्रों के चयन के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट, पारदर्शी और निर्णय लेने में कमी है और इसमें सुधार की जरूरत है। आयोग ने एमएचआरडी को नीति के अंतर्विरोधों की फिर से जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बाल भवन की वेबसाइट पर संशोधित योजना रखी जाए।

चिदंबरम पिता-पुत्र ने मिलकर रची साजिश : सीबीआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइएनएक्स मामले में आरोपपत्र पर अदालत ने लिया संज्ञान
- पी. चिदंबरम को 24 अक्टूबर को विशेष कोर्ट में पेश करने के निर्देश

आइएनएक्स मीडिया डील के भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति समेत 14 लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया। सीबीआइ ने बताया कि 14 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने पी चिदंबरम को 24 अक्टूबर को और कार्ति चिदंबरम व अन्य 12 आरोपितों को 29 नवंबर को पेश करने के लिए समन जारी किया। सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। गुरुवार को ही चिदंबरम की ईडी की रिमांड भी समाप्त हो रही है।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने सीबीआइ से पूछा, आरोप पत्र में धारा-420 भी शामिल है, आखिर किसके साथ धोखाधड़ी हुई? इस पर एजेंसी की अधिवक्ता ने कहा, सरकार के साथ धोखाधड़ी की गई थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि आइएनएक्स मीडिया और आइएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड के एफडीआइ प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए पी.चिदंबरम ने बेटे कार्ति के साथ मिलकर साजिश रची थी। उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिलाई थी। आरोपपत्र में कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्करामन, आइएनएक्स मीडिया लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक पीटर मुखर्जी, नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधूश्री खुल्लर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, आइएनएक्स मीडिया एएससीएल एंड चेस मैनेजमेंट सर्विस के प्रबोध सक्सेना, रविंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा को आरोपित बनाया गया है। सरकारी गवाह बन चुकी इंद्राणी का भी इसमें नाम है। सीबीआइ ने आइपीसी की धारा 120बी, धारा 420, धारा-468, धारा-471 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

ईडी की हिरासत में हैं चिदंबरम : विशेष अदालत ने 17 अक्टूबर को पी चिदंबरम को सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। साथ ही सीबीआइ के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

जमानत पर फैसला आज

नई दिल्ली, आइएएनएस : आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ अपना फैसला सुनाएगी।

डीके शिवकुमार की मां व पत्नी को नया समन जारी करेगा ईडी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की पत्नी ऊषा और मां गौरम्मा के खिलाफ नया समन जारी करेगा। ज्ञात हो, ऊषा और गौरम्मा को 15 और 17 अक्टूबर को पेशी के लिए कहा था पर वह नहीं आयीं।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी के वकील अमित महाजन ने कहा, जांच रोकी नहीं जा सकती है, इसलिए नया समन जारी किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दयन कृष्णन ने कहा, ईडी जब भी नया समन जारी करेगा, उसे सीआइपीसी के नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र की किशोरी और बुजुर्ग महिला को थाने नहीं बुलाया जा सकता। गौरम्मा 85 वर्ष की हैं। ईडी उनसे घर जाकर पूछताछ कर सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय को रतुल पुरी से पूछताछ की मिली अनुमति

जासं, नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से तीन दिन तक तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है। न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने कहा, अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 22 से 24 अक्टूबर तक ईडी रतुल पुरी से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में कोर्ट ने पुरी की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। सीबीआइ ने गत 17 अगस्त को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी, दीपक पुरी व नीता पुरी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर 354 करोड़ का लोन लेने का आरोप है। ईडी ने भी इस संबंध में मामला दर्ज किया था और 20 अगस्त को पुरी को गिरफ्तार किया था। मनी लांड्रिंग मामले में पुरी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

अत्याधुनिक कैमरों से लैस होंगे सीआरपीएफ के डॉग

- केंद्रीय बल के लिए शुरुआत में 25 कैमरे खरीदने की प्रक्रिया शुरू
- जम्मू-कश्मीर व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात इकाइयों में होंगे कैमरे वाले डॉग

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ : जम्मू-कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की इकाइयों के प्रशिक्षित डॉग को अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया जाएगा। शुरुआत में सीआरपीएफ इसके लिए 25 'पुलिस डॉग कैमरे' खरीदेगी। एक दस्तावेज से यह जानकारी मिली है।

पिछले कुछ महीनों से सीआरपीएफ इस तरह के कैमरों को लेकर छानबीन कर रही है। उसके संचालन के तौर तरीकों के बारे में भी केंद्रीय बल जानकारी हासिल कर रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अपनी के9 इकाई के लिए कैमरे खरीदने वाला सीआरपीएफ देश का पहला बल होगा। ये कैमरे हाई रिसोलुशन के तो होंगे ही वाटर-प्रूफ और स्क्रैच-प्रूफ भी नहीं पड़ेंगे।

डॉग (कुत्तों) में लगाए जाने वाले कैमरों को 'पुलिस डॉग कैमरा' के नाम से जाना जाता है। सीआरपीएफ की इकाइयों के डॉग के पिछले हिस्से में कैमरे लगाए जाएंगे। इससे यह भी पता चलता रहेगा कि किस समय डॉग क्या देख रहा है। डॉग स्क्वायड में तैनात कर्मचारियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका समेत दुनिया के अन्य कई देशों में भी के9 इकाइयां हैं, जो बहुत ही बेहतरी से काम करती हैं। कई देशों में डॉग के गले में कैमरे लगाए जाते हैं तो कई देशों में उनके पिछले हिस्से में। इनके जरिए अपराधियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे आखिरकार अपराध पर काबू पाने में मदद मिलती है। बदली परिस्थितियों में दुनिया के तमाम देश अत्याधुनिक उपकरणों को इस्तेमाल कर रहे हैं।

लोकतंत्र में अकल्पनीय व्यवधान पैदा कर सकता है इंटरनेट : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राजनीति में अकल्पनीय व्यवधान पैदा करने वाले शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरा है। सरकार ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतिम रूप देने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए और तीन महीने का वक्त मांगा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शीर्ष अदालत से कहा कि यद्यपि की प्रौद्योगिकी से आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास हुआ है, इसके साथ ही अभद्र भाषा, फर्जी खबरें और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि भी हुई है।

जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र की तरफ से पेश वकील रजत नायर के मेंशन करने के बाद हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाएं दिशानिर्देश (संशोधन) नियम, 2018 को अंतिम रूप देने के लिए और तीन महीने का समय मांगा। यह हलफनामा फेसबुक की ट्रांसफर याचिका पर दायर किया गया। फेसबुक ने तीन हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने से संबंधित दायर मामलों को ट्रांसफर करने की अपील की है।

संसद का शीत सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कई अहम विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी सरकार
- जबकि विपक्षी दल कई मसलों पर सरकार को घेरेंगे

संसद भवन फाइल फोटो

संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने यह जानकारी लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय को भेज दी है। इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी। जबकि विपक्षी पार्टियां कश्मीर में लगाये गये प्रतिबंध, मुख्यधारा के नेताओं को हिरासत में रखे जाने और आर्थिक सुस्ती जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी।

केंद्र की राजग सरकार फिलहाल दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। इनमें से एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम-2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। जबकि दूसरा अध्यादेश सितंबर में ही जारी किया गया था, जिसमें ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है।

केंद्र की मोदी सरकार के दोबारा सत्ता (17वीं लोकसभा) में आने के बाद पहला सत्र 17 जून से 6 अगस्त तक चला था, जिसे सभी दलों की सहमति के बाद बढ़ा दिया गया था। उस सत्र में पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित कराये थे। उसी समय जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने संबंधी विधेयक को भी मंजूरी मिली थी।

अभिजीत की मां ने कहा

अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी की मां ने बेटे की आलोचना करने वालों की जमकर खिंचाई की

विरोधियों के विचारों का भी सम्मान करें आलोचक

जागरण संवाददाता, कोलकाता

अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी की मां निर्मला देवी ने बेटे की आलोचना करने वालों की जमकर खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उनके बेटे की आलोचना करने वालों को विरोधियों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यह भी कहा कि उनके बेटे के बारे में भला-बुरा कहकर विरोधी अपनी बातों को सही साबित नहीं कर पाएंगे।

ज्ञात हो रेलमंत्री पीयूष गोयल ने अभिजीत को वामपंथी विचारधारा से प्रभावित बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अभिजीत की न्यूनतम आय वाली योजना 'न्याय' को देश की जनता ने खारिज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने भी कहा था कि वह अपने अर्थशास्त्र को बंगाल के एक गांव में भी सफलतापूर्वक लागू करके दिखाएं। राहुल ने यह भी कहा था कि विदेशी महिला से दूसरी शादी करने वालों को ही मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। निर्मला देवी ने इस पर कहा-'जो लोग अभिजीत के व्यक्तिगत जीवन और उसकी दूसरी शादी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अगर लगता है कि विदेशी महिला से दूसरी शादी करने पर नोबेल पुरस्कार मिलना सुनिश्चित हो सकता है तो वे खुद ऐसा क्यों नहीं कर लेते। ऐसा करने पर हमारे आसपास बहुत से नोबेल विजेता हो जाएंगे।'

> मेरे बेटे के खिलाफ जो बातें कही गई हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। यह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और विशेषाधिकार है, लेकिन इस तरह से वे अपनी बातें साबित नहीं कर पाएंगे।
> -निर्मला देवी, नोबेल विजेता अभिजीत की मां

पीएम मोदी से मुलाकात आज

अभिजीत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मां इसे लेकर भी बेटे को सावधान करना चाहती हैं। बता दें अभिजीत ने मोदी सरकार की अर्थनीति की आलोचना करते हुए कहा था कि मांग घट रही है, जो चिंताजनक है। आंकड़ों को लेकर भी भ्रम है। इसके बाद रेलमंत्री पीयूष गोयल व भाजपा नेता राहुल सिन्हा द्वारा अभिजीत की आलोचना के परिप्रेक्ष्य में निर्मला देवी चाहती हैं कि उनका बेटा पीएम मोदी से सोच-समझकर कोई बात करे।

बेटे के लिए बनाएंगी मटन कबाब और मछली करी

अभिजीत मंगलवार को ही कोलकाता आएंगे। दक्षिण कोलकाता स्थित उनके घर में इसे लेकर हलचल है। मां निर्मला देवी काफी व्यस्त हैं। वह बेटे के पसंदीदा पकवान तैयार करने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बताया कि बेटे के लिए मटन कबाब और मछली करी बनाएंगी।

अब 'डैमेज कंट्रोल' में जुटी बंगाल भाजपा

नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 'डैमेज कंट्रोल' शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने सभी छोटे-बड़े नेताओं को अभिजीत के खिलाफ अब किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है। पार्टी का मानना है कि नोबेल विजेता अभिजीत के खिलाफ बयानबाजी से बंगाल में उसकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि राज्य की जनता इसे अच्छी नजर से नहीं ले रही है। बंगाल भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहा-'राज्य के लोग अपने नायकों को लेकर काफी संवेदनशील हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद बंगाल में अभिजीत बनर्जी का कद काफी ऊंचा हो गया है और हमें प्रवाह के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।'

कह के रहेंगे माधव जोशी

देर से निकले वोटर, हरियाणा में 65 तो महाराष्ट्र में 60 फीसद मतदान

दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद, 24 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, लोकसभा की दो और विधानसभा की 51 सीटों पर उप चुनाव के लिए भी पड़े वोट

महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार को बारामती में एक मतदान केंद्र पर ग्राउंड गीला होने के कारण मतदाताओं को परेशानी से बचाने के लिए अनोखा इंतजाम किया गया। यहां ग्राउंड में ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को इस तरह कतार में परस्पर जोड़ दिया गया। इसके बाद मतदाता ट्रॉलियों के सहारे बूथ तक जाकर मतदान करते नजर आए। प्रेट्र

जेएनएन, नई दिल्ली

हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को हुए मतदान की रफ्तार शुरुआत में बेहद धीमी रही, लेकिन शाम तक यह संतोषजनक स्थिति तक पहुंच गई। हरियाणा में 65 फीसद लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया तो महाराष्ट्र में 60.66 फीसद मतदाताओं ने वोट डाले। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव में 77 फीसद वोट पड़े। उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों की विधानसभा की 51 और लोकसभा की दो सीटों के लिए उप चुनाव में भी वोट डाले गए। 24 अक्टूबर को मतगणना होगी।

भाजपा शासित हरियाणा में मतदान के प्रति लोगों का रुझान कम रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव में 76.54 फीसद लोगों ने वोट डाले थे। कुछ माह पूर्व हुए लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 70.35 रहा था, जबकि इस बार मतदान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने पिछली बार 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव में 63 फीसद मतदान हुआ था। इस बार शहर की बजाय ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह ज्यादा दिखा। राज्य की 288 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा 150 और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 147 और राकांपा 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

लखनऊ कैंट में सिर्फ 28.53 फीसद मतदान : उत्तर प्रदेश विधानसभा की 11 सीटों के लिए हुए उप चुनाव में 47.05 फीसद मतदान हुआ। सहारनपुर की गंगोह सीट पर सर्वाधिक 60.30, जबकि लखनऊ कैंट में सबसे कम 28.53 प्रतिशत मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले की चित्रकोट विधानसभा सीट पर करीब 77.40 फीसद मतदाताओं ने वोट दिया। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। मध्यप्रदेश के झाबुआ में 62.01 फीसद मतदान हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां मतदान प्रतिशत 64.45 रहा था। राजस्थान में नागौर की खींवसर सीट पर 62.61 और झुंझुनूं की मंडावा सीट पर 69.62 लोगों ने वोट डाले। बिहार में पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीटों पर उप चुनाव में मतदान हुआ। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर महज 45 फीसद मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि विधानसभा की पांच सीटों पर हुए उप चुनाव में करीब 50 फीसद वोट पड़े। ओडिशा के बीजेपुर में 72 फीसद मतदान हुआ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के छोड़ देने के कारण यह सीट खाली हुई थी। सिक्किम में तीन सीटों पर हुए उप चुनाव में 68.37 फीसद मतदान हुआ।

पंजाब की चार सीटों फगवाड़ा, जलालाबाद, दाखा और मुकेरियां में औसतन 60 फीसद से अधिक मतदान हुआ। गुजरात की छह सीटों पर हुए उप चुनाव में औसतन 53.55 फीसद लोगों ने वोट डाले। राज्य की थराद में 68.95 फीसद और अहमदाबाद के अमराईवाड़ी में 31.53 फीसद मतदान हुआ है।

चिंता का सबब बनी हरियाणा में मतदाताओं की उदासीनता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव नतीजों में सत्ताधारी दल फिर से सत्ता में आती दिख तो रही है, लेकिन हरियाणा में वोटरों की उदासीनता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लगभग दस फीसद कम वोट पड़े हैं। यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले पांच-छह साल में शायद किसी राज्य ने अपना पिछला प्रदर्शन न सुधारा हो। ऐसे में दिल्ली से सटे हरियाणा का रुझान सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय होगा।

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काफी प्रयास हुए हैं। चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान और सार्थक प्रयासों के जरिये मतदान को बढ़ाने का काम किया है। वहीं, भाजपा की ओर से संगठन के स्तर पर कोशिशें हुई हैं कि कम से कम उनका समर्थक वर्ग जरूर बाहर आए। इसी लिहाज से नए लोगों को जोड़ा भी गया।

देश की राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण हरियाणा में राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभावी होते हैं। ऐसे में मतदान प्रतिशत में कमी आना राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय होगा। राज्य में जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ था, उसके कारण विपक्ष के मतदाताओं की उदासीनता स्वभाविक है, लेकिन यह देखने की बात होगी कि भाजपा अपने पिछले वोट प्रदर्शन से आगे रहती है या पीछे।

उचाना में दुष्यंत और भाजपा कार्यकर्ताओं में तकरार

संवाद सूत्र, उचाना (जींद) : हरियाणा के जींद जिले की हॉट सीट उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र के गांव डूमरखां में मतदान के दौरान हंगामा हो गया। यहां फर्जी वोटिंग की सूचना मिलने पर जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस दौरान एक महिला मतदान केंद्र पर पहुंची, लेकिन उसका वोट पहले ही डाला जा चुका था। दुष्यंत ने इसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों से की। आरोप है कि इस पर भाजपा के एजेंट ने उनकी तरफ गिलास फेंका। हालांकि, वह उन्हें नहीं लगा। दुष्यंत ने चुनाव ऑब्जर्वर को इसकी लिखित में शिकायत दी। हंगामे की सूचना मिलते ही डीसी डॉ. आदित्य दहिया व एसएसपी अश्विन शैणवी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए। दुष्यंत ने बताया कि कार्रवाई के लिए डीसी जींद, चुनाव आयोग अधिकारी को लिखा है और दोबारा से इस बूथ पर मतदान की मांग की है।

एक्जिट पोल ने बढ़ा दी संकट के दौर से गुजर रही कांग्रेस की बेचैनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पार्टी में जल्द बड़े बदलाव की फिर शुरू हुई चर्चा

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल के अनुमानों ने कांग्रेस में एक बार फिर बेचैनी भरी हलचल मचा दी है। एक्जिट पोल के अनुसार, इन दोनों सूबों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पहले से ही गहरे संकट का सामना कर रही पार्टी में इन संकेतों के बाद संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है।

लोकसभा चुनाव 2019 के पांच महीने के भीतर ही दो बड़े सूबों में पार्टी की दिख रही सूरत से साफ है कि कांग्रेस के लिए हालात बदले नहीं है। इसीलिए वोटिंग तक तमाम दावे कर रहे कांग्रेस नेता एक्जिट पोल के अनुमानों के बाद पार्टी मुख्यालय के गलियारों में लंबी लड़ाई की बात कहते हुए नतीजों के लिए कलेजा मजबूत करते दिखे। इन दोनों सूबों के चुनाव से जुड़े पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि महाराष्ट्र में संगठन की कमजोरी तो हरियाणा में बड़े नेताओं के बीच आपसी फूट ने भाजपा को बड़ा मौका दे दिया। मगर यह भी कहना मुनासिब होगा कि अब केवल खामियों और कमजोरियों को गिनाकर नतीजों को स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनने वाली।

कांग्रेस के एक दूसरे पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे और सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद भी पार्टी के संकट का समाधान नहीं निकला है। सोनिया की वापसी के बाद पार्टी में तात्कालिक जरूरत के हिसाब से सूबों में कुछ एक बदलाव हुए हैं मगर एआइसीसी से लेकर प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तभी कांग्रेस में यह चर्चा चल रही है कि संगठनात्मक बदलाव के साथ खामियों को दुरुस्त करने के लिए पारदर्शी अंदरूनी तंत्र बनाया जाए।

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ कहना है कि इसमें अब देरी की गुंजाइश आत्मघाती होगा। इसीलिए संगठन में बदलाव के साथ सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष की तस्वीर भी आने वाले दिनों में साफ होनी चाहिए। सेहत की चुनौतियों को देखते हुए सोनिया पार्टी का नेतृत्व लंबे समय तक कर पाएंगी इसको लेकर भी संशय है और ऐसे में पार्टी गलियारों में ऐसी कानाफूसी शुरू हो गई है कि अगले साल देर-सबेर राहुल गांधी की अध्यक्ष के रूप में वापसी हो तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि पार्टी रणनीतिकार फिलहाल ऐसी चर्चाओं को तवज्जो नहीं दे रहे।

मुंबई में सोमवार को पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक केंद्र पर पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन के साथ मतदान किया। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी पति अभिषेक बच्चन के साथ वोट डालने पहुंचीं। प्रेट्र

खेल से लेकर फिल्म जगत की हस्तियों में मतदान को लेकर दिखा बहुत उत्साह

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले गए। खेल से लेकर राजनीति और सिनेमा से जुड़ी हस्तियों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला, लेकिन रतन टाटा, मुकेश और अनिल अंबानी समेत उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

टाटा, अंबानी समेत उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने नहीं किया मतदान

भागवत, ठाकरे, पवार, शाह रुख, आमिर, सलमान और माधुरी ने डाला वोट

टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, जिंदल स्टील के चेयरमैन सज्जन जिंदल और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।

सूत्रों ने बताया कि टाटा, चंद्रशेखरन और जिंदल पहले से तय कार्यक्रमों के चलते शहर से बाहर थे, लेकिन अंबानी भाइयों ने क्यों मतदान नहीं किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अमूमन दोनों भाई अपने परिवार के साथ मतदान में हिस्सा लेते रहे हैं।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एचडीएफसी के चीफ एग्जीक्यूटिव केकी मिस्त्री, मैरिको ग्रुप के चेयरमैन हर्ष मरीवाला और एम एंड एम के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

छगन भुजबल ने नहीं किया मतदान

राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने मतदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने चुनाव क्षेत्र में व्यस्त होने के चलते वह मतदान नहीं कर पाए। वह नासिक जिले के येवला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि वह नासिक शहर में रहते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, राकांपा प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मतदान करने वालों में प्रमुख थे। सचिन ने पत्नी अंजलि और बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ मतदान किया।

फिल्मी हस्तियों में शाह रुख खान, सलमान खान, आमिर खान, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित के साथ ही लारा दत्ता ने मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया के साथ लातुर जिले में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। यहां रितेश के भाई चुनावी मैदान में हैं। मुंबई में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ 93 साल के पूर्व फौजी ने भी मतदान किया, जबकि पुणे में 102 साल के इब्राहिम अलीम जोअद अस्पताल से डिसचार्ज होने के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंच गए और मताधिकार का प्रयोग किया।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतदान करने में बॉलीवुड सितारे पीछे नहीं रहे। मुंबई में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेता आमिर खान, माधुरी दीक्षित, रितिक रोशन और करीना कपूर खान समेत कई दिग्गजों ने लोकतंत्र के इस यज्ञ में वोटों की आहुति दी। मायानगरी के बांद्रा और अंधेरी स्थित बूथ पर कलाकारों का सुबह से ही तांता लगा रहा। प्रेट्र/एएनआइ

हरियाणा में स्थाई सरकार की ओर बढ़ी जनता

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

भाजपा की सीटों में आश्चर्य ढंग से इजाफा होने की उम्मीद

जीरो से शुरू करने पर कांग्रेस को नहीं मिल पाया ज्यादा समय

हरियाणा के चरखी दादरी में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी बबीता फोगाट (दाएं) ने बहन गीता फोगाट के साथ विधानसभा चुनाव के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रेट्र

हरियाणा एक बार फिर स्थाई सरकार की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर सोमवार को हुए मतदान के बाद जनता-जनार्दन के रुख से कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। हालांकि, आरंभ में कम मतदान ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी थीं, मगर जैसे-जैसे मतदान प्रक्रिया पूरी होने का समय आया, वैसे-वैसे मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी ने राजनीतिक दलों खासकर भाजपा की उम्मीदों का ग्राफ बढ़ा दिया। राज्यभर से मिले रुझान के आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा हरियाणा में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। उसकी सीटों में आश्चर्यजनक ढंग से इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, इसी तरह की उम्मीद कांग्रेस व जजपा को भी है।

प्रदेश में इस बार के चुनाव नतीजे 2014 के चुनाव परिणाम से काफी भिन्न रहने की संभावना है। 75 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने वाली भाजपा के सामने कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी ने यह चुनाव पूरी शिद्दत के साथ लड़ा। हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद हुड्डा और सैलजा की जोड़ी ने जीरो से शुरू किया तो यही स्थिति दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के सामने रही। इनेलो में हुए बिखराव के बाद जजपा का यह पहला विधानसभा चुनाव है, जिसके नतीजे दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करने वाले साबित हो सकते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 47 सीटें जीती थीं। उस समय भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 10 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 15 साल से सत्ता से बाहर रहे इनेलो के खाते में उस समय 19 सीटें आई थीं। इन पांच सालों में भाजपा ने खुद का ग्राफ बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस पूरे पांच साल फूट का शिकार रही।

अशोक तंवर के स्थान पर सैलजा को अध्यक्ष तथा हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने का फैसला काफी देर से हुआ। ताऊ देवीलाल के परिवार में राजनीतिक विघटन के बाद अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की अलग-अलग राजनीतिक राहों का नुकसान इस परिवार को उठाना पड़ा। इसके बावजूद हुड्डा, सैलजा व दुष्यंत ने चुनाव के रण में एक शानदार योद्धा के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश की।

चुनावी रुझान के आधार पर सैलजा, हुड्डा व दुष्यंत तीनों को अपनी-अपनी पार्टियों की सरकार बनने की आस है, लेकिन इसके लिए बताया जा रहा नंबर गेम ऐसा है कि फौरी तौर पर उस पर यकीन करना वाजिब नहीं है। आरंभ में जब शहरी क्षेत्रों में कम मतदान हुआ, तब लग रहा था कि भाजपा को अपना लक्ष्य साधने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन शाम के वक्त जिस तरह मतदान में तेजी आई और गांवों के साथ-साथ शहरों में भी मत प्रतिशत बढ़ा ।

रखी बात

नागपुर में मतदान करने के बाद सरसंघचालक बोले- समाज एक है और हमेशा एक ही रहेगा

संघ को 90 वर्षों से बना रहे निशाना : मोहन भागवत

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि बीते 90 वर्षों से संघ को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि समाज एक है और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। वहीं, संघ के सरकार्यवाह भय्याजी जोशी का कहना है कि देश में हिंदू नेता असुरक्षित नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका यह बयान हाल ही में लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या के सिलसिले में बेहद महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नागपुर में मतदान करने के बाद संघ के प्रमुख भागवत से वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर कांग्रेस के संघ को निशाना बनाने के बारे में पूछा गया था। हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर पर पूछे गए सवाल के जवाब में भागवत ने कहा, 'हम पर तो बीते 90 वर्षों से हमले किए जा रहे हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि समाज एक है और हमेशा एक ही रहेगा। यह तो राजनीति है और यह सब उसी का हिस्सा है।' विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर भागवत ने कहा, 'मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए इसका अनुमान मैं नहीं लगा सकता। तीन दिन में परिणाम आ जाएगा तब सभी को पता चल जाएगा।'

चुनाव परिणाम के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं इसलिए नहीं लगा सकता अनुमान

मुद्दों पर करें मतदान : भागवत ने लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने जन प्रतिनिधियों को चुनें। उन्होंने कहा, 'हम 100 फीसद मतदान पर जोर देते हैं। किसी व्यक्ति या माहौल को देखकर वोट ना दें बल्कि मुद्दों के आधार पर मतदान करें।' भागवत मतदान के लिए सुबह सात बजे ही महल इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे।

हिंदू नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए : भय्याजी जोशी

संघ में दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने हिंदू महासभा के एक पूर्व नेता कमलेश तिवारी की लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या पर हिंदू नेताओं को पुख्ता सुरक्षा देने की दलील दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि संघ का मानना है कि हिंदू नेता देश में असुरक्षित नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। दिवंगत नेता तिवारी की मां के सरकार के हिंदुओं के हित में काम न करने का आरोप लगाने पर जोशी ने कहा कि सरकार को दिवंगत की मां को जवाब देना चाहिए और वह निश्चित रूप से देगी। वीर सावरकर को भारत रत्न देने के भाजपा के प्रस्ताव और कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या कह रही है, हमें नहीं पता है। हम इतना चाहते हैं कि देश के प्रेरणास्रोत रहे एक व्यक्ति (सावरकर) को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नागपुर में मतदान करने के बाद अंगुली पर स्याही दिखाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। प्रेट्र

डिप्टी सीएम पर शिवसेना से कोई आधिकारिक बात नहीं हुई : भूपेंद्र

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा के महाराष्ट्र चुनाव मामलों के प्रभारी और पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि राज्य में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सहयोगी शिवसेना के साथ कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को दो-तिहाई सीटों पर जीत मिलेगी।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि किसको क्या पद देना है यह तय करने का अधिकार पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी देवेंद्र फड़नवीस के पास है, किसी और के पास नहीं। यादव का यह बयान इस मायने में अहम है क्योंकि चुनाव से पहले ही दोनों सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव देखने को मिला था। भाजपा और शिवसेना ने पिछला चुनाव अलग-अलग लड़ा था और सरकार बनाने के लिए दोनों दल साथ आए थे। उन्होंने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने के फैसले की भी सराहना की।

कहा, महाराष्ट्र में गठबंधन को दो-तिहाई सीटों पर मिलेगी जीत

पिछला चुनाव भाजपा और शिवसेना ने अलग-अलग लड़ा था, इस बार हैं साथ

पिछली बार से ज्यादा नकदी और ड्रग्स बरामद : समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक मतदान समाप्त होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में चुनाव आयोग ने बताया कि 2014 की तुलना में महाराष्ट्र और हरियाणा में इस बार ज्यादा मात्रा में नकदी और ड्रग की बरामदगी हुई। चुनाव आयोग में महानिदेशक (व्यय) दिलीप शर्मा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में 156.94 करोड़ रुपये जब्त किए गए। इसमें 60.69 करोड़ रुपये नकद, 23 करोड़ रुपये की शराब और 19.5 करोड़ रुपये की ड्रग शामिल है। पिछले चुनाव में 30 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। इसी तरह हरियाणा में 2014 के 8.58 करोड़ रुपये के मुकाबले इस चुनाव में 24.17 करोड़ रुपये जब्त किए गए।

1885 में पहली बार अयोध्या मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवरदास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राममंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की थी।

हिंदू पक्ष को दे दिया वैकल्पिक राहत का नोट : मुस्लिम पक्ष

रखा पक्ष ▶ अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत को दी गई जानकारी

हिंदू पक्ष ने सील बंद लिफाफे में दाखिल करने पर जताया था एतराज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक राहत का जो नोट उन्होंने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा था उसे हिंदू पक्ष को भी दे दिया गया है। कोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर ले लिया। बाद में मुस्लिम पक्ष ने अपने इस नोट को सार्वजनिक कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

सोमवार को मुस्लिम पक्ष के वकील एजाज मकबूल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे और एसए अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि छह मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सील बंद लिफाफे में दिए गए नोट पर दूसरे (हिंदू) पक्ष की ओर से एतराज जताया गया था जिस पर उन लोगों ने रविवार को दूसरे पक्ष को भी उसकी प्रति दे दी है। उन्होंने तीन सदस्यीय पीठ से अनुरोध किया कि उनके लिखित नोट को मामले की सुनवाई करने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी जाए। जब वकील ने यह बात कही तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह नोट सील बंद लिफाफे में उनकी मेज पर है, लेकिन उन्होंने उसे अखबार में देखा है। बता दें कि वैकल्पिक राहत के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दिए गए लिखित नोट में कोर्ट से कहा गया है कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में आने वाले फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। इसका असर भावी पीढ़ी और राजनीति पर भी पड़ेगा। इसलिए कोर्ट फैसला देते वक्त देश के भविष्य का ध्यान रखे। लिखित नोट में यह भी कहा गया है कि कोर्ट विवाद का हल निकालते वक्त देश के बहुधर्म और बहु सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखे। कोर्ट संविधान का प्रहरी है और वैकल्पिक राहत तय करते समय यह उसकी जिम्मेदारी है। हिंदू पक्ष की ओर से वैकल्पिक राहत के मुद्दे पर दिए गए लिखित नोट में पूरी जमीन रामलला विराजमान को दिए जाने की बात कही गई है और उन्होंने कोर्ट से विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर पूर्ण न्याय करने की गुहार लगाई है।

मालूम हो कि कोर्ट ने 16 अक्टूबर को मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखते वक्त पक्षकारों को वैकल्पिक राहत पर तीन दिन के भीतर लिखित नोट दाखिल करने की छूट दी थी।

'अयोध्या रीविजिटेड' के मानचित्र से होती है रामजन्मभूमि की पुष्टि

रघुवरशरण, अयोध्या

जिस स्थल पर रामलला विराजमान हैं, वह रामजन्मभूमि थी अथवा बाबरी मस्जिद। इस सच्चाई पर से पर्दा तो अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ उठेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जो इस विवाद में मील के पत्थर की तरह हैं।

इस सूची में वह मानचित्र भी है, जिसे बुधवार को सुनवाई के अंतिम दिन कोर्ट में ही बाबरी मस्जिद के अधिवक्ता राजीव धवन ने फाड़ दिया था। फाड़े गए मानचित्र के बारे में जानना रोचक है। यह मानचित्र तीन वर्ष पूर्व प्रकाशित मंदिर-मस्जिद विवाद के प्रतिनिधि ग्रंथ 'अयोध्या रीविजिटेड' में संलग्न है। पुस्तक के लेखक गुजरात के सहायक पुलिस महानिदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले आचार्य कुणाल किशोर हैं। यह शोधपूर्ण ग्रंथ उन्होंने एक दशक की मेहनत से तैयार किया है और इसमें पुरातन-प्राचीन संदर्भों तथा आधुनिक घटनाक्रम को संयोजित कर निष्कर्ष निकालने की कोशिश हुई है।

अयोध्या के विवादित स्थल का वह मानचित्र, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने फाड़ा गया। (फाइल फोटो)

अनुष्ठान के लिए गोसाईंगंज स्थित रामगंज में राम जानकी मंदिर की सफाई व रंगाई करते लोग। जागरण

ब्रिटिशकालीन गजेटियर का आधार है अयोध्या रीविजिटेड : आचार्य कुणाल ने यूरोपीय एवं अरब यात्रियों, विभिन्न धाराओं के समकालीन इतिहासकारों के विवरण एवं ब्रिटिशकालीन गजेटियर को आधार बनाया है। अयोध्या रिविजिटेड में उन्होंने यह बताया है कि रामजन्मभूमि पर बने मंदिर को बाबर ने नहीं औरंगजेब ने तोड़वाया था। औरंगजेब धर्मांध था। उसी के समय देश के कई प्रमुख मंदिरों को तोड़े जाने के दौरान 1760 में रामजन्मभूमि पर बना मंदिर भी तोड़ा गया। इसी संदर्भ में वह मानचित्र भी है, जिसे देखकर मस्जिद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता कोर्ट में ही भड़क उठे। यह मानचित्र 30 नवंबर 1858 में सईद मुहम्मद की रिपोर्ट, 1767 में ब्रिटिश यात्री जोसफ टिल्फनर के वृत्तांत, 1810 में फ्रांसिस बुकानन की प्लॉन ऑफ अयोध्या, आक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में संरक्षित अयोध्या महात्म्य, 1870 में प्रकाशित पीसी कार्नेगी की 'अजुधिया महात्म' और 1950 के एक प्रामाणिक मानचित्र के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें करीब 14 हजार वर्ग फीट के संपूर्ण विवादित स्थल सहित आसपास की भूमि पर भी मंदिर दर्शित किया गया है और मस्जिद का कोई निशान नहीं है।

राम जानकी मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी : राम जानकी मंदिर में राममंदिर के पक्ष में फैसले के लिए अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई है। महंत आचार्य राधेश्याम शास्त्री की आगुवाई में मंदिर के रंगरोगन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। उनका कहना है कि अति शीघ्र मंदिर में अनुष्ठान शुरू होगा। रामगंज में सैकड़ों वर्ष पुराना राम जानकी मंदिर है।

मंदिरों को तोड़कर बनाई गई कुतुबमीनार में मस्जिद

कुतुबमीनार परिसर स्थित मस्जिद के स्तंभ मे लगी मूर्तियां। जागरण

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

कुतुबमीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के स्तंभों पर लगी देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां और मंदिरों जैसी इसकी नक्काशी यह गवाही दे रही है कि मंदिरों को तोड़कर इसे बनाया गया था। मस्जिद के पिछले हिस्से में नाली के ऊपर लगी एक मूर्ति को लेकर यहां पूर्व में विवाद भी हो चुका है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने लोहे के जाल से मूर्ति को ढक दिया है। यही नहीं मस्जिद के आसपास के क्षतिग्रस्त भाग से मूर्तियां भी निकली हैं।

विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त कुतुबमीनार के परिसर में स्थित यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्मारक है। इतिहासकारों के मुताबिक इसका निर्माण दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसका कार्य 1198 में पूरा हुआ। पुरातात्विक दस्तावेजों में साफ तौर पर वर्णित है कि कुतबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इन्हीं मंदिरों के नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से इसका निर्माण कराए जाने का दावा इतिहासकार करते हैं। इसके स्तंभों पर आज भी देवी-देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस मस्जिद का काफी हिस्सा ढह चुका है, मगर मस्जिद का जो हिस्सा शेष बचा है। वह पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इनमें अधिकतर मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। कहा जाता है कि इन्हें यहां लगाए जाने के समय ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, ताकि लोग यहां पूजा पाठ करना शुरू न कर दें। देवी-देवताओं की इन मूर्तियों को लेकर कुछ साल पहले विवाद भी हो चुका है। उस समय कई हिंदू संगठन यहां पूजा-अर्चना करने पहुंच गए थे। उनकी सबसे अधिक आपत्ति इस मस्जिद के पीछे के भाग में लगी मूर्ति को लेकर थी, जिसे एक नाली के ऊपर लगाया गया है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने इस मूर्ति के ऊपर लोहे का मोटा जाल लगवा दिया है। पूर्व में इस स्तंभ के ऊपर प्लास्टर किया गया था, जो अब उतर गया है।

कुतुबमीनार के पास ही एक चाहरदीवारी भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसमें पत्थर की मूर्ति निकली है, जिसे वहीं रखवा दिया गया है। पुरातात्विक अभिलेखों के मुताबिक चार सौवीं शताब्दी में राजा अनंगपाल यहां विष्णु पर्वत से विभिन्न धातु के बने विष्णु स्तंभ लेकर आए थे, जो आज भी इसी परिसर में स्थित हैं। इस स्तंभ पर गुप्तकाल की लिपि में संस्कृत में एक लेख है। जिसे पुरालेखीय दृष्टि से चतुर्थ शताब्दी का निर्धारित किया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डा. केके मुहम्मद ने भी अयोध्या मसले पर चर्चा के दौरान इस मस्जिद का जिक्र किया था। उनका कहना था कि अयोध्या में विवादित ढांचे के हालात भी दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तरह हैं।

हिंदू संगठनों का दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद है, यहां पर भी पूर्व में मंदिर था। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. विनोद बंसल कहते हैं कि यह पहला स्थान नहीं है, जहां मंदिर था। देश में 30 हजार ऐसे हिंदू स्थान हैं, जिन्हें जोड़कर मुस्लिम मान्यताओं को मानने वालों के केंद्र बनाए गए हैं। यह सब गुलाम वंश और मुगलकाल के शासकों द्वारा हिंदुओं को दी गई पीड़ा है।

यह बात सही है कि कुतुबमीनार स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। पुराने समय में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके लिए आज के मुस्लिम जिम्मेदार नहीं हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बारे में दिए बयान में मैने इस मस्जिद का जिक्र केवल अपनी बात को सही तरह से समझाने के संदर्भ में किया है। इसे किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

डा. केके मुहम्मद, पूर्व निदेशक, एएसआइ

राम मंदिर के लिए राजस्थान के दौसा में भी तेजी से तराशे जा रहे हैं पत्थर

जागरण संवाददाता, जयपुर

- **तोरण द्वार, पिलर, जाली और झरोखों के लिए यहां तैयार हो रहे हैं पत्थर**
- **सिकंदरा से नक्काशी के तीन दर्जन कारीगर दिवाली बाद जाएंगे अयोध्या**

अयोध्या में राम मंदिर के लिए राजस्थान के भरतपुर के बाद अब दौसा जिले के सिकंदरा में भी पत्थर तराशने के काम में तेजी आ गई है। सिकंदरा में राम मंदिर निर्माण में काम आने वाले तोरण द्वार, पिलर, जाली और झरोखों के साथ ही विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों पर नक्काशी का काम कुछ दिन से तेजी से किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दुबई में सिकंदरा के सैंडस्टोन पत्थरों की नक्काशी की काफी मांग है।

जानकारी के मुताबिक अयोध्या भेजने के लिए पांच ट्रक माल तैयार हो चुका है। करीब तीन दर्जन कारीगर भी मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने तक के लिए अयोध्या भेजे जाएंगे। उधर, भरतपुर के बंशी पहाड़पुर की पहाड़ियों से लाल पत्थर निकालने और तराशने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। यहां बनी कार्यशाला में मंदिर मॉडल के अनुरूप तराशे गए पत्थरों की साफ-सफाई कर उनको चमकाने का कार्य किया जा रहा है। वैसे तो बंशी पहाड़पुर से करीब पच्चीस साल से राम मंदिर के लिए लाल पत्थर निकालकर तराशे जा रहे हैं, लेकिन अब इस काम में अधिक तेजी आई है।

> कुछ साल पहले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण में उपयोग होने वाले पत्थर की नक्काशी के लिए यहां के कारीगरों से संपर्क किया था। इसके बाद से यहां छोटे स्तर पर कलाकृतियां मंदिर के लिए बनाई जा रही थीं। अब इस काम में तेज आई है। दिवाली बाद तीन दर्जन कारीगर अयोध्या जाएंगे और वहां काम करेंगे। इसके लिए विहिप ने पैसा देने की पेशकश की थी, लेकिन हम मंदिर निर्माण के लिए तन-मन से सहयोग करेंगे। मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद यहां से कलाकृतियां भेजी जाएंगी।
>
> **-आरपी सैनी, अध्यक्ष, स्टोन कारीगर एसोसिएशन, सिकंदरा**

यहां के पत्थर की खासियत : राजस्थान के दौसा जिले में स्थित सिकंदरा में लाल-बलुआ पत्थरों को काटकर जाली, झरोखे, गुंबद, छतरियां बनाई जाती हैं। इन पर कई तरह की आकृतियां भी उकेरी जाती हैं। यहां निर्मित पत्थर की विशेषता यह है कि इसपर तापमान का कोई असर नहीं होता है। यहां के पत्थर पर उकेरी गई कलाकृति सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहती है।

बंशी पहाड़पुर के पत्थर से बनेंगी दो मंजिल : उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के भरतपुर में स्थित बंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर का चयन विहिप नेता अशोक सिंघल और आचार्य गिरिराज किशोर ने किया था। करीब पच्चीस साल हो गए हैं, तब से पत्थर तराशे जा रहे हैं। यह काम बीच में बंद भी हुआ था। विहिप की भरतपुर इकाई के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा और वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ फौजदार ने बताया कि यहां से हजारों टन पत्थर अयोध्या पहुंच चुका है। अब एक बार फिर पत्थर निकालने के काम में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल के 70 पिलर और दीवारें बंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर से ही तैयार होंगी। इसी पत्थर से रंग मंडप, नृत्य मंडप और विश्राम स्थल का निर्माण होगा।

प्रशासन की पैनी नजर : भरतपुर के जिला कलेक्टर जोगाराम और दौसा जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी निरंतर विहिप की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इनका प्रयास है कि दोनों स्थानों पर तैयार हो रहे पत्थर तराशने के काम से कहीं किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों ही जिला कलेक्टर सरकार को नियमित रिपोर्ट भेज रहे हैं।

कमलेश हत्याकांड का एक और साजिशकर्ता गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के तार गुजरात सहित कई राज्यों से जुड़े हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने नागपुर में हत्याकांड की साजिश से जुड़े अन्य आरोपित सैय्यद आसिम अली (29) को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस की टीम आसिम को तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है। यहां उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। बताया गया है कि आसिम कमलेश हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता राशिद अहमद खुर्शीद अहमद पठान के लगातार संपर्क में था और कमलेश की हत्या के बाद राशिद ने आसिम को फोन कर इसकी जानकारी भी दी थी।

उल्लेखनीय है कि गुजरात एटीएस ने सूरत से कमलेश हत्याकांड के साजिशकर्ता मौलाना मोहसिन शेख सलीम (24), फैजान (21) व राशिद अहमद खुर्शीद अहमद पठान (23) को पकड़ा था। नागपुर में जिनगाबाई टकली निवासी आसिम तीनों आरोपितों के लगातार संपर्क में था। बताया गया कि आसिम के बारे में सूचना मिलने पर महाराष्ट्र एटीएस उसके बारे में छानबीन कर रही थी और रविवार को आसिम के नागपुर स्थित घर पर छापा भी मारा गया था। आसिम से हुई शुरुआती पूछताछ में कमलेश हत्याकांड की साजिश में उसकी अहम भूमिका सामने आई है। महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार को आरोपित आसिम को नागपुर कोर्ट में पेश किया। यूपी एटीएस ने कोर्ट से उसकी तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। आसिम से पूछताछ में कई अहम राज सामने आएंगे। अब तक कमलेश हत्याकांड में कुल चार साजिशकर्ताओं की भूमिका सामने आ चुकी है।

कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रचने वाले तीनों आरोपितों को लखनऊ पुलिस 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सोमवार को राजधानी पहुंची। अहमदाबाद से तीनों को फ्लाइट से यहां लाया गया। सोमवार को पूरे दिन आरोपित मौलाना शेख सलीम, फैजान और राशिद अहमद पठान को गुप्त स्थान पर रखा गया, जहां उनसे लखनऊ पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान आरोपितों ने कहा कि 2015 में उन्होंने कमलेश तिवारी की ओर से दिए गए विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था। तब से वह कमलेश की हत्या की साजिश रच रहे थे। सभी आरोपित एक दूसरे के परिचित थे। आरोपित इस बात की कोशिश भी कर रहे थे कि किसी तरह कमलेश सूरत आ जाएं। लंबे समय तक जब कमलेश के सूरत आने की कोई संभावना नहीं दिखी तो मौलाना शेख सलीम ने नाराजगी जताते हुए काम में देरी होने की बात कही थी। इसके बाद अशफाक और मोइनुद्दीन तैयार हो गए थे।

हिंदुवादी नेता के हत्यारोपितों के सात मददगार हिरासत में लिए गए

जागरण संवाददाता, बरेली

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के हत्यारोपितों शेख अशफाक हुसैन और पठान मोईनुद्दीन अहमद और उनके मददगारों की तलाश में बरेली मंडल में एसटीएफ व एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर से सात युवकों को हिरासत में लिया गया है। एक तरह से अब यह साफ हो गया है कि वारदात के बाद हत्यारोपित बरेली मंडल में ही थे। इन सात लोगों की मदद से लोकेशन बदलते रहे। रविवार को नेपाल भागने की कोशिश भी की थी, मगर सफलता नहीं मिली। दोनों हत्यारोपितों की सीसीटीवी फुटेज भी शाहजहांपुर में मिल गई है।

शुक्रवार को लखनऊ में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपित बरेली की ओर भागे। इसकी जानकारी टीमों को मिल चुकी थी। सर्विलांस के जरिये पता चला कि दोनों आरोपित बरेली, पीलीभीत व शाहजहांपुर में कुछ लोगों के संपर्क में थे। इसके बाद रविवार रात से लेकर सोमवार दोपहर तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें बरेली से पांच व पीलीभीत से एक युवक को पकड़ा गया, शाहजहांपुर से एक कार चालक को हिरासत में लिया गया।

शाहजहांपुर स्टेशन रोड पर पैदल जाते दिखे हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के हत्यारोपित। वीडियो ग्रैब

दोनों हत्यारोपित रुके थे बरेली में, युवकों ने की पूरी व्यवस्था : शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि शुक्रवार रात को दोनों हत्यारोपित बरेली आकर रुके थे। इन पांचों युवकों ने उनके रुकने, खाने-पीने का इंतजाम कराया। पीलीभीत के शेरपुर कला गांव से जिस युवक को पकड़ा गया, वह भी फोन पर लगातार संपर्क में बना हुआ था। शाहजहांपुर में जिस इनोवा कार चालक को पकड़ा गया, वह दोनों हत्यारोपितों को रविवार को पलिया (लखीमपुर खीरी) से रेलवे स्टेशन तक लेकर आया था।

रेलवे स्टेशन के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों: रविवार रात को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास लगे एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों हत्यारोपित पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटीएस व एसटीएफ टीम ने सोमवार तड़के से दोपहर तक शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के आसपास कई होटलों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक होटल के कैमरे में दोनों हत्यारोपित दिख गए। होटल मालिक व अन्य कई लोगों से पूछताछ हुई तो एक इनोवा कार चालक का नंबर मिला। उसे खुटार के पास एक जगह से पकड़ा गया।

नेपाल सीमा के करीब पहुंच चुके थे दोनों आरोपित : कार चालक को हिरासत में लेने के बाद पता चला है कि रविवार को दोनों आरोपित पलिया में मिले थे। वहीं से दोनों ने कार नेपाल सीमा तक ले जाने के लिए बुक की। वहां तक पहुंचते-पहुंचते शाम के सात बज चुके थे, इसलिए सीमा बंद हो गई। इस पर कार चालक उन दोनों को लेकर रात में शाहजहांपुर तक आया और उतार दिया। रात बारह बजे दोनों स्टेशन के पास पैदल गुजर रहे थे, जिसकी फुटेज कैमरे में कैद हो गई। शाहजहांपुर से दोनों आरोपित कहां गए, इस बाबत टीमें पता करने में जुटी हैं।

पूछताछ कर लौटी एसआइटी हिरासत में रहेंगे मौलाना

जासं, बिजनौर : हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या में नामजद मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम से पूछताछ के बाद एसआइटी की टीम लखनऊ लौट गई। फिलहाल दोनों आरोपितों को बिजनौर पुलिस की हिरासत में रखा गया है। लखनऊ से निर्देश मिलने पर अग्रिम कार्रवाई होगी। सोमवार को एसआइटी की पांच सदस्यीय टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई। टीम को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगने की बात कही जा रही है। रविवार को लखनऊ से पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में दोनों आरोपितों को गोपनीय स्थान पर ले जाकर पूछताछ की गई। मौलाना और मुफ्ती से पूछा गया कि कमलेश तिवारी के सिर पर इनाम रखने के पीछे किसका हाथ था। सूत्रों का कहना है कि एसआइटी ने पूछताछ के दौरान स्थानीय पुलिस को भी दूर रखा। दोनों मौलाना को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया।

हत्यारों पर ढाई-ढाई लाख का इनाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर फरार दोनों आरोपित शेख अशफाक हुसैन व पठान मोईनुद्दीन अहमद पर डीजीपी ओपी सिंह ने ढाई-ढाई लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। अब तक पुलिस दोनों हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस हत्याकांड की छानबीन में जिस तरह वारदात के पीछे गहरी साजिश सामने आ रही है, उससे घटना में किसी आतंकी संगठन की भूमिका होने की आशंका भी बढ़ती जा रही है।

डीजीपी का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर एसआइटी जांच कर रही है और किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। गुजरात, हरियाणा, अंबाला व उत्तर प्रदेश सभी जगहों के मॉड्यूल देखे जा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाई जा रही है। हत्या में नामजद आरोपित बिजनौर के दोनों मौलानाओं से भी कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपितों के हर कनेक्शन की गहनता से छानबीन कर रही है। डीजीपी का दावा है कि पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिनकी मदद से जल्द फरार हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

नया रास्ता

अकाल तख्त की बैठक के बाद सरकार ने की अलग स्टेज की घोषणा, एक ही स्टेज पर आएंगे पीएम, राष्ट्रपति, वर्तमान व पूर्व मुख्यमंत्री

सरकार और एसजीपीसी की अलग-अलग होगी स्टेज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को लेकर अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पर पांच सिंह साहिबान की बैठक के बाद पंजाब सरकार ने कहा है कि वह अपना अलग स्टेज लगाएगी। दूसरी तरफ अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि मुख्य स्टेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की होगी और कार्यक्रम का संचालन भी एसजीपीसी करेगी। उन्होंने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को रद कर दिया है जिसमें सरकार ने कहा था कि वह स्टेज तैयार करके देगी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम उसी स्टेज पर आयोजित किए जाएं।

दरअसल स्टेज पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को बिठाने को लेकर पंजाब सरकार को ऐतराज था। उसका कहना था कि किसी एक सियासी पार्टी के प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री को अगर स्टेज पर बिठाया जाएगा तो अन्य पार्टियों के प्रधान को भी बिठाना पड़ेगा। बादल स्टेज पर बैठेंगे या नहीं, इसको लेकर फैसला पांच सिंह साहिबान की मीटिंग में होना था। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बीच का रास्ता अपनाते हुए मुख्य समारोह जहां एसजीपीसी को सौंपकर बादल को स्टेज पर बिठाने का रास्ता साफ कर दिया वहीं, पंजाब सरकार को अलग से स्टेज लगाने की भी इजाजत दे दी।

अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब में सिंह साहिबान की बैठक बाद अरदास करते हुए (बाएं से दाएं) ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर, बलविंदर सिंह जौड़ासंघा, जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, ज्ञानी रघबीर सिंह, बाबा बलबीर सिंह, एसजीपीसी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोगोंवाल, अजायब सिंह अभियासी व अन्य।

जत्थेदार ने कहा कि सियासी पार्टियां भी अपनी स्टेज लगा सकती हैं, लेकिन यहां से कोई सियासी बात नहीं होगी, केवल गुरु नानक साहिब की शिक्षाओं आदि पर बात होगी। मुख्य समारोह की स्टेज पर धार्मिक शख्सियतें, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि, एसजीपीसी के प्रधान, पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। इस स्टेज पर भी कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। सिर्फ गुरु साहिब की शिक्षाओं और जीवन के संबंध में संदेश व चर्चाएं होंगी। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि 11-12 नवंबर को आयोजित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रम गुरुद्वारा बेर साहिब की ओर से बनाई गई एसजीपीसी की स्टेज पर संयुक्त रूप में होंगे। इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी नेता पहुंच सकता है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बनाई गई दो सदस्यीय कमेटी में शामिल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा दिए आदेश का पालन किया जाएगा। पंजाब सरकार की स्टेज पर राजनीतिक बातें नहीं होंगी, केवल गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर बात होगी। 12 नवंबर के कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली प्रबंधक कमेटी बनाएगी।

उत्तर प्रदेश में 650 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद

जागरण संवाददाता, बांदा

उप्र के बांदा एसपी दफ्तर के पास 650 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक की बरामदगी ने जिले में सनसनी फैला दी। सोमवार सुबह एक स्कार्पियो से 13 बोरियों में बड़ी मात्रा में विस्फोटक देख पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। विशेषज्ञों के मुताबिक इतने अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से तीन-चार किलोमीटर का इलाका तबाह हो सकता है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है। एसपी गणेश साहा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया है।

सुबह छह बजे सिविल लाइन चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी महोबा की तरफ से स्कार्पियो आते दिखी। रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी की गति तेज कर दी। कुछ दूर भागने के बाद कार पेड़ से टकराकर रुक गई। उसमें सवार तीन लोग उतरकर भाग निकले। पुलिस को वाहन तलाशी में बोरियों में भरी विस्फोटक सामग्री (अमोनियम नाइट्रेट) मिली। बोरियों का वजन 50-50 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि स्कार्पियो महोबा के विस्फोटक माफिया राकेश द्विवेदी की है। एसपी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है।

आतंकी धमाकों में इस्तेमाल : 27 अक्टूबर 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान पटना में पीएम मोदी की सभा में अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया गया था। बोध गया और मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों में भी इसका इस्तेमाल किया गया।

> विस्फोटक सामग्री बरामद होने की यह बड़ी घटना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। बांदा व महोबा एसपी को आरोपितों की गिरफ्तारी 24 घंटे में करने के निर्देश दिए गए हैं।
>
> **-दीपक कुमार सिंह, डीआइजी चित्रकूट धाम रेंज**

35 हजार एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) तैनात हैं मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर में। इस समय में केंद्र के निर्देश पर पूरे राज्य में पांच हजार एसपीओ की भर्ती भी चल रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 22 अक्टूबर 2019

राजनाथ की पाक को चेतावनी, आतंक को शह देने के होंगे गंभीर परिणाम

दो टूक ▶ गुलाम कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के अगले दिन लेह पहुंचे रक्षा मंत्री

चीन सीमा पर सैन्य दृष्टि से बेहद अहम पुल देश को किया समर्पित

राज्य ब्यूरो, जम्मू

गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के अगले दिन सोमवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंक को शह देना बंद नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजनाथ के साथ सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे।

लेह पहुंचे राजनाथ सिंह ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास श्योक नदी पर सैन्य दृष्टि से बेहद अहम 1400 फीट लंबे पुल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कर्नल छिवांग रिनचिन पुल को देश को समर्पित करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। इस पुल के बनने से क्षेत्र में हर मौसम में न सिर्फ पूरा साल सड़क संपर्क बना रहेगा अपितु सीमांत क्षेत्रों के लिए यह पुल रणनीतिक रूप से भी अतिमहत्वपूर्ण होगा। पुल का नाम लद्दाख के शेर कहे जाने वाले कर्नल छिवांग रिनचिन के नाम पर रखा गया है। कर्नल रिनचिन ने दो बार महावीर चक्र जीता है।

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास श्योक नदी पर बना पुल। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। जागरण

हमारे सैनिक गोलाबारी की शुरुआत नहीं करते : रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, भारत को अस्थिर बनाने के लिए आतंकवाद को शह देने के साथ सीमा पर गोलाबारी कर रहा है। हमारे सैनिक कभी गोलाबारी की शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन अगर सीमा पार से यह सब नहीं रुका तो पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा।

कश्मीर आंतरिक मामला, चीन ने भी नहीं किया जिक्र : रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई मुलाकात पर राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनफिंग ने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। इसके साथ आतंकवाद के खिलाफ चीन का हालिया बयान भी बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। सीमा को लेकर दोनों देशों में मतभिन्नता है, लेकिन इस मुद्दे से बड़ी गंभीरता व जिम्मेदारी से निपटा जा रहा है।

सियाचिन पर्यटकों के लिए खुला

रक्षा मंत्री ने कहा कि लद्दाख में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। बेहतर सड़क संपर्क से लद्दाख में और अधिक पर्यटक आएंगे। अब सियाचिन क्षेत्र पर्यटकों के लिए खुला है।

सुरक्षा हालात का लिया जायजा

लद्दाख पहुंचे रक्षामंत्री के साथ पुल बनाने वाले सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, सेना की उत्तरी कमान और लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली चौदह कोर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की भारी गोलाबारी से उपजे हालात के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के बारे में भी जानकारी ली।

सुधर जाए पाक वरना गुलाम कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे : सत्यपाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में आतंकी कैंप और आतंकवाद को बंद करने की चेतावनी दी है। सोमवार को उन्होंने कहा कि अगर वह बाज नहीं आया तो हम गुलाम कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे। उन्होंने कश्मीर के युवाओं को बंदूक और बर्बादी का रास्ता छोड़ राज्य की बेहतरी के लिए काम करने को प्रेरित करते हुए कहा कि एक नवंबर से नया कश्मीर होगा। राज्यपाल सोमवार को श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र जेवन में राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि उेने पहुंचे थे।

गुलाम कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के लांचिंग पैड तबाह किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम आतंकी कैंपों को बर्बाद कर देंगे। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हम अदंर तक जाएंगे। हम सभी कैंप बर्बाद कर देंगे। हम अंदर घुसकर मारेंगे। राज्यपाल ने कहा कि जंग एक बुरी चीज है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं रोका तो हमारा जवाब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा।

श्रीनगर में सोमवार को पुलिस शहीदी दिवस पर आयोजन में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर दो टूक चेतावनी दी। जागरण

उन्होंने राज्य में हालात के सामान्य होने का दावा करते हुए कहा कि पहली नवंबर से जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कश्मीर में नौजवानों को हिंसा और ंदूक के रास्ते से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि मैं इन लड़कों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस रास्ते से, बंदूक से क्या प्राप्त किया है... अब उन्हें अपने प्रदेश की बागडोर को संभालना चाहिए। उन्होंने घाटी में हालात पूरी तरह सामान्य होने तक प्रीपेड मोबाइल व इंटरनेट सेवा बंद रखे जाने के संकेत भी दिए।

हताश हिजबुल मुजाहिदीन ने रियाज को हटा नवीद को बनाया ऑपरेशनल कमांडर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में सुरक्षाबलों के दबाव के आगे आतंकी संगठनों से लेकर पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और सेना हताश हो चुकी है। हिजबुल मुजाहिदीन ने दक्षिण कश्मीर में अपने ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायकू उर्फ जुबैर उल इस्लाम को हटा दिया है। सुरक्षाबलों ने उस पर 12 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। ऐसे में अब उसके स्थान पर नवीद बाबू उर्फ बाबर आजम को कमान सौंपी गई है। हालांकि नवीद भी सुरक्षाबलों की हिट लिस्ट में है।

सूत्रों ने बताया कि पाक सेना ने हिजबुल को कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी लाने और दक्षिण कश्मीर में खास जगहों पर हमला करने के लिए कहा था, लेकिन रियाज नाकाम रहा। एक अन्य सूचना के मुताबिक रियाज को हिजबुल पूरे कश्मीर की कमान सौंपने जा रहा है। इसलिए दक्षिण कश्मीर का जिम्मा नवीद को सौंपा है।

नवीद ने बाहरी लोगों को बनाया है निशाना : सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2017 में पुलिस की नौकरी छोड़ आतंकी बने नवीद ने सरहद पार आकाओं के हुक्म पर बाहरी लोगों को निशाना बनाया है। हालांकि वह रियाज की तरह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पांच साल की पुलिस की नौकरी और आतंकरोधी अभियानों में हिस्सा लेने के कारण वह पुलिस के तौर-तरीके अच्छी तरह समझता है।

सात साल से आतंकी संगठन में सक्रिय है रियाज : अवंतीपोरा का रहने वाला रियाज करीब सात साल से आतंकी संगठन में सक्रिय है। आतंकी बनने से पहले वह स्कूल में अध्यापक था। हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन ने रियाज को दक्षिण कश्मीर में नए लड़कों की भर्ती का जिम्मा सौंपा था। सूत्रों ने बताया कि रियाज दो माह में तीन बार अपने गांव में आया और अवंतीपोरा और उससे सटी कुछ मस्जिदों में भाषण देकर नौजवानों को बंदूक उठाने के लिए उकसा रहा था।

सलाहुद्दीन ने भी लगाए कई चक्कर : पाकिस्तान सेना के निर्देश के बाद सलाहुद्दीन ने कुछ दिनों में रावलपिंडी से गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के कई चक्कर लगाए हैं। इसके अलावा उड़ी, नौगाम और मच्छल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार गुलाम कश्मीर में स्थित हिजबुल के लांचिंग पैड पर भी गया है।

सिर्फ डोडा व किश्तवाड़ रेंज में हैं आतंकी : सिंह

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू संभाग के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आइजीपी) मुकेश सिंह का कहना है कि मौजूदा समय में डोडा, किश्तवाड़ रेंज में कुछ आतंकी शेष हैं। इनके खात्मे के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। जल्द ही इन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा। आइजीपी ने राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू के शांतिपूर्ण माहौल को खराब किया जाए। लेकिन सुरक्षा बल पड़ोसी देश के नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। सुरक्षाकर्मी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

गुलाम कश्मीर में छह लांचिंग पैड पर जमा थे 100 आतंकी

भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में गुलाम कश्मीर की नीलम घाटी में ध्वस्त मकान। एएफपी

आइएएनएस, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार गुलाम कश्मीर में छह लांचिंग पैड पर लगभग 100 आतंकी जमा थे। ये आतंकी कश्मीर में घुसपैठ कर हिंसा फैलाने के लिए मौका तलाश रहे थे, लेकिन शनिवार रात को पाक सेना की गोलाबारी के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में छह में से चार लांचिंग पैड तबाह हो गए हैं।

वहीं, कई घुसपैठिये मारे गए और जो जिंदा बचे वे निकटवर्ती बस्तियों में भाग गए। गौरतलब है कि शनिवार रात को पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत टंगडार सेक्टर में आतंकियों के एक दल को भारतीय इलाके में घुसपैठ कराने का प्रयास किया था। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नागरिक बस्तियों और सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान सेना की गोलाबारी का जवाब देते हुए दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए और एक ग्रामीण भी मारा गया। इसके बाद भारतीय सेना ने उन जगहों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तानी सेना गोलाबारी कर रही थी। भारतीय सेना ने टंगडार सेक्टर के सामने गुलाम कश्मीर में जोरा, एथमुकाम और कुंडलशाही में बने लांचिग पैड पर भी गोलाबारी की। संबंधित सैन्य सूत्रों की मानें तो इन लांचिंग पैड पर 100 आतंकी जमा थे। भारतीय कार्रवाई से उनका घुसपैठ का इरादा नाकाम हो गया है। वहां छह लांचिंग पैड थे, इनमें से चार तबाह हो चुके हैं। रविवार को थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि भारतीय सेना की कार्रवाई में छह से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और चार आतंकी कैंप तबाह हुए है। टंगडार के अलावा केरन, मच्छल और नौगाम सेक्टर में आतंकी लांचिंग पैड पर मौजूद हैं।

एलओसी के करीब तोपों को तैनात कर रहा पाक

गगन कोहली, राजौरी

कश्मीर में उड़ी के तंगडार सेक्टर में शनिवार की रात को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी तोपों को एलओसी के करीब तैनात करने का काम शुरू कर दिया है। टैंकों को भी सीमा की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोमवार को ही उसने एलओसी पर अपने जवानों की संख्या को बढ़ा दिया है।

भारतीय सेना द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के बाद पाक सेना व पाक की खुफिया एजेंसी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इसलिए वह किसी बड़ी नापाक हरकत करने की तैयारी में जुटी गई है। सूत्रों का कहना है कि पाक सेना सैन्य शिविर समेत रिहायशी क्षेत्र को निशाना बनाकर गोलाबारी कर सकती है।

सूत्रों का कहना है कि पाक सेना के उच्च अधिकारियों और आइएसआइ के अधिकारियों ने एलओसी का दौरा किया है। इन्होंने एलओसी पर तैनात जवानों व अधिकारियों के साथ काफी लंबी बातचीत की और कई दिशा निर्देश जारी किए।

अंग्रेजी मीडिया ने नहीं पेश की अनु. 370 पर निष्पक्ष तस्वीर : जयशंकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब वह अमेरिका यात्रा पर गए थे तब अन्य लोगों से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले उदारवादी मीडिया ने कहीं ज्यादा कठिन चुनौती पेश की थी क्योंकि उसकी इस बारे में पूर्वधारणा थी और उसने निष्पक्ष तस्वीर पेश नहीं की।

अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, 'यह बदलाव हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन दुनियाभर में इसके बारे में उत्सुकता थी क्योंकि अलग-अलग लोगों के इसके बारे में अपने-अपने विचार थे और हमारे पड़ोसियों ने इसके बारे में थोड़ा हो-हल्ला मचा दिया था।' विदेश मंत्री ने कहा कि यह कदम उठाने के बाद भारत की प्राथमिकता विभिन्न देशों की सरकारों के साथ बातचीत की थी ताकि बदलाव के बारे में उन्हें समझाया जा सके।

उन्होंने कहा, 'इसलिए, जब मैं सितंबर में अमेरिका गया तो यह कदम उठाए जाने के छह हफ्ते बीत चुके थे, हम ठीकठाक प्रगति कर चुके थे। मुझे लगता है मीडिया के साथ कहीं ज्यादा कठिन चुनौती थी, विशेषकर अंग्रेजी बोलने वाले उदारवादी मीडिया के साथ, क्योंकि आंशिक रूप से वे इसके बारे में बहुत ज्यादा

कहा, मीडिया के इस वर्ग ने पेश की कहीं ज्यादा कठिन चुनौती

सैद्धांतिक थे, इस मसले पर उनकी बेहद कठोर पूर्वधारणा थी। मेरे विचार से... कई तरीकों से उन्होंने निष्पक्ष तस्वीर पेश नहीं की। शायद वे निष्पक्ष तस्वीर को पचा नहीं पाए।' मालूम हो कि विदेश मंत्री सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में एक हफ्ते से अधिक समय की अमेरिका यात्रा पर थे। जयशंकर ने आगे कहा कि इनमें से ज्यादातर सामूहिक धारणाओं को सही ठहराने में लगे थे जो मीडिया कवरेज करने वालों को आसानी से मिल जाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा, 'मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो यह जानकारी पाकर आश्चर्यचकित थे कि संविधान का जो प्रावधान बदला गया वह अस्थायी था। इसकी वजह यह थी कि मीडिया ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा।'

जयशंकर ने बताया, 'अनुच्छेद 370 ने कश्मीर में कारोबार की संभावनाएं कम और लागत बढ़ा दी थी जिसका मतलब था कम विकास। ऐसी ज्यादातर चीजों के बारे में लोग प्रेस में नहीं पढ़ रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे थे... यह मेरे अनुभव (अमेरिका में) का कुल निचोड़ था।'

दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है पाक : राम माधव

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान को आतंकवाद का 'केंद्र' बताते हुए भाजपा महासचिव राम माधव ने सोमवार को कहा कि पड़ोसी देश न सिर्फ भारत की समस्या है, बल्कि अब वह पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को बाध्य करना चाहिए।

दोनों देशों के संबंधों व संवाद के सवाल पर माधव ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैत्री संबंध रखने में निश्चित रूप से खुशी होगी, लेकिन सबसे पहले उसे सीमापार आतंकवाद के प्रमुख मुद्दे पर ध्यान देना होगा। अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम की तरफ से आयोजित सम्मेलन में माधव ने कहा, 'आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को अब सिर्फ भारत ही मुश्किल संबंधों के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वह दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है।'

भाजपा के जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर पर पाक ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे वह वैश्विक समुदाय के सामने अलग-थलग पड़ गया है। एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में माधव ने कहा कि वह काली सूची में आने से बाल-बाल बचा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगले साल फरवरी में क्या होगा।

अमेरिका के मुकाबले चीन से भारत के बेहतर संबंध

आइएएनएस के अनुसार, अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम के दौरान भाजपा महासचिव राम माधव व पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस के बीच जमकर तकरार हुई। माधव ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत डंपिंग मार्केट नहीं है। सरकार घरेलू बाजार व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये देश को व्यापार का केंद्र बनाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि रक्षा, संचार, ऊर्जा व स्वास्थ्य सेवाएं व्यापार के प्रमुख क्षेत्र हैं। आज हमारे पास व्यापारिक संबंधों के लिए उत्कृष्ट दिमाग और संसाधन उपलब्ध हैं। चीन भारत का निकटतम पड़ोसी है और हमें क्षेत्रीय या वैश्विक दबाव से इतर साझेदारी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। माधव ने यह कहते हुए कई को आश्चर्य में डाल दिया कि आज भारत का अमेरिका के मुकाबले चीन के साथ बेहतर संबंध हैं। इस पर राइस ने आगाह करते हुए कहा कि चीन भारत के साथ गुरिल्ला युद्ध कर रहा है। यह हर कोई देख रहा है, लेकिन भारत कई तरीकों से चीन के साथ जुड़ना चाहता है। भारत को विकास के सभी क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि विकास और विकास से संबंधित बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए

नई दिल्ली में सोमवार को अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते भाजपा महासचिव राम माधव। प्रेट्र

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का कैसे इस्तेमाल किया गया।

इस पर माधव ने कहा, 'अमेरिका को समझना चाहिए कि दो देशों के बीच बड़ा व्यापार घाटा नहीं हो सकता। इसे संतुलित करना होगा। भारत और अमेरिका के व्यापारिक साझेदारी के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। लेकिन, अमेरिका को यह समझना होगा कि हम डंपिंग मार्केट नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारी आबादी बड़ी है, हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते।'

तत्काल तीन तलाक रोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

नई दिल्ली, आइएएनएस : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने तत्काल तीन तलाक को अवैध और अपराध करार देने वाले 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अधिशासी कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को तीन तलाक को दंडनीय अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। कमेटी के सदस्य कमल फारुकी ने बताया कि संसद में पारित किया गया मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम-2019 असंवैधानिक है। चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। इस कानून के चलते तीन तलाक बोलना अपराध माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून मनमाना, अवांछित और गलत तरीके से तीन तलाक को अपराध करार देता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन होता है। इससे एक नागरिक की निजता का उल्लंघन होता है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर की रिट याचिका

नए कानून के तहत तलाक-ए-बिद्दत होने की जानकारी पति या पत्नी की मर्जी के बगैर पत्नी से संबंधित कोई भी व्यक्ति दे सकता है। इसमें पत्नी के रक्त संबंधी से लेकर शादी से जुड़े रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस कानून के जरिए शादी से जुड़ी बेहद आंतरिक बातें भी सार्वजनिक हो जाती हैं। लिहाजा, इससे प्रतिष्ठा और निजता के अधिकारों को भी क्षति पहुंचती है। याचिका में कहा गया है कि विगत 31 जुलाई को केंद्र की ओर से पारित किया गया था। इस कानून के जरिए तत्काल तीन तलाक देने वाला शौहर तीन साल की कैद का हकदार होगा।

अक्टूबर की शुरुआत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दारुल उलूम नदवातुल उलमा में एक बैठक में यह फैसला किया गया कि बोर्ड इस कानून के खिलाफ रिट याचिका दायर करेगा। बोर्ड की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि तत्काल तीन तलाक पर संसद से पास हुआ कानून शरीयत में हस्तक्षेप है।

करतारपुर कॉरिडोर

प्रधानमंत्री मोदी आठ नवंबर को करेंगे कॉरिडोर व टर्मिनल का उद्घाटन, भारत 31 अक्टूबर तक पूरा कर लेगा टर्मिनल का काम

भारत आज लगाएगा 300 फीट ऊंचा झंडा

जागरण संवाददाता, कलानौर (गुरदासपुर)

गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बनाए जा रहे कॉरिडोर के टर्मिनल पर भारत 300 फीट ऊंचा तिरंगा लहराएगा। इसे देख पाकिस्तान भी इतना ही ऊंचा अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाएगा।

भारत की ओर टर्मिनल के निर्माण में जुटी कंपनी मंगलवार को टर्मिनल परिसर में 300 फीट ऊंचा पोल खड़ा करना शुरू कर देगी। सोमवार को पोल की रंगाई करने और इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाने का काम पूरा किया गया। भारत को देख पाकिस्तान भी अपने टर्मिनल पर इतना ही ऊंचा झंडा लगाने के लिए पोल तैयार कर रहा है। डिफेंस धुस्सी के पास बने पाकिस्तान के टर्मिनल पर श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के दस्तावेज जांचे जाएंगे। पाकिस्तान ने अधिकतर काम पूरा कर लिया है। भारत भी 31 अक्टूबर तक टर्मिनल का काम पूरा कर लेगा।

गौरतलब है कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरा बाबा नानक में कॉरिडोर और टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उपनिदेशक सुखदेव सिंह का कहना है कि तिरंगा लगाने के लिए पोल का काम पूरा कर लिया गया है। मंगलवार को इसे लगाया जाएगा।

गुरदासपुर के कस्बा डेरा बाबा नानक स्थित टर्मिनल परिसर में 300 फीट ऊंचे पोल का सोमवार को रंग-रोगन किया गया। इसके ऊपर अशोक स्तंभ भी लगा दिया गया है। मंगलवार को इस पोल को खड़ा कर दिया जाएगा। जागरण

करतारपुर कॉरिडोर से रोजाना डेढ़ करोड़ कमाएगा पाकिस्तान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : करतारपुर कॉरिडोर पर हर श्रद्धालु से 20 डॉलर का शुल्क आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। यही कारण है कि भारत के बार-बार कहने के बावजूद वह शुल्क छोड़ने के तैयार नहीं है। अनुमान है कि हर श्रद्धालु से 20 डॉलर की फीस से पाकिस्तानी खजाने में हर साल 561 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा होगा। दरअसल, पाकिस्तान ने एक दिन में 5,000 श्रद्धालुओं के आने की अनुमति दी है। पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत 156 रुपये है। 20 डॉलर प्रति श्रद्धालु के हिसाब से पाकिस्तान को रोजाना एक लाख डॉलर यानी 1.56 करोड़ रुपये (भारतीय मुद्रा में करीब 71 लाख रुपये) की कमाई होगी। यह रकम एक हफ्ते के हिसाब से 10.92 करोड़ रुपये और एक महीने की कमाई 46.80 करोड़ रुपये बनती है। एक साल में यह कमाई 5,61,60,00,000 रुपये यानी साढ़े पांच अरब रुपये से ज्यादा की बनती है।

टेरर फंडिंग : एक समाजसेवी भी सदाकत का है करीबी

जासं, बरेली

टेरर फंडिंग के आरोपित सदाकत की कुंडली खंगालने में जुटी टीमों को उसके करीबियों के बारे में भी कई जानकारियां मिली हैं। उसका एक दोस्त समाजसेवी बनकर अधिकारियों के नजदीकियां बढ़ाता रहा है। उनके साथ फोटो खिंचवाता। जून में सदाकत ने अपने फेसबुक वॉल पर उस कथित समाजसेवी का फोटो अधिकारियों संग फोटो अपलोड किया था। बीते दिनों लखीमपुर में जब टेरर फंडिंग के चार आरोपित गिरफ्तार हुए और पूछताछ के बाद सदाकत का नाम सामने आया तो वह कथित समाजसेवी भी गायब हो गया। किला क्षेत्र में उसका घर है मगर कई दिन से वहां नहीं है। उसके सदाकत से करीबी संबंधों की जानकारी होने पर खुफिया टीम लोकेशन ट्रेस करने में लगी हैं।

फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में भी कई नेता व अधिकारी शामिल : सदाकात के इस करीबी दोस्त ने एक सामाजिक संस्था बना ली थी,

फेसबुक पर अफसरों के साथ दिख रहा कथित समाजसेवी दोस्त

खुफिया टीम उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी

जिसके माध्यम से अधिकारियों के बीच उठता-बैठता। आइपीएस अधिकारियों, एसपी, सीओ व कई इंस्पेक्टर उसे तवज्जो देते दिखते थे। उन्हीं के साथ फोटो भी खिंचवाता था। उसके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन आदि के विवाद, मुकदमों में वह मध्यस्थता करता था। अधिकारियों से मामले निपटवाता था। सदाकत की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में भी कई नेता व अधिकारी शामिल हैं।

बरेली के परतापुर चौधरी गांव में रहने वाला टेरर फंडिंग का आरोपित सदाकत फरार है। एटीएस उसकी तलाश में जुटी हुई। पिछले सप्ताह उसने लखीमपुर खीरी की कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी थी मगर पहुंचा नहीं। पीछे लगी एटीएस को उसकी लोकेशन मिल रही है लेकिन वह बार-बार जगह बदल रहा है।

162 करोड़ की राशि प्रदान की है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने। इसमें से 44 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मिले हैं।

पहले चूके राज्यों में अब हो रही जमकर बारिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मानसून अब पूर्वोत्तर व दक्षिणी राज्यों में जमकर बरस रहा
- टमाटर और प्याज की आपूर्ति के बाधित होने की आशंका

दक्षिण पश्चिम मानसून की बरसात से चूके क्षेत्रों में अब दूसरे चरण के मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। इससे पूर्वोत्तर समेत दक्षिणी राज्यों में सामान्य से अधिक बरसात हो रही है। पूर्वोत्तर मानसून की सक्रियता से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में बरसात होने से उत्तरी राज्यों में प्याज और टमाटर की आपूर्ति के प्रभावित होने का आशंका बढ़ गई है।

इन राज्यों में पिछले कई सालों से मानसून के दूसरे चरण में बारिश सामान्य से बहुत कम होती रही है। इसके चलते दक्षिणी राज्यों में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया था। इससे पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। भारतीय मौसम विभाग के जारी बुलेटिन के मुताबिक तमिलनाडु से लगी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने लगा है। इसी तरह अरब सागर में भी चक्रवाती तूफान की स्थिति बनने से निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है।

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में मानसून सक्रिय होने से सोमवार को केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कोच्चि में कई इलाकों में यहां भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रेट्र

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर बारिश से मतदान में खलल पड़ गया। महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्र नाशिक और लासलगांव में खेतों से प्याज की निकासी रुक गई है। बरसात के चलते ही देश के उत्तरी राज्यों में प्याज की आपूर्ति पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। इसी तरह हैदराबाद से टमाटर की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। उत्तरी राज्यों में टमाटर और प्याज की आपूर्ति कम होने से कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिसे थामने के उपाय तो किए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बरसात के चलते स्थितियां विपरीत हो सकती हैं।

देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून अपने निर्धारित समय पर आया और जमकर बरसा। 15 अक्टूबर के आसपास विदा हो गया, लेकिन इस दौरान पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई थी। मौसम विभाग के जारी बुलेटिन के मुताबिक आने वाले चार-पांच दिनों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों के साथ अगले एक-दो दिनों के भीतर महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण क्षेत्र और गोवा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि पूर्वी राज्यों में ओडिशा और झारखंड में भी दिवाली से पहले अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।

सुरक्षा के लिए खतरा हैं दाबोलिम एयरपोर्ट के पास बनीं इमारतें

पणजी, आइएएनएस : नौसेना की औपचारिक सहमति के बिना दाबोलिम एयरपोर्ट के नजदीक बनीं इमारतें आइएनएस हंसा नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। साथ ही इससे यहां से संचालित होने वाले एयरपोर्ट और विमानों की सुरक्षा पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यह बात नौसेना ने अपने एक बयान में कही है।

अपने बयान में नौसेना ने यह भी कहा कि स्थानीय राजनेताओं ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 2015 की अधिसूचना को लागू करने पर जो आशंका जताई है वह निराधार है। इस अधिसूचना के तहत गोवा के मामले में दाबोलिम एयरपोर्ट के रनवे से 20 किमी के दायरे में निर्माण के लिए हवाईअड्डा संचालन प्राधिकरण से मंजूरी लेना आवश्यक है। बयान में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट इमारतें सुरक्षित उड़ान के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण एयरबेस की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हैं। इन इमारतों के निर्माण के दौरान नौसेना से एनओसी नहीं ली गई है।

बयान में कहा गया है कि इस मामले को गोवा की राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है और इसे उचित रूप से उनके समक्ष उठाया जा रहा है। दरअसल, पिछले सप्ताह राज्य

- नौसेना ने कहा, निर्माण के लिए नहीं ली गई जरूरी एनओसी

सरकार के परिवहन मंत्री मौवीन गोडिन्हो और पूर्व उपमुख्यमंत्री विजई सरदेसाई ने नौसेना पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। गोडिन्हो ने यह भी कहा था कि नौसेना से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना आसान नहीं है, क्योंकि नौसेना एन्क्लेव तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। उधर, नौसेना ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को एनओसी के लिए नौसेना एन्क्लेव आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन, पंचायत और नगरपालिका के माध्यम से एनओसी के आवेदन नौसेना को भेजे जाते हैं। ऐसे में नौसेना के क्षेत्रों में लगी पाबंदियां आवेदकों के लिए परेशानी नहीं बन सकती हैं। एनओसी का उद्देश्य प्रत्येक मामले की योग्यता की जांच करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निर्माण पर्यटकों, स्थानीय लोगों और उड़ान की सुरक्षा को खतरे में न डाले। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारी विभागों और नौसेना की मंगलवार को इस मुद्दे पर बैठक बुला सकते हैं।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए तीन अस्पतालों को स्वर्ण प्रमाणपत्र

नई दिल्ली, एएनआइ : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाइ) के तहत मरीजों की बेहतर देखभाल करने वाले तीन अस्पतालों को सरकार ने 'स्वर्ण प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया है। देश में यह पहली बार इस योजना के तहत अस्पतालों को यह प्रमाणपत्र दिया गया है।

इन अस्पतालों में अहमदाबाद के दो अस्पताल यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर और स्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपैडिक और हरियाणा का सिग्नस सुपर स्पेशिऐलिटी हॉस्पिटल शामिल है।

एबी-पीएमजेएवाई में हॉस्पिटल नेटवर्किंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस विभाग के महाप्रबंधक डॉ. जेएल मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले प्रमाणपत्र से संबंधित मानकों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए हमारी बहुत ठोस प्रणाली है। इस प्रमाणपत्र के लिए अब तक विभाग को सिर्फ चार आवेदन ही प्राप्त हुए थे। चौथे आवेदन की गहनता से जांच की जा रही है।

मीणा ने कहा कि यह सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की संस्कृति विकसित हो सके।

न्यूज गैलरी

गोवा में आवारा गाय-बैल खा रहे मांसाहारी भोजन : लोबो

पणजी : गोवा के मंत्री माइकल लोबो ने दावा किया है कि राज्य की गोशालाओं में लाए गए आवारा गाय-बैलों के मांसाहारी होने का पता चला है। इन पशुओं में यह आदत कचरे में फेंके गए बचे हुए चिकन और फ्राइड फिश खाने से पड़ी है। उत्तरी गोवा जिले के अर्पोरा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान लोबो ने कहा, 'हम कलंगुट क्षेत्र से 76 गाय-बैलों को गोशाला में लाए थे जहां उनकी देखभाल की जा रही है। हमें पता चला कि वे मांसाहारी हो गए हैं। वे घास नहीं खाते। वे न तो चना खाते हैं और न ही उन्हें दिया जाने वाला विशेष भोजन।' उन्होंने आगे कहा, 'हम हमेशा कहते हैं कि गाय-बैल शाकाहारी होते हैं। लेकिन कलंगुट से लाए गए गाय-बैल मांसाहारी हैं। अब वे (गोशाला संचालक) इस समस्या का सामना कर रहे हैं।' (प्रेट्र)

गश्त से लौट रहे वन रक्षक को बाघ ने बनाया निवाला

पौड़ी गढ़वाल : जिम कार्बेट नेशनल पार्क में गश्त से लौट रहे वन रक्षक को बाघ ने निवाला बना लिया। सोमवार को वनकर्मियों ने जंगल से वन रक्षक का क्षत-विक्षत शव बरामद किया। जुलाई में भी इसी रेंज में बाघ ने एक वनकर्मी को अपना निवाला बनाया था। यह घटना रविवार दोपहर की है। राजेश नेगी (47) अपने दो सहयोगियों के साथ पलेन रेंज में गश्त पर थे। वापसी में अचानक राजेश पर बाघ ने हमला कर दिया और उन्हें घसीटता हुआ जंगल के भीतर ले गया। हड़बड़ाए साथियों ने हवाई फायर कर बाघ को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे साथी को बचा नहीं पाए। (जासं)

उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 100 दुर्दांत अपराधी : योगी

नमन ▶ पुलिस स्मृति दिवस पर राज्य के शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि

- मुख्यमंत्री ने पांच शहीदों के परिवारीजन को सम्मानित भी किया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में 100 दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। प्रदेश में संगठित अपराधी जेल में हैं। योगी ने कुंभ मेला, लोकसभा चुनाव अन्य प्रमुख मौकों पर सुरक्षा-व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस की प्रशंसा की। हालांकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते योगी पुलिसकर्मियों के लिए किसी कल्याणकारी योजना की घोषणा नहीं कर सके। उन्होंने प्रदेश में शहीद हुए पांच पुलिसकर्मियों के परिवारीजनों को सम्मानित भी किया।

लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारीजन को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। पुलिस का मनोबल, कार्यकुशलता व व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना व लोगों में सुरक्षा भावना पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर कदम बढ़ाए गए हैं।

एक सितंबर 2018 से 31 अगस्त 2019 के मध्य देश में 292 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के पांच शहीद पुलिसकर्मी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी सुरेश प्रताप सिंह, आरक्षी हर्ष चौधरी, हरेंद्र सिंह व बृजपाल सिंह शामिल हैं। योगी ने शोक परेड की सलामी लेने के बाद पांचों शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भेंट की। समारोह में उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

लखनऊ में सोमवार को आयोजित पुलिस स्मृति दिवस में अमरोहा निवासी शहीद हर्ष चौधरी का परिवार भी शामिल हुआ। उनकी पत्नी और बच्चे से मिलते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद के नौनिहाल को गोद में लेकर दुलारने लगे। फर्ज की खातिर सर्वोच्च बलिदान करने वाले पिता की निशानी को दुलारते सीएम उस अबोध से प्रेम की मौन भाषा में कहते जान पड़े कि, बेटा हम कर्जदार हैं तेरे। हृदेश चंदेल

शहीदों के परिजनों को दी सहायता

योगी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अथवा जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी 169 जवानों के आश्रितों को 37 .54 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पुलिस में 79972 पदों पर भर्ती हुई। उपनिरीक्षक व आरक्षी के कुल 61,134 पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया चल रही है। एक वर्ष में 28, 453 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई।

डर से 16,985 अभियुक्तों ने किया समर्पण

योगी ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में 1631 अपराधी घायल हुए हैं। पुलिस ने 10,252 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 6,759 पुरस्कार घोषित अपराधी हैं। बदमाशों से मुकाबले में पांच पुलिसकर्मी शहीद हुए और 752 घायल। पुलिस कार्रवाई के भय से 16,985 अभियुक्तों ने अपनी जमानतें निरस्त कराकर समर्पण किया है।

27 सप्ताह की गर्भवती 11 साल की बच्ची के गर्भपात के निर्देश

नईदुनिया, जबलपुर

- हाई कोर्ट ने कहा - बच्ची नहीं देगी दुष्कर्मी की संतान को जन्म
- मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता का गर्भपात न कराने की दी है राय

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27 सप्ताह की गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता ग्यारह साल की बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी है, जबकि तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ व एक मनोचिकित्सक के मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात न कराने की राय दी है। लेकिन, अनचाहा गर्भधारण करने व दुष्कर्मी की संतान को जन्म देने के सदमे से बचाने के लिए जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने बच्ची के गर्भपात के लिए सर्वोत्तम व सुरक्षित मेडिकल सहायता के साथ तत्काल कदम उठाने के सरकार को निर्देश दिए।

मप्र के टीकमगढ़ जिले की एक महिला ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री से उसके ही देवर ने दुष्कर्म किया था। इसके चलते वह गर्भवती हो गई। अधिवक्ता कबीर पॉल ने कोर्ट को बताया कि टीकमगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिकाकर्ता ने गर्भपात की अनुमति देने के लिए आवेदन दिया, लेकिन खारिज कर दिया गया। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता दुष्कर्मी की संतान को जन्म नहीं देना चाहती।

लिहाजा, उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। गत 15 अक्टूबर को कोर्ट ने कमिटी गठित करने व 17 अक्टूबर को स्त्री रोग विशेषज्ञ व एक मनोचिकित्सक का बोर्ड बनाकर पीड़िता की जांच के निर्देश दिए थे। सोमवार को शासकीय अधिवक्ता अभय पांडे ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पेश कर बताया कि बच्ची को गर्भपात की सीमा से 11 सप्ताह अधिक का गर्भ है। वह शारीरिक रूप से गर्भपात के योग्य भी नहीं है। उसे गर्भधारण व गर्भपात दोनों में ही खतरा है। मेडिकल बोर्ड ने बच्ची पर गर्भ व बच्चे के जन्म के प्रभाव को लेकर कोई राय नहीं दी।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ। फाइल

उन्होंने दलील दी कि 19 जुलाई 2019 को हाई कोर्ट 13 साल की बच्ची को इन्हीं परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दे चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से भी इसके लिए रजामंदी जताई गई। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञों की देखरेख में तत्काल गर्भपात का इंतजाम किया जाए।

आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो की कार शेड परियोजना पर रोक नहीं : कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो की कार शेड परियोजना पर रोक नहीं है। उसने साफ किया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ वहां स्थित पेड़ों की कटाई पर लागू होगा। शीर्ष अदालत ने बृहनमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) से आरे वन क्षेत्र से काटे गए पेड़ों की संख्या, पौधों की रोपाई और पेड़ों के प्रत्यारोपण को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

जस्टिस अरुण मिश्रा व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को बीएमसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वस्त किया कि आरे कॉलोनी में अब पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में वहां यथास्थिति बहाल है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने आरोप लगाया कि आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई और परियोजना के तहत निर्माण कार्य जारी हैं। पीठ ने कहा, 'मेहता ने याचिकाओं पर जवाब देने के लिए मोहलत

- शीर्ष अदालत ने कहा, पेड़ों की कटाई के मामले में रहेगी यथास्थिति
- बीएमसी व मुंबई मेट्रो से पेड़ों की कटाई, प्रत्यारोपण व रोपाई पर मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

मांगी है। हमने उनसे आरे वन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है।' कोर्ट ने कहा, 'हमने मुंबई मेट्रो की तरफ से प्रस्तुत वरिष्ठ वकील मनींदर सिंह व मुकुल रोहतगी से मौजूदा पेड़ों की तस्वीर, उनकी संख्या, दो साल पहले रोपे गए और विकास कर रहे पेड़ों, पेड़ों की मोटाई तथा ऊंचाई के बारे में जानकारी मांगी है। ये समस्त जानकारियां हलफनामे के साथ देनी होंगी और उसमें साफ-साफ बताना होगा कि पेड़ों के प्रत्यारोपण की दर क्या रही?'

रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि 5,000 से ज्यादा पेड़ों का प्रत्यारोपण किया जा चुका है। उन्होंने आरे वन क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण के प्रस्ताव के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रोजाना 60 लाख लोग दिल्ली मेट्रो में परिवहन करते हैं। इससे सात लाख वाहन सड़कों पर नहीं निकलते और उनका धुआं उत्सर्जन रुकता है।

उल्लेखनीय है कि सात अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे क्षेत्र में मेट्रो के कार शेड निर्माण के लिए हो रही पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। पेड़ों की कटाई का लोगों ने विरोध किया था और इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

पूर्व विधायक बोले- बेटी को लव जिहाद में फंसाया गया

नईदुनिया, भोपाल : दस साल तक बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाने वाली बेटी के आरोपित पिता व भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने अब लव जेहाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में चल रहे हुक्का लाउंज तत्काल बंद कराए जाएं। ये लव जेहाद का बड़ा कारण भी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी लव जिहाद में फंसाया गया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि मंगलवार तक हुक्का लाउंज बंद नहीं कराए गए तो जनता बंद करा देगी। गौरतलब है कि सुरेंद्रनाथ की बेटी ने उन पर बंधक बनाने के आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है।

सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने अभिभावकों से अपील की कि ऐसे स्थानों पर अपने बेटे-बेटी को न जाने दें। इन हुक्का बार में बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। वहां हिंदू युवतियों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। यहां फ्लेवर के नाम पर ड्रग्स दिया जाता है और लव जेहाद का शिकार बना लिया जाता है। मेरी बेटी का मामला भी लव जेहाद का है। उसे लव जेहाद में फंसाया गया है।

बार-बार एसआइटी प्रमुख बदलने के सरकार के जवाब से हाई कोर्ट नाराज

मप्र में हनी ट्रैप का मामला

नईदुनिया, इंदौर

- सरकार की दलील-सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए बदला
- कोर्ट ने कहा- यह तो कोई कारण नहीं, 15 दिन में दोबारा पेश करें स्टेटस रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी (विशेष जांच दल) के प्रमुख को बार-बार बदले जाने को लेकर शासन ने हाई कोर्ट में जो दलील दी, उससे उसने नाराजगी जताई। सरकार ने कहा कि प्रमुख बनाए गए पहले अधिकारी ने पारिवारिक कारणों से खुद को जांच से अलग रखने की गुहार लगाई थी, जबकि दूसरे अधिकारी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा था। इसके चलते उन्हें बदलना पड़ा। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह तो कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि केस में प्रभारी बनाए गए अधिकारी सुनवाई पूरी होने तक बदले नहीं जाएंगे। ट्रांसफर बहुत जरूरी हो तो पहले कोर्ट की अनुमति लेना होगी।

गौरतलब है कि कई राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को हनी ट्रैप करने के राजफाश के बाद गठित एसआइटी में तीसरी बार उसके प्रमुख की नियुक्त की गई है। इसे लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर हुई थीं। सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। शासन को इस सुनवाई में एसआइटी प्रमुख को बार-बार बदले जाने पर जवाब देना था। सोमवार को बंद लिफाफे में रिपोर्ट तो पेश हुई, लेकिन इसके साथ एसआइटी प्रमुख बदलने के संबंध में चलाई गई नोटशीट नहीं थी। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई और कहा कि स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है। इसके साथ दस्तावेज ही संलग्न नहीं हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया है, उनके बयान तक इसमें नहीं हैं। रिपोर्ट लौटाते हुए कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में नोटशीट के साथ स्टेटस रिपोर्ट दोबारा पेश करो।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ। फाइल

महत्वपूर्ण हैं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य : कोर्ट ने शासन से पूछा कि मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि) जब्त किए थे, उनकी जांच कहां करवाई। इस पर बताया गया कि अपने स्तर पर जांच करवाई थी। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई और कहा कि शासन ही साक्ष्य जब्त कर रहा है और उसकी ही लैब में जांच हो रही है। यह तो ठीक नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की हैदराबाद की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में जांच करवाई जाए और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। मामले में अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।

पहल

भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार बीमा कंपनियों के जरिए 950 यात्रियों को मिलेगा हर्जाना

तेजस की लेटलतीफी पर यात्रियों को मिलेगा 1 .62 लाख मुआवजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के विगत 19 अक्टूबर को तीन घंटे से भी अधिक समय की देरी से चलने के कारण आइआरसीटीसी को करीब 1.62 लाख रुपये का हर्जाना भरना पड़ रहा है। रेलवे की यह कंपनी बीमा कंपनियों के जरिए अपने 950 यात्रियों को मुआवजा देगी। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तेजस ट्रेन लखनऊ से सुबह 6.10 बजे चलने के बजाय 9.55 बजे चली थी और नई दिल्ली दोपहर 12.25 बजे पहुंचने के बजाय करीब 3.40 बजे पहुंची थी। यह ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के लिए दोपहर 3.35 बजे रवाना होने के बजाय शाम को 5.30 बजे रवाना हुई थी। इसके बाद यह ट्रेन रात को 10.05 बजे पहुंचने के बजाय रात 11.30 बजे पहुंची थी। इसके चलते लखनऊ से दिल्ली जाने वाले 450 यात्रियों को 250 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जबकि दिल्ली से लखनऊ जाने वाले प्रत्येक 500 यात्रियों को सौ रुपया दिया जाएगा।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हरेक यात्री

- सोमवार को सुबह 6.10 बजे चलने के बजाय 9 बजे चली थी ट्रेन

तेजस एक्सप्रेस। फाइल

इस मुआवजा राशि को बीमा कंपनी की ओर से दिए गए लिंक के जरिए हासिल किया जा सकता है। यह लिंक तेजस एक्सप्रेस के हर टिकट पर दर्ज होता है। उन्होंने यह भी बताया कि 19 अक्टूबर को तेजस एक्सप्रेस के परिचालन में देरी की वजह कानपुर के पास एक ट्रेन का पटरी से उतर जाना था।

ट्रेनों की लेटलतीफी में हो रहा है सुधार, मगर धीरे-धीरे

नई दिल्ली, प्रेट्र : ट्रेनों को समय से संचालित करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार में कोशिश में है। चालू वित्त वर्ष में अब तक इन कोशिशों का थोड़ा-थोड़ा असर दिखा है। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के जरिये मिली जानकारी में यह बात सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, इस साल अब तक 18 फीसद राजधानी और नौ फीसद शताब्दी ट्रेनें लेट हुई हैं। पिछले वित्त वर्ष में 23 फीसद राजधानी और 13 फीसद शताब्दी ट्रेनें लेट हुई थीं। गरीब रथ और सुविधा एक्सप्रेस के मामले में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। इस वित्त वर्ष में अब तक (अप्रैल-सितंबर) 44 फीसद गरीब रथ और 53 फीसद सुविधा एक्सप्रेस लेट हुई हैं। आरटीआइ में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में 74 फीसद मेल एक्सप्रेस और 71 फीसद पैसेंजर ट्रेनें समय पर चलीं। पिछले वित्त वर्ष में 69.23 फीसद मेल एक्सप्रेस और 68 फीसद पैसेंजर ट्रेनें समय पर चली थीं। भोपाल के आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर ने ट्रेनों की समयबद्धता पर सवाल पूछा था।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि स्टेशनों के पुनर्विकास की एक लाख करोड़ की रेलवे की योजना में गंभीर खामियों के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं। कैग ने स्टेशनों पर ट्रेनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने पर भी सवाल उठाया था। रेलवे ने ट्रेनों के संचालन पर नजर रखने के लिए उन्हें इसरो के सेटेलाइट नेटवर्क से जोड़ने वाला सिस्टम लांच किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि ट्रेनों को उनकी अधिकतम तय गति सीमा तक चलाया जाए।

बघेल के खिलाफ सेक्स सीडी मामला स्थानांतरित कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स सीडी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में आरोपित हैं। शीर्ष कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका पर मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्यों न इस मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोब्डे और जस्टिस एसए नजीर की पीठ ने सीबीआइ की याचिका पर बघेल को नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी ने आपराधिक मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने मामले में गवाहों को धमकाया है। पीठ ने मुख्यमंत्री से यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न इस मामले को स्थानांतरित कर दिया जाए।

सीबीआइ ने सितंबर 2018 में बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस समय वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा नेता राजेश मुनात को फर्जी सेक्स सीडी मामले में फंसाने की शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री और एक पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद में पत्रकार वर्मा के घर पर छापामारी की थी और भाजपा नेता की छवि खराब करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने यह मामला सीबीआइ को सौंप दिया था।

सीबीआइ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने जांच एजेंसी से शिकायत की है कि उन्हें आरोपित की ओर से धमकी दी गई है। उसे मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने पर धमकाया गया है।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

दैनिक जागरण

गुरु के बिना मनुष्य जीवन बिना पतवार की नौका के समान होता है

क्या दिल्ली ही देश है?

यह स्वागतयोग्य है कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ भी आगे आ गया। वह पंजाब और हरियाणा की सरकारों से मिलकर इसकी कोशिश करेगा कि यहां के किसान पराली न जलाएं। केंद्र सरकार पहले से ही इस कोशिश में है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली न जले। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की कोशिश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। इन सबके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण भी। इन सबके प्रयासों ने असर दिखाया है और दिल्ली एवं आसपास के इलाके को प्रदूषण से पूरी तरह न सही, एक बड़ी हद तक राहत मिली है। इसकी एक वजह आम जनता की जागरूकता भी है और यह पहलू भी कि नीति-नियंताओं का एक बड़ा वर्ग दिल्ली में रहता है। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ तमाम सरकारी एजेंसियों की सक्रियता से बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद आगे भी की जाती है, लेकिन क्या दिल्ली ही देश है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि मौसम में नमी बढ़ने और तापमान घटने के साथ ही उत्तर भारत के अन्य शहर भी प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक आंकड़े के अनुसार रविवार को प्रदूषित हवा के मामले में लखनऊ की स्थिति दिल्ली से भी खराब रही। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कई शहरों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में प्रदूषण का दायरा और बढ़ने का अंदेशा है। इस अंदेशे का एक बड़ा कारण यह है कि पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी देश के चुनिंदा प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर, आगरा, वाराणसी से लेकर गया, पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल थे। अब अगर सर्दियों में उत्तर भारत के उन शहरों की हवा की गुणवत्ता भी खराब हो जा रही है जो औद्योगिक शहरों में गिनती नहीं रखते तो इसका मतलब है कि प्रदूषण की समस्या कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है और वह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। विडंबना यह है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जैसी चिंता जताई जाती है वैसी कोई चिंता उत्तर भारत के अन्य शहरों को लेकर नहीं की जाती। न तो दिल्ली के मुकाबले उत्तर भारत के अन्य शहरों के लोग दोयम दर्जे के हैं और न ही ऐसा कुछ है कि उनके लिए प्रदूषण कम घातक है। ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं कि देश के हर हिस्से के लोगों की सेहत की चिंता समान भाव से की जाए?

हाईवे पर डेंजर जोन

उत्तराखंड में एक के बाद एक हादसे आम जनमानस के दिल को दहला रहे हैं। पिछले दिनों टिहरी जिले में देवप्रयाग के पास हेमकुंड जा रहे पंजाब के तीर्थयात्रियों के वाहन पर बोल्डर गिरने से छह लोगों की मौत हो गई तो इसी शनिवार देर रात केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे ही हादसे में आठ लोगों ने जान गंवाई। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष दिसंबर में रुद्रप्रयाग के पास बांसवाड़ा में पहाड़ी दरकने से सड़क निर्माण में जुटे आठ मजदूर जिंदा दफन हो गए। इन हादसों का मुख्य कारण सिर्फ कुदरत का कोप भर नहीं है, बल्कि मानवीय चूक अथवा लापरवाही भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। दरअसल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत सड़क की कटिंग की गई है। इसके बाद केदारनाथ हाईवे पर 13 स्थानों को चिन्हीत कर खतरनाक घोषित किया गया। हाईवे पर ये 13 स्थान डेंजर जोन के तौर पर उभरे हैं। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने दावा किया था कि इन स्थानों पर चौबीस घंटे एसडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल मौजू हैं। मसलन यदि प्रशासन की तैयारी इतनी पुख्ता थी तो हादसा टाला जा सकता था। दूसरा 76 किलोमीटर लंबे केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात में आवाजाही की इजाजत क्यों दी जा रही है। बात सिर्फ केदारनाथ हाईवे की ही नहीं है, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे का हाल भी जुदा नहीं है। बदरीनाथ के पास लामबगड़ में दरकती पहाड़ी यात्रियों के चुनौती बन चुकी है। यह क्रम कई वर्षों से बना हुआ है। सड़क की देखरेख का जिम्मा उठा रहा सीमा सड़क संगठन कई बार इस पहाड़ी के ट्रीटमेंट का प्लान बना चुका है, लेकिन अब तक यह धरातल पर नहीं उतर पाया। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर करीब 52 डेंजर जोन चिन्हीत हैं। इनमें गंगोत्री हाईवे पर चुंगी-बड़ेथी और यमुनोत्री पर डाबरकोट जी का जंजाल बन चुके हैं। इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर आई सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की टीम भी निर्माण एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा चुकी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ की कटिंग का मलबा नदी तटों पर डालने पर भी कमेटी नाराजगी जता चुकी है। स्थानीय लोग भी निर्माण एजेसिंयों के मनमाने रवैये से खासे आक्रोशित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑल वेदर रोड पहाड़ की लाइफ लाइन को निष्कंटक करेगी, लेकिन निर्माण के दौरान एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यह देखा जाना चाहिए कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

व्यापार में संरक्षणवाद की वापसी

डॉ. भरत झुनझुनवाला

अमेरिका और चीन को रोजगार बचाने के लिए व्यापार युद्ध से गुरेज नहीं। ऐसे में हमें भी वही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि महंगे माल और रोजगार में हमेशा रोजगार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए

पिछले दो वर्षों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से आयात होने वाली तमाम वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा रहे थे। पलटवार करते हुए चीन ने भी अमेरिका से आयातित सामान पर आयात कर में बढ़ोतरी की। परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार कम होने लगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ का कहना है कि इस व्यापार युद्ध का संपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आइएमएफ आकलन के पीछे मुक्त व्यापार का सिद्धांत है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि संपूर्ण विश्व का एक बाजार होने पर तमाम देशों में जो सबसे बेहतर होगा, वही माल का उत्पादन करेगा। जैसे मान लीजिए किसी कार की उत्पादन लागत भारत में पांच लाख रुपये और अमेरिका में सात लाख रुपये है तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार ऐसी परिस्थिति में कार का उत्पादन भारत में होना चाहिए। भारत में उत्पादन कर इसे अमेरिका को निर्यात करना चाहिए जिससे ढुलाई का खर्च वहन करने के बाद भी अमेरिकी उपभोक्ता को छह लाख रुपये में वह कार उपलब्ध हो जाए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुक्त व्यापार से विश्व के सभी उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलेगा जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसी आधार पर चीन में बना माल भारत में बड़ी मात्रा में आयातित हो रहा है और भारतीय उपभोक्ताओं का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है।

प्रश्न है कि तब अमेरिका को चीन से आयात पर कर क्यों बढ़ाने पड़े? कारण है कि अमेरिका में रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तमाम वस्तुओं का उत्पादन चीन, भारत, वियतनाम आदि देशों में किया जा रहा है और फिर उसे अमेरिका में आयात किया जा रहा है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता माल अवश्य मिल रहा है, लेकिन अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। रोजगार के अवसर चीन, भारत अथवा वियतनाम में सृजित हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों के रोजगार बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को चीन में बना सस्ता माल उपलब्ध कराने के बजाय अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाए। यदि अमेरिका में उत्पादन लागत ज्यादा आती है तो अमेरिकी उपभोक्ता उसे वहन करें। सस्ते माल और रोजगार के बीच अंतर्विरोध है। मुक्त व्यापार से अमेरिका को सस्ता माल तो मिल रहा है, लेकिन रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति का विरोध कर रही हैं। इन कंपनियों के लिए यह फायदेमंद है कि वे उस देश में माल का उत्पादन करें जहां पर श्रम सस्ता होने के साथ प्रदूषण संबंधी नियम शिथिल हों। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड वॉर से पीछे हटें और मुक्त व्यापार को अपनाएं जिससे उन्हें विश्व के तमाम देशों में विचरने की छूट मिले। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तर्ज पर आइएमएफ भी मुक्त व्यापार का समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपूर्ण विश्व में विचरण करेंगी तो पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलेगा। इस बात में दम है, लेकिन आइएमएफ के पास इसका जवाब नहीं है कि यदि उत्पादन चीन में होगा तो अमेरिकियों को रोजगार कैसे मिलेगा? इसी क्रम में राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिका से दुग्ध उत्पादों के आयात की छूट दे जिससे अमेरिकी किसानों के लिए अवसर बढ़ें। दोनों देश आखिर अपनी जनता के रोजगारों का संरक्षण करना चाहते हैं।

अवधेश राजपूत

ऐसे में भारत के समक्ष दो विकल्प हैं। एक यही कि हम आइएमएफ की तर्ज पर कहें कि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध को समाप्त किया जाए। संपूर्ण विश्व को एक बाजार बनाया जाए जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को भी सस्ता माल उपलब्ध हो। इसी सोच के चलते चीन में बने खिलौने, बिजली के सामान और अन्य वस्तुएं आज भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते में उपलब्ध हो रही हैं। इस रणनीति का दूसरा फायदा यह हो सकता है कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध के चलते तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे विकासशील देशों का रुख कर रही हैं। जैसे एपल ने वियतनाम में अपना कारखाना लगाया है तो फोक्सकॉन ने भारत में और शार्प ने वियतनाम में। हम प्रयास कर सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर जाना चाहती हैं उन्हें भारत में उत्पादन करने को प्रेरित करें।

इस रणनीति में समस्या यह है कि रोजगार का मसला अटका रह जाता है। यदि वर्तमान में इन कंपनियों द्वारा चीन में किए जा रहे उत्पादन से अमेरिकी रोजगारों का हनन हो रहा है तो भविष्य में फोक्सकॉन द्वारा भारत में उत्पादन करने से भी अमेरिकी श्रमिकों के रोजगारों का हनन होगा। इसके चलते अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद का सहारा लिए जाने की आशंका कायम रहेगी। तब हमारा यह प्रयास विफल हो जाएगा। आज हम अभी अपनी ताकत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में स्थापित करने में लगाएंगे और भविष्य में उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा आयात कर लगाए जाएंगे। जिस प्रकार ये कंपनियां आज चीन को छोड़कर जा रही हैं, आने वाले वक्त में उसी प्रकार भारत को छोड़कर किसी अन्य देश या अपने मुल्क अमेरिका का भी रुख कर सकती हैं। इसलिए मुझे यह रणनीति सफल होती नहीं दिखती। दूसरी रणनीति यह हो सकती है कि अमेरिका, चीन की तर्ज पर हम भी संरक्षणवाद को अपनाएं। जिस प्रकार अमेरिका और चीन ने अपने श्रमिकों और किसानों के रोजगार को बचाए रखने के लिए व्यापार युद्ध अपनाया है, कुछ वैसी ही रणनीति हमें भी अपनानी होगी। हम भी चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर आयात कर बढ़ाकर चीनी माल के भारतीय बाजार में प्रवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं। इससे भारत में उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह रणनीति दीर्घकाल में कारगर होगी।

हालांकि कुछ वक्त के लिए भारतीय उपभोक्ताओं को यह भारी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें चीन की सस्ती वस्तुओं को छोड़कर महंगे भारतीय उत्पादों को खरीदना होगा। इसकी भरपाई के लिए भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकती है जिससे कंपनियां बेहतर और सस्ते माल का उत्पादन करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसी देश के श्रमिकों के हित से कोई वास्ता नहीं है। उनकी दृष्टि विश्व स्तर पर लाभ कमाने पर ही केंद्रित रहती है। ट्रंप ने सही आकलन कर इसका विरोध किया है। हमें भी उनकी रणनीति के अनुसार संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिले। महंगे माल और रोजगार के बीच हमेशा रोजगार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। रोजगार उपलब्ध हो और महंगा माल खरीदना पड़े तो श्रमिक बिना टेलीविजन के भी जीवनयापन कर सकता है। वहीं यदि सस्ता टेलीविजन उपलब्ध हो, लेकिन खाने के लिए रोटी न हो तो वह सस्ता टेलीविजन किस काम का?

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

स्कूली शिक्षा में सुधार का सही उपाय

प्रो. गीता गांधी किंगडन

सरकारी स्कूलों और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने में डीबीटी एक सशक्त माध्यम बन सकता है

अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। सरकार शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए समय-समय पर प्रयास भी करती है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। सरकारी स्कूलों को अनुदान देने का तरीका बदलकर अपेक्षित सफलता हासिल की जा सकती है। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति की धनराशि को सीधे बच्चों के माता-पिता के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है अथवा उन्हें 'वाउचर' दिया जा सकता है। इससे प्रत्येक बच्चे को वाउचर पर लिखी निर्धारित फीस लेने वाले तमाम स्कूलों में से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुनने का अवसर भी मिल सकेगा। इससे भारत के तमाम बच्चों का भविष्य बदल सकता है। अगर वाउचर फंडिंग शुरू हो जाए तो देश के खराब गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल और वहां के शिक्षकों की भी जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि इन स्कूलों और इनके शिक्षकों के वेतन को भी स्कूल की फंडिग से जोड़ा जाएगा। बच्चों के इन स्कूलों में दाखिला लेने पर ही इन स्कूलों की फंडिंग निर्भर हो जाएगी।

मौजूदा समय सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चे टिकते नहीं हैं। तमाम स्कूल खाली पड़े हुए हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2011-2017 के बीच सरकारी स्कूलों में होने वाले कुल दाखिलों में 2.38 करोड़ की गिरावट आई है, वहीं निजी स्कूलों के कुल नामांकन में 2.11 करोड़ छात्रों की वृद्धि हुई है। बच्चों के पलायन के चलते अधिकांश सरकारी स्कूल शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अलाभकारी बन गए हैं। कुल सरकारी स्कूलों में से 41 प्रतिशत (4,26,700) स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से भी कम है। डीबीटी के तहत सरकार हर बच्चे के अभिभावक को एक निर्धारित धनराशि का वाउचर दे सकती है। यदि इस वाउचर की राशि 500 रुपये प्रति माह के रूप में निर्धारित की जाती है तो इसका मतलब है कि अभिभावक अपने बच्चे को किसी भी ऐसे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं जहां की मासिक फीस 500 रुपये तक है, लेकिन यदि कोई इससे अधिक फीस वाले स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहता है तो बाकी के पैसे अपनी जेब से वहन कर सकता है। विश्व के कई देश कोलंबिया, चिली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि में स्कूल वाउचर योजना को लागू कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। यही भारत को करना चाहिए। फिलहाल अपने यहां सरकारी अनुदान सीधे स्कूल को मिलता है, लेकिन वाउचर योजना के तहत

यह पैसा अभिभावक के माध्यम से ही स्कूल को मिलेगा। वाउचर योजना के तहत स्कूल को प्रति बच्चे के हिसाब से पैसा मिलेगा, जबकि मौजूदा स्कीम में प्रत्येक सरकारी वित्त पोषित स्कूल को एकमुश्त राशि मिलती है। सैकड़ों सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में भारी गिरावट के बावजूद उन्हें पूरा अनुदान मिलता रहता है।

वाउचर योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अभिभावकों को स्कूल चुनने का अधिकार देती है। अगर वे स्कूल की गुणवत्ता या वहां के माहौल से असंतुष्ट हैं तो वे अपने बच्चे को उस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में डाल सकते हैं, जिससे उस स्कूल को वाउचर से मिलने वाली धनराशि भी बंद हो जाएगी। ऐसे में एक ओर जहां स्कूलों एवं शिक्षकों की अभिभावकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी तो दूसरी ओर स्कूलों को इस वाउचर धनराशि को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित करने के लिए दूसरे स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ेगी। ऐसे में ये स्कूल अच्छे परीक्षा परिणाम देने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। स्कूल वाउचर योजना के तहत शिक्षा में समानता भी बढ़ सकती है।

शिक्षा में डीबीटी लागू करने को लेकर सरकार की दो मुख्य आपत्तियां हैं। पहली, सरकार का मानना है कि पिछड़े ग्रामीण इलाकों में सरकारी वाउचर फंडिग के बावजूद स्थानीय शिक्षित लोग निजी स्कूल नहीं खोलेंगे। हालांकि यह डर बेबुनियाद है। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार गैर सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक स्कूलों की औसत फीस ग्रामीण इलाकों में 292 रुपये प्रति माह और शहरी इलाकों में 542 रुपये प्रति माह थी। इस सर्वे के मुताबिक भारत के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 25 प्रतिशत बच्चों ने 200 रुपये प्रति माह से कम फीस भरी थी, 57 प्रतिशत ने 500 प्रति माह से कम फीस भरी थी, 82 प्रतिशत ने 1000 प्रति माह से कम फीस भरी थी और सिर्फ 3.6 प्रतिशत ने 2,500 रुपये प्रति माह से अधिक फीस भरी थी। इसका मतलब है कि 25 प्रतिशत निजी स्कूल 200 रुपये प्रति माह से कम फीस ले रहे हैं, जो कि 500 रुपये कीमत के वाउचर की तुलना में बेहद कम है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के स्कूलों एवं शिक्षित व्यक्तियों के लिए इस योजना में शामिल होना फायदेमंद होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डीबीटी योजना को लेकर दूसरी शंका यह है कि सरकारी स्कूल खाली हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि जिन सरकारी स्कूलों में बेहद कम बच्चे होंगे उन्हें डीबीटी के तहत बहुत कम पैसा मिल पाएगा और ऐसे में वे अपने शिक्षकों की तनख्वाह भी नहीं दे सकेंगे। वक्त के साथ यह समस्या खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए जहां बच्चे कम और शिक्षक ज्यादा हैं, वहां जब कुछ शिक्षक रिटायर होंगे तो उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। दूसरा समाधान यह है कि सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अलग-अलग कीमत के वाउचर निर्धारित किए जाएं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का प्रति छात्र खर्च 2017-18 में प्राथमिक स्तर पर 2,500 प्रति माह और उच्चतर प्राइमरी स्कूलों में प्रति माह 3,300 रुपये का है, जो कि औसत निजी स्कूलों की फीस से कई गुना अधिक है।

यह सर्वविदित है कि कठिन समस्याओं के समाधान के लिए साहसी कदम उठाने ही पड़ते हैं। मौजूदा व्यवस्था में ही थोड़ा-बहुत हेरफेर करने से स्कूली शिक्षा में वांछित सुधार नहीं आने वाले। शिक्षा की समस्या का समाधान संभव होगा स्कूल और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने से और इसके लिए डीबीटी सशक्त माध्यम है, जो कि देश भर के बच्चों को एक तरह की स्कॉलरशिप भी होगी।

(लेखिका यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में शिक्षा, अर्थशास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय विकास की प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आहार संयम

इंसान की मौलिक इच्छाओं में पहली इच्छा भोजन की होती है। भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे एक ऐसा रसायन बनता है, जो प्राण-ऊर्जा बनकर संपूर्ण शरीर-तंत्र का संचालन करता है। हमारे भोजन से ही प्राण-शक्ति पैदा होती है जो शक्ति केंद्र को संचालित करती है। इसलिए भोजन का महत्व है और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि ''जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन।'' भोजन तीन प्रकार का होता है-सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन जहां मन को शुद्ध करता है, वहीं तामसिक और राजसिक भोजन मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसलिए आहार-शास्त्र में सात्विक भोजन की सिफारिश की गई है और तामसिक तथा राजसिक भोजन से बचने का आग्रह किया गया है।

एक दिन पवनार-आश्रम में विनोबा भावे ने उपवास की उपयोगिता पर कहा कि, ''भगवान महावीर ने जितने दिन खाया, उससे अधिक दिन नहीं खाया।'' तभी वे अपनी साधना में सफल हो सके। भगवान महावीर ने कहा भी है कि ''आत्म-नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है।'' टॉल्स्टॉय ने कहा है, ''जो भोजन का संयम नहीं करता, वह सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा? जो आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता, वह आत्म-नियंत्रण कैसे पर पाएगा?'' उन्होंने आगे कहा, ''जीने की कामना, भोजन की कामना और लड़ने की कामना-ये मौलिक इच्छाएं हैं। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सका तो इनके आधार पर चलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले अपनी मौलिक इच्छाओं पर नियंत्रण करे।'' भोजन का संयम न हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भोजन में कम खाने का महत्व है। कहा गया है कि जितने आदमी भूख से मरते हैं, उससे अधिक ज्यादा खाने से मरते हैं। इसीलिए संतुलन आवश्यक है।

ललित गर्ग

डिजिटल अर्थव्यवस्था की बाधाएं

अनीश कुमार

सरकार भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है, लेकिन अभी भी इसकी राह में कई बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना होगा

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार भीम यूपीआइ एप 2.0 लांच करने जा रही है। नए एप में न केवल फीचर अधिक होंगे, बल्कि ग्राहक पहले से ज्यादा भाषाओं में डिजिटल लेन-देन कर सकेंगे, लेकिन इतने भर से ही देश में डिजिटल पेमेंट में तेजी नहीं आएगी। इसके सामने कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। हालांकि डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है। फिर भी नकदी और चेक से लेन-देन अभी बड़ी मात्रा में हो रहा है। क्रेडिट सूइस ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार 72 फीसद भारतीय उपभोक्ता नकदी में लेन-देन करते हैं, जो कि चीन की तुलना में दोगुना है।

कई स्मार्ट फोन यूजर्स तो सिर्फ कैशबैक की उम्मीद में डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा फीचर फोन यूजर्स ज्यादातर नकदी में ही लेन-देन करते हैं। डिजिटल पेमेंट अधिकतर शहरी लोगों खासकर इंटरनेट का उपयोग करने वालों के बीच ज्यादा है। डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ भी यही है। डिजिटल पेमेंट की लागत भी काफी अधिक है। ऐसे लेन-देन पर जीएसटी 18 प्रतिशत है। यह निम्न आय वाले लोगों को हतोत्साहित करने वाला कदम है। यहां तक कि ई कॉमर्स कंपनियों से अधिकतर लोग कैशऑन डिलिवरी में ही सामान मंगाते हैं। आज भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर होने वाले आधे ऑर्डर कैशऑन डिलिवरी होते हैं। पहले यह 70 फीसद था। वर्ल्ड कैश रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत उन गिने चुने लोगों में है जहां यूजर कैब बूक करते हैं स्मार्ट फोन से, लेकिन भुगतान करते हैं कैश में। प्वाइंट ऑफ सेल मशीन ज्यादातर शहरी क्षेत्र में केंद्रित हैं। क्यूआर कोड की सुविधा का लाभ भी कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं। ये कारक डिजिटल लेने-देन में बाधक हैं।

वर्ष 2016 में नोटबंदी की गई थी। उसके बाद डिजिटल लेन-देन बढ़ा था, लेकिन आज 500 मिलियन मोबाइल इंटरनेट यूजर में से 120 मिलियन से भी कम यूजर डिजिटल लेन-देन करते हैं। अभी भी आधी आबादी इंटरनेट से दूर है। जाहिर है भारत में डिजिटल लेन-देन की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन यह कैसे होगा? आरबीआइ द्वारा जुलाई में जारी बुलेटिन में अगले तीन साल में डिजिटल लेन-देन को दस गुना बढ़ाने की बात कही गई थी। जाहिर है यदि ट्रांजेक्शन शुल्क को हटा लिया जाए, केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया जाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए और बैंक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को कम कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। फिर लोग कैशबक की आस भी छोड़ देंगे। फीचर फोन यूजर्स के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर उन्हें भी डिजिटल लेन-देन की ओर आकर्षित किया जा सकता है। हालांकि फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआइ का विकल्प है, लेकिन बैंकों के सुस्त रवैये के कारण यह जोर नहीं पकड़ रहा है।

जाहिर है जब तक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और माहौल नहीं दिया २जाएगा तब तक देश में डिजिटल लेन-देन में अपेक्षित तेजी नहीं आएगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अधिक समावेशी हैं कैब के प्रावधान

जख्मों पर लगे नागरिकता का मरहम शीर्षक से लिखे अपने लेख में एम नागेश्वर राव ने असम में एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब), 2016 की प्रासंगिकता पर विस्तार से विचार किया है। यह आशंका निराधार नहीं कि कैब के वर्तमान प्रावधानों की आड़ में भारतीय नागरिकता पाने की लालसा में बहुतेरे लोग दिखावे के लिए अपना धर्म बदल लें और एक बार नागरिकता पा लेने के बाद वापस अपनी मूल धार्मिक पहचान हासिल कर लें। ऐसे में तो यह व्यवस्था भारत में घुसपैठ का कानूनी जरिया बन सकता है तो फिर इस संभावित छल को रोकने के लिए विधेयक में कौन से उपाय जोड़े जा सकते हैं? एक उपाय तो यह है कि इच्छुक आवेदकों के पूर्वजों के धर्म को भी एक आधार बनाया जाए। दूसरे, आवेदकों की जमीन के दस्तावेज, उनकी सामूहिक पहचान आदि को देखा जा सकता है। लेखक ने कैब को केवल इंडिक धर्मों तक सीमित रखने की बात की है। यह विचार सुनने में चाहे जितना भला लगे, किंतु उत्पीड़ित ईसाइयों और यहूदियों को इससे बाहर रखने की स्थिति में न सिर्फ देश के बाहर, बल्कि अंदर भी इस पर विवाद बढ़ जाएगा, फिर भारत के उच्च सदन के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए इसे पास कराना और भी कठिन हो सकता है। निःसंदेह कैब के वर्तमान प्रावधान अधिक समावेशी हैं और इसलिए अधिक व्यावहारिक एवं लागू कर सकने योग्य भी। जहां तक बात दुनिया भर के इंडिक धर्मों के अनुयायियों को भारतीय नागरिकता देने की है तो यह एक वृहत्तर और अधिक जटिल प्रश्न है। अमेरिका के सर्वकालिक महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि 'मैं धीमा चलता हूं और इसलिए कभी वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ी।' फिलहाल कैब के प्रावधानों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों तक सीमित रखने के सरकार के संकल्प को लिंकन के उक्त सूत्र वाक्य से भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

चंदन कुमार, देवघर

मेलबाक्स

हमाम में सभी नंगे

दैनिक जागरण के 15 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित राजीव सचान का लेख, कर्ज के नाम पर लुटते बैंक, पढ़ा। यह बात बिल्कुल सही है कि बैंक अपने स्तर पर ही रिजर्व बैंक के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को भी ऋण मुहैया करा दे रहे हैं जिन्होंने अपने पहले ऋण के भुगतान में खामियां की हैं। अब सवाल यह उठता है कि आम आदमी को कोई छोटा सा भी ऋण देते समय ये सभी बैंक व वित्तीय संस्थाएं क्रेडिट रेटिंग की जांच करती हैं, पर इतने बड़े-बड़े ऋण देते समय ये सब प्रक्रिया आखिर क्यों पूरी नहीं की जाती? मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव और मिलने वाली सुविधाओं के चक्कर में ये सब घाल मेल चल रहा है और नियमों की अनदेखी बैंक के अधिकारियों द्वारा ही की जा रही है। आश्चर्य इस बात पर भी है कि आखिर बैंकों का अंकेक्षण करने वाली संस्थाएं भी इन वित्तीय अनियमितताओं को समय पर क्यों नहीं पकड़ पातीं। क्यों हर चीज में कैग को ही हस्तक्षेप कर इन अनियमितताओं को पकड़ना पड़ता है? शायद हमाम में सभी नंगे हैं, इसलिए कोई किसी पर अंगुली नहीं उठाता है। सरकार को चाहिए कि वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त ऐसी संस्थाओं व अधिकारियों पर सख्ती से नजर रखी जाए और जहां जरूरत पड़े उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। अगर बैंकिंग व्यवस्था साफ-सुधरी होती तो इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं नहीं होतीं। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बैंकों पर आम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। जब बैंकों में घपले की खबरें आती हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उनका विश्वास टूटता है।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

काबू में होंगे आतंकी

पाकिस्तान के साथ नरम रुख अख्तियार करना भारत के लिए घातक हो सकता है। यह बात केंद्र सरकार समझ चुकी है। इसीलिए एक के बाद एक हमला कर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। पहले की सरकार ने अगर जवाबी कार्रवाई की होती तो आज पाक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह बार-बार आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश करता। ऐसी ही कार्रवाई होती रही तो आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लग जाएगा।

विजय किशोर तिवारी, शिक्षक, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

20 अरब डॉलर के आसपास है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसके वर्ष 2023 तक एक खरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है, एक सरकारी अध्ययन के अनुसार।

आजकल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवसर और चुनौतियां

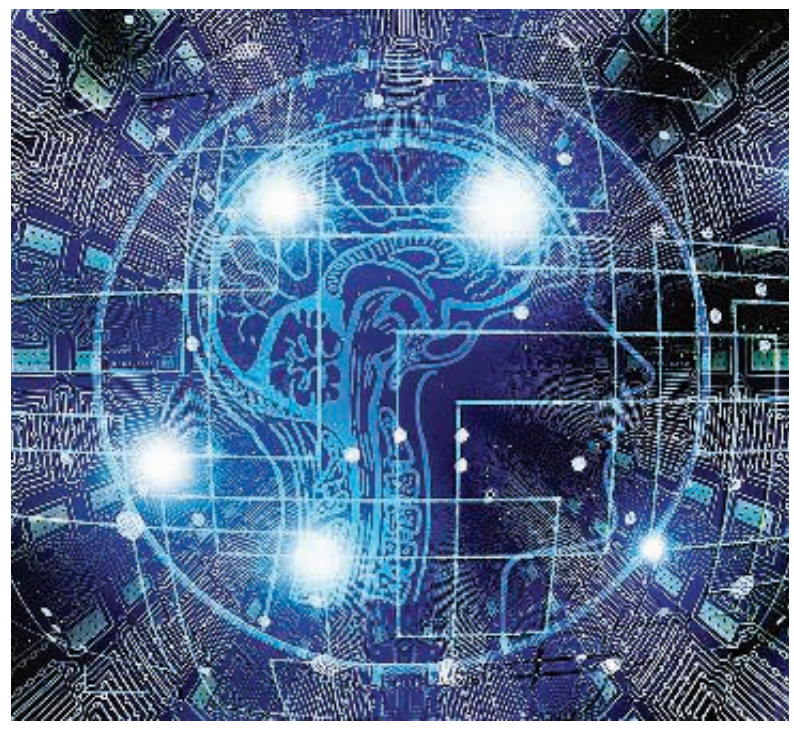

विश्व आर्थिक मंच का 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन इसी माह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें 40 देशों के 800 से ज्यादा नीति निर्माताओं और संबंधित विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह सम्मेलन दक्षिण एशिया में चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने और युवा आबादी का अधिकतम लाभ उठाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती तकनीकों, नवाचार व उद्यमशीलता, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और कौशल विकास के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई

कैलाश बिश्नोई
अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय

पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की दृष्टि से दो बड़े स्तरों पर काम हो रहा है- कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) विगत एक दशक में चर्चा के केंद्र में रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में एआइ का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मसलन शिक्षा के क्षेत्र में एआइ का प्रयोग ग्रेडिंग, रिकॉर्ड कीपिंग व अंक देने में, व्यापार में ग्राहकों को तत्काल सेवा देने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में अधिक उन्नत रोबोट का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। संभावना यह भी है कि भविष्य में इसके द्वारा उन सभी कार्यों को किया जा सकेगा जो एक इंसान करता है।

आने वाला वक्त एआइ का होगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 26 प्रतिशत और ब्रिटेन 10 प्रतिशत निवेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित गतिविधियों और व्यापार पर करेगा। वहीं 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में एआइ 15.7 खरब डॉलर का योगदान करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में भारत भी एआइ के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में एआइ रोजगार के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी। इस वजह से दुनिया भर में वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा शिक्षकों को बताया जा रहा है कि उन्नत तकनीक जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है और मौलिक रूप से उनके काम की प्रकृति को बदल देगी तथा नई अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से संपन्न लोगों की मांग करेगी। सवाल यह है कि क्या हमारा देश इस मामले में जरूरी निवेश कर पा रहा है? हाल के तमाम सर्वे बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल-निर्माण कर पाने में भारत अभी बहुत पीछे है। देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम एक हजार विद्यार्थियों में से मात्र चार ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपने उच्च अध्ययन का विषय बनाते हैं जो गहरी चिंता की बात है।

वर्तमान में भारत के 90 फीसद कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जन्मी आर्थिक ऊथल-पुथल का आसानी से शिकार बन सकते हैं। ऑटोमेशन के प्रसार के साथ ही संविदा नियुक्तियों की संख्या बढ़ेगी और वेतन में बहुत कमी आएगी। निर्माण उद्योग से जुड़े अनेक श्रमिक, जो अभी संविदा पर काम कर रहे हैं, थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक के आने के बाद तो बेकार ही हो जाएंगे। इसी प्रकार पूर्वी एशिया के देशों में रोबोट के जरिये होने वाली कृषि के सस्ते उत्पाद जब भारत में आने शुरू हो जाएंगे, तब भारत के किसानों की और भी ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी। वाहनों के क्षेत्र में पहले ही रोबोट प्रवेश कर चुके हैं। वहीं, दूसरी तरफ भारत के बैंक भी खर्च नियंत्रित रखने के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और गलतियां भी कम होंगी। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में भर्तियां कम हो गई हैं और जो हो भी रही हैं वे अग्रिम पंक्ति की होती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के आइटी और बीपीओ उद्यम में कम स्किल वाले कर्मियों की संख्या 2016 में घटकर 24 लाख रह गई थी जो 2022 में 17 लाख रह जाएगी। वैसे उसी स्टडी के अनुसार मध्यम कौशल वाली नौकरियों की संख्या 2022 तक बढ़कर 10 लाख हो जाएगी, जो 2016 में नौ लाख थी। उच्च कौशल वाली नौकरियों की संख्या भी 2022 तक बढ़कर पांच लाख हो जाएगी जो 2016 में 3.20 लाख थी।

आने वाले वर्षों में एआइ, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस तथा क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के लाखों मौके भी तैयार होंगे जो उच्च गुणवत्ता और बढ़िया वेतन वाले होंगे। लेकिन इसके लिए भारत को तीन चुनौतियों से पार पाना होगा। पहला, अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित बनाना होगा जिसके लिए जरूरत के अनुरूप शिक्षा के आधारभूत ढांचे पर व्यापक निवेश करना होगा और भारत की शिक्षा व्यवस्था को डिग्रियों के जाल से निकाल कौशल आधारित करना होगा। साथ ही चौथी औद्योगिक क्रांति से निपटने के लिए हमें ऐसे टास्क फोर्स बनाने होंगे, जो बहुआयामी कौशल से युक्त हों। दूसरी चुनौती रोबोट के रोजगार को छीनने के खतरे से निपटने की होगी। रोबोट के रोजगार पर पड़ते प्रभाव को देखते हुए भारत में रोबोट के इस्तेमाल की इच्छुक कंपनियों पर इसके प्रयोग के लिए 'जॉब परमिट फॉर रोबोट' का शुल्क लगाया जाए। तीसरी चुनौती, तकनीकी बदलावों और नवाचारों से सामंजस्य स्थापित करने की होगी।

पूरी दुनिया में चौथी औद्योगिक क्रांति को लेकर अटकलें और तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में भारत के लिए भी करीब पांच करोड़ तकनीक सक्षम कर्मचारी तैयार करने की चुनौती है। लिहाजा डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते रुझान को अपनाकर ही भारत बेरोजगारी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपट सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत में शैशवावस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां एआइ का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआइ के प्रयोग से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच बनाने में उत्पन्न बाधाओं को हल करने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां कनेक्टिविटी की समस्या तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। एआइ के प्रयोग से बीमारियों का पता लगाने, उनका निदान बताने, संभावित महामारी की प्रारंभिक पहचान और इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स को सरल बनाया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र की तरह विनिर्माण, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग, खेल, साइबर सुरक्षा व अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों में भी इस एआइ तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में काफी लाभदायक साबित हो सकता है। एआइ के अलावा डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी हैं, जिनमें रोजगार और धन के लाभ की अपार संभावनाएं हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2023 तक एक खरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 20 अरब डॉलर है। भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने तथा इंजीनियरों की प्रतिभा का देश में ही उपयोग करने के लिए ऐसी औद्योगिक नीति की जरूरत है, जो शोध-विकास के साथ जोखिम उठाने में विश्वास रखती हो।

निजता संबंधी नीतियों की अनदेखी

मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

आज इंटरनेट और मोबाइल फोन हर क्षेत्र का आधार बन चुका है। बढ़ती तकनीक के जरिये आज लोगों की ना सिर्फ जिंदगी आसान हुई है, बल्कि इस वजह से कई सारी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। हम रोज इंटरनेट के जरिये अनेक जानकारी लेते-देते हैं, पर इन सबके बीच हम यह भूल जाते हैं कि हम अपनी जानकारी का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, और हमारी निजता इससे किस तरह से प्रभावित हो रही है।

इंटरनेट एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया है, जो आपको कुछ इस तरह बांधने की क्षमता रखती है कि जिससे दूर होना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हर रोज हम अलग-अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अलग-अलग वेबसाइट से जुड़ते हैं, तरह तरह के एप डाउनलोड करते हैं। ऐसा करते वक्त कई बार हम अपनी निजी जानकारी जैसे अपना नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आइडी वगैरह का इस्तेमाल भी ऑनलाइन करते हैं और इसको एक आम प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हैं। पर क्या आपको पता है कि निजता का मुद्दा आज के समय में एक व्यापक समस्या का कारण बन चुका है। आपका डाटा आपकी पहचान है और इस पर कंपनियों की नजर आपको हानि पहुंचा सकती है। यह मुद्दा हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। आज इंटरनेट पर ऑनलाइन एप्स और वेबसाइट्स की भरमार है। कई बार हमें कोई एप रोचक लगती है तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद एप हमारे फोन में कई सारे परमिशन मांगते हैं और अक्सर एप को इस्तेमाल करने की जल्दी में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम किसी एप को परमिशन दे रहे हैं, तो हम उसको हमारी निजी जानकारी जैसे हमारे कांटेक्ट, हमारी गैलरी वगैरह में झांकने का मौका दे रहे हैं और यह काम वे हमारी जानकारी में करते हैं, पर जागरूकता के अभाव में हम मौसम की जानकारी देने वाले किसी एप को भी अपने कांटेक्ट को देखने की अनुमति दे देते हैं। अब मौसम की जानकारी वाला एप हमारे कांटेक्ट की जानकारी क्यों चाहता है यह सोचने की फुर्सत किसे है।

आप एक समस्या से बचने के लिए एक एप डाउनलोड करते हैं, लेकिन उससे जुटाई गई आपकी ही जानकारी आपके लिए दूसरी समस्या पैदा कर देती है। उससे बचने के लिए हम दूसरा एप डाउनलोड करते हैं, इस तरह डाटा का कारोबार लगातार फलता-फूलता रहता है और हमारा ही डाटा कई गुणकों में तब्दील होता जाता है। अक्सर हम जब कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई एप डाउनलोड करते हैं, तो एक लंबी-चौड़ी प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन की सूची हमारे सामने आ जाती है। अधिकांश लोग यह गोपनीयता नीति नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उनका मानना है कि उसमें क्या लिखा है, वह उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल इसका मकसद मुख्यतया कंपनी को कानूनी तौर पर किसी दायित्व से बचाना होता है, ना कि उपभोक्ता को सूचित करने का।

सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार आपकी निजी जानकारी की वकालत करता है जिसके अनुसार हर व्यक्ति को यह निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी जानकारी का उपयोग कौन और किस उद्देश्य के लिए कर सकता है। डाटा उल्लंघन के मामले लगभग हर रोज होते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग समस्या की गंभीरता को तब तक नहीं समझते हैं, जब तक यह व्यक्तिगत रूप से पहचान की चोरी या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के माध्यम से उन्हें प्रभावित नहीं करते। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व होता है। हम डिजिटल तो हो रहे हैं, पर शायद आज भी उसके लिए तैयार नहीं हैं। आज सरकार के साथ-साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि वह अपना डाटा किस कंपनी को दे रहे हैं, वह डाटा किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और डाटा से संबंधित कंपनी की क्या पॉलिसी है। साथ ही उपभोक्ता की जानकारी सुरक्षित रखना कंपनियों का दायित्व है, और वे उस जानकारी के प्रति जवाबदेह हैं। साइबर गोपनीयता जैसे मामलों पर एक मजबूत ढांचे की आज देश को जरूरत है जिससे हमारा भारत तकनीक की दौड़ में बाकी देशों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।

खरी-खरी

शब्दों की जुगलबंदी चालू आहे

आशीष दशोत्तर

शब्द आहत थे। चिंतित भी। विचारमग्न भी। कर्णधारों के आचरण से प्रचलन में आए इन शब्दों को अचानक इस तरह के प्रतिबंध की उम्मीद नहीं थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यदि इनके श्रीमुख से उनका उच्चारण नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। इनके मन में हम नहीं रहेंगे तो हमारा कोई नामलेवा नहीं रहेगा। इनके कर्म में हम अभिव्यक्त नहीं हुए तो हमारा कोई प्रयोग नहीं करेगा। हम चलन से बाहर हो जाएंगे। जब पूछपरख नहीं होगी तो होना, न होना बराबर। वैचारिक द्वंद्व से गुजरते इन शब्दों ने मिलकर विमर्श किया।

जुगलबंदी के इस आयोजन में गहरा मौन छाया हुआ था। इस निस्तब्धता को तोड़ते हुए 'जूतमपैजार' ने कहा कि मेरा तो इस्तेमाल इन सज्जनों से है। समाज में जिन्हें सज्जन कहा जाता है, वे लोग तो इतने निष्ठुर हैं कि कभी मेरा इस्तेमाल ही नहीं करते। ये तो भला हो इन नीति-नियंताओं का जो हर बैठक, हर आयोजन में मेरे कद और महत्व को बढ़ाते रहते हैं। जूतमपैजार के इस वक्तव्य पर सहमति जताते हुए 'छीछालेदर' ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसका कहना था कि ये लोग भी अगर आपस में शालीनता से मिलेंगे, बतियाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। स्वार्थी समाज में मेरा इस्तेमाल कोई करता ही कहां है।

इन बातों को ध्यान से सुन रहे 'लट्ठमलट्ठ' ने गहरी सांस छोड़ी। ये मानवता के मकोड़े अगर बात-बात पर आपस में नहीं भिड़ते और वहां व्यवस्था लट्ठ नहीं रखती तो मेरा तो मरण हो गया होता। अब जहां ये मकोड़े होते हैं, वहां मेरा होना अनिवार्य सा हो गया है। इतनी लंबी परंपरा को मैं खत्म नहीं होने दूंगा।

पिछले कुछ दिनों से अतिव्यस्त चल रहे 'गुत्थमगुत्था' ने कहा, दो महीनों के चुनाव प्रचार में आज पहली बार इतनी देर चैन से बैठा हूं। हर पल मेरा इस्तेमाल ये महानुभाव कर रहे थे। अब मैं नहीं हूं तो ये क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। इस पतन को हमें रोकना होगा।

इस चर्चा को लंबे समय से सुन-सुनकर 'गालीगलौच' के तो आंसू बहे जा रहे थे। उसे सांत्वना देने आगे आई 'बयानबाजी' ने कहा, यूं हिम्मत नहीं हारते। मुझे देखो, कितना सह रही हूं। यदि ये हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। संकट की घड़ी में हम मिलकर रहें। चार दिन बाद फिर इनके मन, वचन और कर्म से हम ही उच्चारित होंगे।

ट्वीट-ट्वीट

एसटीएफ के सूत्रों की मानें तो कमलेश तिवारी के हत्यारों ने अपने फुटप्रिंट्स जानबूझकर छोड़े हैं। दरअसल उनका मकसद न सिर्फ कमलेश तिवारी की बेरहमी से हत्या करना था, बल्कि यह भी जताना था कि हत्या उन्होंने ही की है।

स्वाति गोयल शर्मा@swati_gs

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निजी उपभोग से संचालित होती है, लेकिन निवेशक और उपभोक्ता सरकार में भरोसा खो रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वयं दोषी है। उसने खर्च या मांग को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं।

अरुण पुरी@aroonpurie

रांची में चल रहे टेस्ट मैच को देखकर यही महसूस होता है कि अगर भारत के पूर्वी इलाके में सूर्योदय जल्दी हो जाता है तो हम वहां खेल की शुरुआत आधे घंटे पहले क्यों नहीं कर देते? जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइम जोन हो सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं? इस बारे में हमें नए सिरे से विचार करना चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी@DrAMSinghvi

महाराष्ट्र डायरी

जहां सुमति तहं संपति नाना...

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परिणामों का इंतजार हो रहा है। 24 अक्टूबर को दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि सत्ता का ताज किसके सिर रखा जाना है। ऐसे में कुछ पुरानी घटनाएं और गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई याद आने लगी है। घटनाओं का जिक्र बाद में करते हैं। पहले चौपाई याद कर लेते हैं। चौपाई है- 'जहां सुमति तहं संपति नाना। जहां कुमति तहं विपति निधाना।।' तुलसी बाबा ने यह चौपाई सुंदरकांड में किसी संदर्भ में कही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि जहां लोग सुमति यानी अच्छी बुद्धि से रहते हैं वहां हर प्रकार की सुख-समृद्धि आती है। और जहां कुमति का वास होता है वहां विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं।

महाराष्ट्र का 1999 का विधानसभा चुनाव शिवसेना-भाजपा गठबंधन द्वारा लगभग पांच वर्ष की सत्ता भोगने के बाद आया था। उस सत्ता के शुरुआती चार वर्ष तक शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री एवं भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री थे। उस समय सीटों का समझौता करते हुए यही तय भी हुआ था कि गठबंधन में जिसकी सीटें अधिक होंगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा और जिसकी कम होंगी उसका उपमुख्यमंत्री होगा। यही समझौता 1999 के बाद भी चलना था, लेकिन चुनाव आने से छह माह पहले ही शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटा नारायण राणे को सत्ता सौंप दी थी। उस समय शिवसेना 171 और भाजपा 117 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भाजपा जानती थी कि शिवसेना से इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़कर वह उससे अधिक सीटें नहीं ला सकेगी। इसलिए मुंडे के मुख्यमंत्री बनने का अवसर कभी नहीं आएगा। भाजपा दोनों पार्टियों के ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने का नया फॉर्मूला अपनाना चाहती थी। शिवसेना तैयार नहीं थी। चुनाव परिणाम आए तो शिवसेना को पिछले चुनाव से चार सीटें कम यानी 69 व भाजपा को पिछले चुनाव से नौ सीटें कम यानी 56 सीटें मिली थीं। दोनों को मिला 125 सीटें हो रही थीं जो सरकार बनाने की जादुई संख्या से 20 कम थीं।

दूसरी ओर कांग्रेस और राकांपा, दोनों वह चुनाव अलग-अलग लड़े थे। वास्तव में कुछ माह पहले ही शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया था। दोनों दलों में कटुता भी चरम पर थी। चुनाव में तितर-बितर हो चुकी कांग्रेस ने 75 सीटें एवं नई बनी राकांपा ने 58 सीटें जीती थीं। कोई उम्मीद नहीं थी कि दोनों दल साथ आकर सरकार बनाने की बात भी करेंगे। कांग्रेस, राकांपा, एवं शिवसेना-भाजपा गठबंधन को छोड़कर 30 सदस्य अन्य छोटे दलों के या निर्दलीय जीतकर आए थे। इनमें आठ-दस ऐसे थे जो वैचारिक कारणों से किसी कीमत पर शिवसेना-भाजपा के साथ नहीं आ सकते थे, लेकिन 20-22 को अपने साथ लाने की बात तब शिवसेना की कमान संभाल रहे नारायण राणे करते आ रहे थे। किंतु गोपीनाथ मुंडे कम से कम ढाई साल के मुख्यमंत्री पद का आश्वासन मिले बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। भाजपा-शिवसेना के बीच 'कुमति' का यह नाटक पूरे 11 दिन चलता रहा और 18 अक्टूबर 1999 को कांग्रेस के विलासराव देशमुख ने मुख्यमंत्री और राकांपा के छगन भुजबल को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर मंत्रालय में जो विराजमान हुए तो अगले 15 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा की ही सत्ता रही। दूसरी ओर भाजपा को ये अवधि बगैर सत्ता के हाथ मलते ही गुजारनी पड़ी।

अब आते हैं 2004 के विधानसभा चुनाव पर। उस बार शिवसेना को 62, भाजपा को 54, कांग्रेस को 69 और शरद पवार की राकांपा को 71 सीटें प्राप्त हुईं यानी उस बार सबसे बड़ी पार्टी थी शरद पवार की राकांपा। कांग्रेस-राकांपा में भी गठबंधन की शर्तों के अनुसार मुख्यमंत्री उसी का बनना था, जिसकी सीटें ज्यादा थीं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पूरी तरह मुख्यमंत्री पद के लिए कमर कसे बैठे थे। दूसरी ओर कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थी। चुनाव सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस मराठावाद की राजनीति के कारण उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। शरद पवार चाहते तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह और खुद को मिली अधिक सीटों का लाभ लेते हुए मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 'सुमति' से काम लेते हुए मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को सौंप दिया। सत्ता फिर पांच साल के लिए कांग्रेस-राकांपा के हाथों में आ गई।

वर्ष 2014 में गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा-शिवसेना एक बार फिर गठबंधन कर चुनाव लड़े हैं। इस बार माहौल भी इस गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवसेना के मन में बड़े भाई का रुतबा छोड़ने की कसक और मंत्रालय पर शिवसेना का भगवा फहराने की लालसा बाकी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इसे कई बार सार्वजनिक रूप से प्रकट भी कर चुके हैं। अब तो उनके चिरंजीव आदित्य ठाकरे स्वयं सत्ता संभालने को तैयार हैं। दूसरी ओर अब शिवसेना को अधिक सीटें देकर स्वयं कम सीटों पर लड़ने को राजी हो जानेवाली मुंडे-महाजन की भाजपा भी नहीं रही। ऐसे में परिणाम आने के बाद देवेंद्र फड़नवीस एवं उद्धव ठाकरे को ज्यादा सुमति से काम लेना होगा। वरना दूसरी ओर महाराष्ट्र के बूढ़े शेर शरद पवार आज भी इन्हें धोबीपछाड़ देने को तैयार बैठे हैं।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या भीम यूपीआइ एप 2.0 देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा?

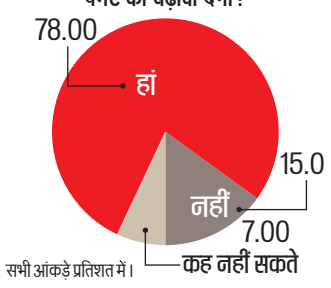

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सेना की कठोर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुसपैठ कराने से बाज आएगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गोले छूटें तोप के तो होता है दर्द,
फिर क्यों गोली छोड़कर बनते हो जी मर्द?
बनते हो जी मर्द दिखाओ अगर शराफत,
क्यों आए हर बार बंधु फिर तुम पे आफत!
सुनो मियां इमरान नहीं है अब हम भोले,
ये है हिंदुस्तान नया दागेगा गोले!!

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

ठोस विकल्प ही दिलाएगा प्लास्टिक से मुक्ति

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने की तैयारी के बीच हमें यह भी सोचना होगा कि इसका ठोस विकल्प क्या हो सकता है। साथ ही यह भी कि वह विकल्प कितना व्यावहारिक, खर्चीला और कारगर हो सकता है

देश-दुनिया में प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के कारण सरकार चाहती है कि देश प्लास्टिक मुक्त हो जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल समाप्त हो। देश में कई राज्यों में इस पर पाबंदी लगी है। पर प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी क्या बिना किसी व्यावहारिक विकल्प के संभव है?

जब प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना सामान्य नहीं हुआ था, दूध और शीतल पेय भी शीशे की बोतलों में आते थे। कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल का वजन अमूमन 20 से 25 ग्राम होता है। यही कोल्ड ड्रिंक जब कांच की बोतल में आती थी तो बोतल का वजन 200 से 250 ग्राम तक होने लगा। बोतल भारी होगी तो ढुलाई भी महंगी होगी। इस कार्य में ज्यादा तेल जलेगा, मतलब पर्यावरण कई गुना खराब होगा, दाम पर भी असर होगा। अमेरिकी केमेस्ट्री काउंसिल और पर्यावरणीय अनुसंधान करने वाली संस्था ने अपने एक शोध पत्र में कहा है कि अगर शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां प्लास्टिक की जगह कांच, एल्युमिनियम या टिन की बोतलों का इस्तेमाल करें तो इससे न उत्पाद का दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि इससे फैलने वाले पांच गुना ज्यादा प्रदूषण के चलते सरकार इन कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाएगी। ऐसे में कंपनी उत्पाद का दाम बढ़ाकर यह लागत ग्राहक से वसूलेगी।

प्लास्टिक के गुणों की बात करें तो इसके सहयोग से हरी सब्जियों की उम्र बढ़ जाती है। खाने को बर्बाद होने से बचाने में प्लास्टिक के रोल का बहुत बड़ा रोल है। प्लास्टिक में लिपटा खीरा फ्रिज में दो हफ्ते टिक सकता है, पर खुला हुआ दो दिन से ज्यादा मुश्किल से। सेब, अंगूर जैसे अनेक फल की बर्बादी 75 फीसद तक प्लास्टिक के चलते ही कम हो पाती है। खाने-पीने के सामान की उम्र केवल एक दिन बढ़ जाने से देश भर में कई करोड़ रुपयों की बचत हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसका खामियाजा अमूमन खाद्य सामग्री तैयार करने वाले निर्माता या खुदरा दुकानदार ज्यादा उठाते हैं। सबसे ज्यादा पाबंदी सिंगल यूज यानी केवल एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक पर है। दलील यह कि सबसे बड़ा खलनायक यही है। जितना

प्लास्टिक कचरा है, उसका आधा यही है। पर यह भी एक तर्क है कि इसी की वजह से खाने की चीजों की बर्बादी रुकती है। हालांकि दुनिया की बर्बादी का सामान साबित हो चुके इस प्लास्टिक के समर्थन में यह तर्क बहुत लचर है। सरकार और समाज ऐसे तर्कों को नहीं मानने वाला, जो प्लास्टिक के प्रयोग के समर्थन में हो, मानना भी नहीं चाहिए।

प्लास्टिक को निबटाने के तरीके ढूंढने में वैज्ञानिक कई दशक से लगे हुए हैं। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने प्लास्टिक और अलसी के सूखे पौधे को मिलाकर प्लास्टिक को निबटाने की युक्ति ढूंढी। कानपुर और मुंबई सरीखी आइआइटी संस्थाओं ने प्लास्टिक से ईंधन बनाने की तरकीब निकाली, आइआइटी दिल्ली में शोध कर रही एक छात्रा ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बाजार में मिल रहे डीजल जैसा डीजल बनाने के लिए किया। आइआइटी रुड़की ने प्लास्टिक से ईंट तथा टाइल बनाने में सफलता पाई। कचरा हो चुके प्लास्टिक को पिघलाकर और गेहूं, धान या मक्के की भूसी, जूट और नारियल के छिलकों को मिला कर उन्होंने यह बनाया है। प्लास्टिक से सड़कें भी बनाई गईं। यह पर्यावरण के लिए बेहतर है और बेहद सस्ती भी। हमारे पास प्लास्टिक कचरा भी व्यापक तादाद में है, पर उस अनुपात में आवश्यकता के बावजूद प्लास्टिक से सड़कें नहीं बन रहीं। दावा है कि प्लास्टिक गलाने वाला मशरूम ढूंढ लिया गया है। सवाल यह है कि आखिर वे क्या कारण हैं कि इस तरह की खोजें चलन में नहीं आ रहीं। भारत में क्या विदेशों में भी, क्या ये अवैज्ञानिक हैं, अधूरी हैं, अव्यवहारिक हैं, सरकार, प्लास्टिक लॉबी, बाजार इन्हें आगे आने देना नहीं चाहता, जन जागरूकता की कमी है या कोई और बात।

बहुत सी कंपनियां अपने आप नष्ट हो जाने वाली बायोप्लास्टिक बना रही हैं। ब्राजील में पैदा होने वाले गन्ने को मिलाकर तैयार होने वाला यह बायोप्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक से दोगुना महंगा है। बायोप्लास्टिक को वनस्पति तेल और लकड़ियों के बुरादे या छाल से भी बनाया जा रहा है। कोका-कोला ने वादा किया है कि वो ऐसी ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगी, हालांकि इससे उसकी लागत बढ़ेगी। कोका-कोला के अलावा नेस्ले, यूनीलीवर, पेप्सी और लॉरियल ने भी रीयूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने का वादा किया है। टेस्को और वालमार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय स्टोर्स ने पैकेजिंग में प्लास्टिक कम करने का भरोसा दिलाया है। बर्गर और सैंडविच की पैकेजिंग का सामान समुद्री खरपतवार से बना रहे हैं, इसमें पैकेजिंग को भी लोग खा सकते हैं, ये पोषक भी है और पर्यावरणमित्र भी। इतना सब होने के बावजूद कंपनियां वो तरीका नहीं खोज पाई हैं, जिनसे प्लास्टिक के इस्तेमाल में कटौती कर सकें, उसका सही विकल्प तलाश सकें।

सरकारों को सिंगल यूज प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हर प्रकार के नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने और उसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक की लत को छुड़ाना कठिन है। आखिर इस प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करने के लिए ऐसा क्या करें जो व्यावहारिक हो और उम्मीद बढ़ाने वाली भी। उपाय बहुतेरे हो सकते हैं, वे कारगर और शुरुआती स्तर पर एक हद तक कामयाब होते भी दिख सकते हैं, पर यह ध्यान रखना होगा कि इलाज कहीं नई बीमारी न बन जाए। अचानक इस पर पाबंदी लगी, तो इसकी कीमत हम कई तरह से चुकाएंगे।

(इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर)

25 फीसद अधिकारियों को जोनल कार्यालयों में भेजने का फैसला लिया है रेलवे बोर्ड ने। इसके तहत निदेशक और इससे ऊपर के 50 अधिकारियों का देशभर में जोनल कार्यालयों में ट्रांसफर किया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 22 अक्टूबर 2019

डाटागीरी

अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में घट रहे विदेशी छात्र

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अमेरिका की वीजा नीति और एच-1बी वीजा कार्यक्रम में बदलाव के चलते वहां के बिजनेस स्कूलों के कई प्रोग्रामों में विदेशी छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनजीओ ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल (जीमैक) ने रिपोर्ट जारी कर इसकी पुष्टि भी की है। अब बिजनेस स्कूलों के डीन और सीईओ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नियमों में सुधार की मांग की है...

पिछले हफ्ते अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रमुख बिजनेस स्कूलों के 50 डीन और 13 सीईओ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुला पत्र लिखकर देश की वीजा नीति और एच-1बी वीजा कार्यक्रम में सुधार की मांग की है। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ के उस अध्ययन को सही बताया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में कमी आई है। कई प्रोग्रामों में छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। गैर लाभकारी संस्था ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल (जीमैक) ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी साझा की है। इसमें बताया गया है कि 2016 से 2018 तक अमेरिका के बिजनेस स्कूलों के ज्यादातर प्रोग्रामों में विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट आई है।

2019 की बात करें तो अमेरिकी बिजनेस स्कूलों के 48 फीसद प्रोग्राम ऐसे हैं, जिनमें आवेदन देने वाले दूसरे देशों के छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, केवल 30 फीसद प्रोग्रामों में विदेशी छात्रों के आवेदन बढ़े हैं, जबकि 22 फीसद प्रोग्रामों में कोई बदलाव नहीं आया है। 2018 में 53 फीसद बिजनेस प्रोग्रामों में विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि केवल 28 फीसद प्रोग्रामों में ही वृद्धि हुई थी। 19 फीसद प्रोग्राम ऐसे थे, जिनमें कोई परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया था। यानी उनमें विदेशी छात्रों की संख्या स्थिर थी। जीमैक ने इस गिरावट के लिए अमेरिकी वीजा नीतियों, आवज्रन पर कठोर बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। इनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों को चुन रहे हैं।

भारतीय बिजनेस स्कूलों की यह है स्थिति : भारत के 28 बिजनेस स्कूलों के मुताबिक, यहां के प्रोग्रामों में आवेदन करने वालों की संख्या लगभग पिछले वर्ष के समान ही है। 46 फीसद प्रोग्राम ऐसे हैं, जिनमें भारतीय छात्रों के आवेदन अधिक आए हैं, जबकि 25 फीसद प्रोग्रामों में छात्रों की संख्या स्थिर हैं। हालांकि, 29 फीसद प्रोग्रामों में भारतीय छात्रों ने कम रुचि दिखाई है। दूसरी तरफ भारतीय संस्थानों में 12 फीसद प्रोग्राम ऐसे हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 84 फीसद प्रोग्रामों में विदेशी छात्रों की संख्या स्थिर है। मात्र चार फीसद प्रोग्राम ऐसे हैं, जिनमें विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

साल दर साल अमेरिकी बिजनेस स्कूलों के प्रोग्रामों में विदेशी छात्रों के आवेदन की स्थिति

वर्ष	वृद्धि	कमी	स्थिर
2014	44	38	19
2015	44	35	21
2016	40	39	21
2017	32	48	20
2018	28	53	19
2019	30	48	22

(प्रोग्राम प्रतिशत में)

भारतीय बिजनेस स्कूलों के प्रोग्रामों की स्थिति (2019 में)

आवेदन करने वाले	वृद्धि	कमी	स्थिर
भारतीय छात्र	46	29	25
विदेशी	12	4	84
छात्राएं	63	26	11
कुल	50	39	11

(प्रोग्राम प्रतिशत में)

खेती-बाड़ी को कॉरपोरेट रूप देकर बदली तस्वीर

रंग लाई मेहनत ▶ अभिषेक की पहल से समृद्ध हो रहे औरंगाबाद के किसान, ग्रीन-टी का कर रहे उत्पादन

अपनी कंपनी बनाकर बेच रहे बाजार में

मनीष कुमार, औरंगाबाद

बिहार के औरंगाबाद के कई गांवों में लेमनग्रास व मोरिंगा की खेती लहलहा रही है। रबी और खरीफ फसल का मोह छोड़कर किसान इसके साथ-साथ तुलसी का भी उत्पादन कर रहे है। इनके सम्मिश्रण से ग्रीन-टी बनाई जाती है। पूरी तरह हर्बल और औषधीय। सेहत के लिए फायेदमंद और स्वाद में भी लाजवाब। कंपनी के नाम (कादंबनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी) से ही किसानों का सीधा वास्ता है। कंपनी की ग्रीन-टी अब औरंगाबाद की सीमा लांघकर दूसरे प्रदेशों के बाजारों में अपनी पहचान बना चुकी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है यहां खेती-किसानी को कॉरपोरेट रूप दे दिया गया है और इसका श्रेय जाता है औरंगाबाद के ही अभिषेक को।

जनसंख्या नियोजन

कंपनी की बुनियाद अभिषेक ने डाली थी और उन्हीं के नेतृत्व में बरौली गांव के किसान आज भविष्य के नए सपने देख और साकार कर रहे हैं। इसी गांव के निवासी अभिषेक ने पुणे से प्रबंधन की पढ़ाई की है। कुछ दिनों तक एक निजी कंपनी में बतौर प्रबंधक काम किया, लेकिन मन नहीं लगा। उसके बाद वह खेती के मैदान में उतर आए। 2011 से वह उन्नतशील किसान बन गए। पॉली हाउस में जरबेरा, आर्किड फूल, लिलियम आदि की खेती करने लगे। उसी के साथ ग्रीन-टी का उत्पादन भी।

बिहार के औरंगाबाद जिला के बरौली गांव में अभिषेक द्वारा की गई लेमनग्रास व मोरिंगा की खेती देखते नाबार्ड के जिला प्रबंधक वकार आलम। जागरण

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सम्मान प्राप्त करते अभिषेक कुमार। फाइल

सीमा लांघ गई प्रेरणा : अभिषेक की प्रेरणा से कई किसान ग्रीन-टी के उत्पादन में सहभागी बने। औरंगाबाद में मदनपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित घोरहत गांव में संजय सिंह, बारुण के बरौली में अभिषेक, तेंदुआ में आलोक कुमार और मौआर खैरा में मुकेश मौआर ने बड़े पैमाने पर लेमनग्रास, मोरिंगा और तुलसी की खेती की है। प्रति एकड़ लाख रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ। इस कामयाबी की चर्चा बिहार के दूसरे जिलों में भी पहुंची। आज पटना, नवादा, छपरा, बांका और लखीसराय के किसान भी लेमनग्रास, मोरिंगा और तुलसी की खेती करने लगे हैं। इससे किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं।

कामयाबी की नई कहानी : अभिषेक के गांव बरौली में ही ग्रीन-टी का उत्पादन होता है। किसानों के खेत से ही हर्बल व औषधीय फसल खरीद ली जाती है। नकद भुगतान होता है। जिला कृषि पदाधिकारी राजेश प्रताप सिंह किसानों के लिए अभिषेक को प्रेरणास्रोत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उनके अभिनव प्रयोग प्रायः सफल रहे हैं। कंपनी बनाकर तो उन्होंने कामयाबी की नई कहानी लिख दी है।

कई पुरस्कार व सम्मान किए हासिल : कृषि में तरह-तरह के प्रयोग और सफल किसानी के लिए अभिषेक को कई सम्मान मिले हैं। इस साल अगस्त में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें अटल मिथिला पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2014 में भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार के सर्वोच्च प्रगतिशील किसान का सम्मान दिया था। 2016 में कृषि रत्न सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा भी सफल खेती के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

बिजली की कम खपत कर प्रदूषक कणों का डाटा एकत्र करेगी नई डिवाइस

टेक्नो वर्ल्ड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइआइटी दिल्ली की दो छात्राओं ने विकसित की तकनीक
- सौर ऊर्जा से चलने वाली डिवाइस 10 किमी दूर तक पहुंचाएगी डाटा

वर्तमान में प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। इससे निपटने के लिए तभी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, जब प्रदूषण कणों को सही तरह से और कम ऊर्जा खपत कर मापा जा सके। इस कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली की दो छात्राओं ने बड़ी सफलता हासिल की है। पायली दास और सुष्मिता घोष ने ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो 5जी तकनीक से लैस है और सौर ऊर्जा का प्रयोग कर प्रदूषक कणों का डाटा एकत्र करती है।

पीएचडी की छात्रा पायली दास ने बताया कि इस डिवाइस की खासियत है कि यह बहुत कम बिजली की खपत से तेजी से प्रदूषक कणों के डाटा को मेन सर्वर में भेजने में सक्षम है। इस डिवाइस में नौ सेंसर लगाए गए हैं, जो प्रदूषक कण जैसे पीएम 1, पीएम 2.5 और पीएम 10 को मापेंगे। साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसों का डाटा भी एकत्र करेंगे। इसके अतिरिक्त यह डिवाइस तापमान और हवा की नमी को मापने में भी सक्षम है। इसमें एक बैट्री लगाई गई है जो इसी डिवाइस में लगे सौर पैनल से चार्ज होगी। पायली ने बताया कि एक बार में मेन सर्वर में प्रदूषक कणों के डाटा को भेजने में 3.5 माइक्रो वाट बिजली लगेगी। हम एक घंटे में दो बार डाटा भेजेंगे। एक घंटे में वाई-फाई के जरिये दो बार डाटा भेजने में 130 मिली वाट बिजली की खपत होती है, जबकि इस डिवाइस से सिर्फ सात माइक्रो वाट की ही खपत होगी। पायली के मुताबिक, इस डिवाइस की क्षमता 10 किलोमीटर तक है। 10 किलोमीटर के दायरे में यह डिवाइस मेन सर्वर को डाटा भेजने में कारगर है। पायली और सुष्मिता मूल रूप से अगरतला की रहने वाली हैं। पायली दास ने अगरतला स्थित त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआइटी) से एमटेक की और फिर इसी वर्ष जून 2019 में आइआइटी दिल्ली में पीएचडी में दाखिला लिया। वहीं, सुष्मिता घोष ने अगरतला की एनआइटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की और यहीं से ही एमटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने भी इसी वर्ष आइआइटी दिल्ली में पीएचडी में दाखिला लिया है।

पायली दास और सुष्मिता घोष डिवाइस के साथ। जागरण

बाइक से सफर कर बनाया 786, अब 'ओम' के लिए यात्रा कर रहे अख्तर

मप्र के बुरहानपुर में बाइक से शांति का संदेश लेकर देश भ्रमण पर निकले अख्तर पटेल। नईदुनिया

नईदुनिया, बुरहानपुर (मप्र)

पहल

- शांति व एकता का संदेश दे रहे मुंबई के बाइक राइडर

देश में शांति और एकता का संदेश देने के लिए लोग कई तरह के अभियान चलाते हैं, लेकिन मुंबई के अख्तर पटेल ने अपने शौक को ही शांति के पैगाम का जरिया बना लिया है। वह बाइक राइडर हैं और लंबे समय से इसके जरिये अमन और शांति का संदेश दे रहे हैं। वह 'राइड फॉर पीस' और 'हम सब एक हैं' का मूल मंत्र लेकर चारों प्रमुख धर्मों के प्रतीक चिह्न 786, ओम, क्रॉस व सिख धर्म के चिह्न बुलेट से सफर तय कर देश के भौगोलिक नक्शे पर बनाना चाहते हैं।

पहले चरण में अख्तर ने वर्ष 2017 में 8786 किमी का सफर तय कर मुस्लिम धर्म का पवित्र अंक '786' बनाया था। यह सफर उन्होंने कुल 24 दिन में तय किया था और इस दौरान वह सात प्रदेशों में पहुंचे थे। गत 13 अक्टूबर को वह दूसरे चरण में ओम बनाने के लिए (ओम आकृति के नक्शे के मुताबिक यात्रा) 9786 किमी की यात्रा पर निकले हैं।

उन्हें विश्वास है कि करीब 30 दिन में वह यह सफर पूरा कर लेंगे। इस दौरान भी वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत सात प्रदेशों से गुजरेंगे। अख्तर पटेल ने रोजाना करीब 400 किमी यात्रा का संकल्प लिया है। यात्रा के दूसरे पड़ाव के दौरान अख्तर बीते दिनों मप्र की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर पहुंचे। लोगों से यहां का इतिहास जानने और ऐतिहासिक विरासतों को देखने की मन में उठी तीव्र इच्छा के चलते वह यहां एक दिन रुके भी। इस दौरान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सिटी वॉक में भी शामिल हुए।

अगले चरण में क्रॉस बनाएंगे : अपने संकल्प के मुताबिक, ओम चिह्न बनाने के बाद अगले चरण में अख्तर पटेल ईसाई धर्म का प्रतीक चिह्न क्रॉस बनाने के लिए करीब 5786 किमी की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे 18 दिन में 11 प्रदेशों से गुजरेंगे। इसके बाद सिख धर्म के चिह्न के लिए यात्रा शुरू करेंगे। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया को अख्तर ने बताया कि वह लोगों को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत एक है और यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोग एक हैं। उन्हें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। धर्म और जात-पात के भेदभाव से ऊपर उठकर देश की तरक्की के विषय में काम करना चाहिए।

दुनिया को बदल रही है थ्री-डी प्रिंटिंग

फोटो न्यूज

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : विज्ञान के विकास के साथ बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। थ्री-डी प्रिंटिंग के क्षेत्र में हाल ही में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। **यह तस्वीरें रूस में तैयार किए गए थ्री-डी बायोप्रिंटर की हैं, जो माइक्रोग्रैविटी में चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके खरगोश और मछली के ऊतक तैयार कर सकता है।** इसे अमेरिका, रूस और इजरायल की कंपनियों ने मिलकर तैयार किया गया है। बीते दिनों इसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किया गया। इस प्रिंटर को अंतरिक्ष स्टेशन में प्रयोग के लिए तैयार किया गया है, ताकि वहां रह रहे वैज्ञानिकों को खाने की दिक्कत न आए। इसके जरिये वैज्ञानिक कई प्रयोग भी अंतरिक्ष में कर सकेंगे।

क्या है यह तकनीक

आप एक सामान्य प्रिंटर से तो परिचित ही होंगे, जिसमें एक कागज पर छपाई होती है। थ्री-डी प्रिंटिंग उससे एक कदम आगे किसी वस्तु को तैयार करने का काम करती है। इसके जरिये सिर्फ विभिन्न मैटेरियल से खिलौने, जूत आदि ही नहीं, बल्कि घर तक तैयार किए जा रहे हैं। पिछले साल फ्रांस में थ्री-डी प्रिंटिंग की मदद से घर तैयार किए गए, जिसका निर्माण करने वाली कंपनी का दावा है कि ये घर 100 साल तक बिना किसी नुकसान के टिके रह सकते हैं।

किस तरह करती है काम

इस तकनीक में सबसे पहले एक डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसका डाटा कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। फिर किस मैटेरियल से चीज को तैयार करना है उसकी जानकारी डालते हैं। जैसे-कांच, धातु, कागज, प्लास्टिक, रबड़ आदि। इसके बाद विशेष प्रिंटर (हर वस्तु को तैयार करने लिए अलग थ्री-डी प्रिंटर होता है) में उस मैटेरियल को रखा जाता है और वह वस्तु प्रिंटर में तैयार हो जाती है। इसके जरिये जूते, खिलौने, वाहनों के कल-पुर्जे आदि चीजें तैयार की जा सकती हैं। इन्हें तैयार करने में लगने वाला समय कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक का हो सकता है। मसलन, जूता आदि तैयार करने में कुछ घंटे लगते हैं, जबकि फ्रांस में तैयार किए गए थ्री-डी घरों को बनाने में 18 दिन का समय लगा था।

मप्र में शुद्ध के लिए युद्ध, फिर भी मिलावटखोरों के हौसले चुस्त

वरुण शर्मा, ग्वालियर

बिग न्यूज

दूध में मिलावट को लेकर बीते सप्ताह आई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की रिपोर्ट में पैकेट दूध के 37.7 फीसद और खुले दूध के 47 फीसद सैंपल फेल हो गए। जिन तीन राज्यों में दूध की गुणवत्ता सबसे खराब पाई गई उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। देश का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश दूध व अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए पहले से ही कुख्यात रहा है। इस रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार सख्ती नहीं कर रही है। यहां 'शुद्ध के लिए युद्ध' जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मिलावटखोरों पर कार्रवाई भी जारी है। इन सबके बावजूद इस पर लगाम लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। त्योहार के सीजन में ये चुनौति और भी बढ़ गई है। जानते हैं अब तक मिलावटखारों पर क्या कार्रवाई की गई और उसके क्या परिणाम सामने आए...

मध्य प्रदेश में कई महीनों से दूध में 'उबाल' जारी है। यह दूध को कीटाणुरहित करने के लिए नहीं, बल्कि मिलावटखोरों पर की जा रही सख्ती का 'उबाल' है। मप्र में दूध में मिलावट के लिए कुख्यात ग्वालियर-चंबल अंचल में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, लेकिन मिलावट रुकने का नाम नहीं ले रही है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के देश के 1103 शहरों में किए गए सर्वे में सबसे कम गुणवत्ता के दूध वाले शीर्ष तीन प्रदेशों में मध्य प्रदेश शामिल है। इस सर्वे ने प्रदेश में अशुद्ध, मिलावटी व अमानक दूध की आपूर्ति पर मुहर लगा दी है। मप्र में यह स्थिति तब है जब गत 19 जुलाई से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चला रहा है। इसमें गत 16 अक्टूबर तक 31 कारोबारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा चुका है।

मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय करने वाले कारोबारियों के खिलाफ 89 एफआइआर दर्ज की गई हैं। दूध में मिलावट के धंधे में प्रदेश ही नहीं, देशभर में ग्वालियर-चंबल संभाग शीर्ष पर है। दूध में डिटर्जेंट-यूरिया की मिलावट तो आम बात हो गई है। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत भिंड, मुरैना और ग्वालियर में सफेद दूध के काले कारोबार को बंद करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन मिलावटखोरों के तगड़े नेटवर्क को खत्म करना अब भी चुनौती है।

यदि ग्वालियर-चंबल अंचल की बात करें तो इस अभियान में अब तक लगभग 1000 सैंपल, चार पर रासुका और 18 मिलावटखोरों पर एफआइआर दर्ज की गई है। इसके बाद भी मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं।

मुरैना में 425 सैंपल लिए, तीन पर रासुका व 18 पर एफआइआर : 19 जुलाई से लेकर अभी तक मुरैना में दूध व दुग्ध पदार्थों के 425 नमूने लिए गए हैं। इनमें से चार मिलावटखोरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजा गया। साथ ही 18 मिलावटखोरों पर थानों में एफआइआर दर्ज कराई गई। हाल यह है कि सिंथेटिक दूध बनाने वाले मिलावटखोरों ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं और वे अब ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम को कर रहे हैं। अंबाह में वनखंडेश्वर डेयरी पर 19 जुलाई को एसटीएफ व खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने पहली बड़ी कार्रवाई की थी। कार्रवाई में डेयरी पर सिंथेटिक दूध बनाने का केमिकल व सामग्री मिली थी। प्रशासन ने एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर करीब पौने तीन करोड़ का केमिकल, सिंथेटिक दूध बनाने की सामग्री को भी जब्त किया।

भिंड में तीन पर रासुका के प्रस्ताव, 143 नमूने लिए गए : यहां अभी तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 143 सैंपल लिए हैं। इनमें से सिर्फ 16 की रिपोर्ट आई है, जिसमें 13 फेल हो गए यानी 16 में से 13 नमूनों में मिलावट, अशुद्धता पाई गई। 11 स्थानों पर कार्रवाई के दौरान दूध और मावा बनाने में इस्तेमाल करने के लिए रखे घातक केमिकल और डिटर्जेंट पाउडर आदि जब्त किए गए। जिले में नकली दूध का कारोबार करने वालों पर कुल चार एफआइआर दर्ज की गई हैं। एसटीएफ ने लहार में जिन तीन कारोबारियों पर कार्रवाई की थी, उन तीनों के खिलाफ एसपी ने रासुका के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है, जो अभी लंबित है।

ग्वालियर में 425 सैंपल, एक पर रासुका, सात पर मुकदमे दर्ज : ग्वालियर में जुलाई से अब तक कई मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन मिलावटखोरी धड़ल्ले से जारी है। 21 जुलाई से अब तक ग्वालियर में 425 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें करीब 80 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें करीब 40 फीसद दूध मिलावटी, अमानक पाया गया है। मोहना में उम्मेद सिंह नामक आरोपित नकली दूध की फैक्ट्री चलाता पकड़ा गया जिस पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। सात कारोबारियों पर एफआइआर दर्ज कराई है। यहां करीब 35 लाख रुपये का जुर्माना मिलावटखोरों पर किया जा चुका है।

उठ रहा भरोसा : सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री, डिटर्जेंट-यूरिया का मावा, चींटियों से लिपटे हुए छैना इस तरह के उदाहरण मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई में सामने आए हैं। इनसे हर कोई शर्मसार हुआ है। आम जनता का भरोसा ही पूरी तरह टूट चुका है। लोगों के पास दुग्ध उत्पादों के विकल्प तो अभी नहीं हैं, लेकिन इस तरह के माहौल में वे हर दूध को शक की दृष्टि से देखने लग गए हैं।

इतने खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे : दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सोडियम पराक्साइड, लाइम स्टोन का पाउडर आदि मिलाने के मामले भी सामने आए हैं। नकली दूध बनाने के मामलों में कास्टिक सोडा, यूरिया, सस्ते डिटर्जेंट मिलाने के मामले भी उजागर हुए हैं। डिटर्जेंट से मिलावटी दूध में झाग बनता है। यही नहीं, मिलावट करने वाले कार्रवाई के दौरान यह तर्क देते हैं कि यह केमिकल वे सफाई के लिए रखते हैं। यह कल्पना ही भयावह है कि जिस केमिकल से वे फर्श व परिसर की सफाई की बात कह रहे हैं, वह दूध में मिलाया जाता है। मावा बनाने में इसी तरह के कई खतरनाक केमिकल उपयोग किए जाते हैं। जाहिर है यह सब भारी मुनाफे के लिए किया जा रहा है।

मिलावट के खिलाफ प्रदेशभर में कार्रवाई जारी है। ग्वालियर जिले में अभी तक की गई कार्रवाई में करीब 425 सैंपल लिए जा चुके हैं। जुर्माना लगाया जा रहा है। दूध और दूध के उत्पाद से लेकर हर तरह के खाद्य पदार्थ में इस तरह की मिलावट की जाती है कि जांच टीम तक हैरत में पड़ जाती है। सेहत से इस तरह का खिलवाड़ भी हो सकता है, विश्वास नहीं होता है।

- पुष्पा पुषाम, अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग, ग्वालियर

63 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में। इस मामले में देश का दुनिया में दूसरा स्थान है। देश में सिर्फ 16 फीसद महिलाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

मौत का सौदागर बांट रहा जिंदगी

दिलीप सिन्हा, गिरिडीह

जागरण विशेष

- जेल में बंद नक्सली को डॉक्टर साहब कहकर बुलाते कैदी और सिपाही
- कैदी ही नहीं, अधिकारी और उनके रिश्तेदार भी लेते हैं परामर्श

झारखंड के सेंट्रल जेल गिरिडीह में विचाराधीन कैदी रामचरण राम बंद है। उस पर चौकीदार की हत्या सहित कई नक्सली वारदात को अंजाम देने का आरोप है, लेकिन वह आज लोगों को जिंदगी दे रहा है। आयुर्वेद पर उसकी गहरी पकड़ है। इस कारण वह जेल में बंद कैदियों के बीमार होने पर इलाज करने के लिए प्रेरित हुआ। उसकी बताई गई दवाएं ऐसा काम करने लगी हैं कि कैदी ही नहीं जेल के कई अधिकारी भी अपने व परिजनों के बीमार होने पर उससे सलाह लेते हैं। जेल में बंद करीब 1100 बंदियों और जेल प्रशासन के बीच वह डॉक्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गया है।

रामचरण ने वैसे वैद्य की कोई डिग्री नहीं ली है। उसने बचपन से अपने वैद्य पिता के साथ रहकर और बड़े वैद्यों की सोहबत में रहकर यह ज्ञान पाया है। गिरिडीह के खुखरा थाना की पुलिस ने 25 जनवरी, 2018 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस पर आवास से हथियार व विस्फोटक बरामद होने का आरोप लगा था। वह जेल आया था, तब उसे अन्य बंदी एक नक्सली के रूप में देख रहे थे, लेकिन बहुत जल्द ही हर किसी के प्रति संवेदना का उसका भाव देख उसे सभी सम्मान देने लगे। इस बीच, उसने बीमार होने पर कुछ लोगों को परामर्श दिया। उसकी सुझाई गई दवाएं रामबाण की तरह काम करने लगीं तो जेल में उसकी पहचान आयुर्वेदिक डॉक्टर की हो गई। उसके मरीज जेल के बंदी तो थे ही, जेल अधिकारियों के रिश्तेदार भी उससे इलाज के लिए आने लगे। कई ऐसे रोगी भी उसके परामर्श पर आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं, जो किडनी की खराबी व कैंसर जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं। रामचरण के पिता ब्रह्मदेव राम और दादा लखराज राम वैद्य थे।

जेल के एक आरक्षी की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था। पटना में इलाज के दौरान ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। तब उसने जेल में बंद रामचरण से परामर्श लिया। उसकी बताई दवाओं के सेवन से ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और अब वह स्वस्थ है। एक पूर्व जेल अधीक्षक के बहनोई को किडनी संबंधी बीमारी थी। वह भी उसके परामर्श से दवाएं ले रहे हैं। अभी स्थित पहले से बेहतर है। रामचरण पेटरवार में एक वैद्य के यहां पिता के सुझाव पर 1971 में गया था। वहां दस साल रहकर जड़ी-बूटियों से इलाज का ज्ञान लिया। फिर पटना के वैद्य प्रभुदेव आचार्य के यहां जाकर जानकारी ली। दिल्ली एवं राजस्थान के भी कई वैद्यों से आयुर्वेद के गुर सीखे। तभी भाई की मौत हो गई और वापस गांव आ गया। यहां उसने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। यह वह दौर था, जब नक्सलवाद चरम पर था। उसका गांव भी नक्सल प्रभावित था। यहां से उसका रुख नक्सलवाद की ओर हो गया।

गिरिडीह के इसी जेल में बंद है विचाराधीन कैदी रामचरण। जागरण

ये हैं आरोप

- माओवादियों ने चौकीदार नंदलाल तूरी की हत्या की थी। इस कांड में रामचरण के साथ ही गांव के मांझो राम को पुलिस ने आरोपित बनाया था। इस मामले में गिरिडीह की अदालत ने दोनों को बरी कर दिया है।
- उसके आवास से विस्फोटक व हथियार बरामद होने का आरोप है।
- पुलिस पिकेट पर नक्सली हमले में शामिल होने का भी मामला चल रहा है।

रामचरण आयुर्वेदिक दवाओं से जेल में बंद मरीजों का इलाज करता है। जिन लोगों का इलाज किया है, उनको फायदा हुआ है। अभी तक किसी ने यह शिकायत नहीं की है कि दवा से फायदा नहीं हुआ।

– कोलेश्वर पासवान, जेलर

रामचरण के दो बेटे और एक बेटी है। उनकी पढ़ाई के प्रति वह हमेशा गंभीर रहा। बचपन से ही उनको शिक्षा का महत्व समझाया। दोनों बेटे स्नातक हैं। बेटी की शादी उसने एक इंजीनियर से की है। जेल जाने के कारण बेटों की पढ़ाई बाधित हुई थी, जो बाद में पटरी पर आ गई। रामचरण की इच्छा है कि बच्चे बड़े अधिकारी बनकर समाज की सेवा करें। वह खुद भी अंतिम सांस तक गरीबों का इलाज करना चाहता है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

बिना कोल्ड चेन के भी सुरक्षित रहेगी वैक्सीन

शिगेला संक्रमण की शिगोलोसिस वैक्सीन पर परीक्षण सफल, दो साल तक चला शोध

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

रोगों की रोकथाम के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखने की जरूरत नहीं होगी। अब इन्हें आम दवाओं की तरह ही सामान्य तापमान में रखा जा सकेगा। आइआइटी कानपुर के बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डीएस कट्टी और पीएचडी छात्रा नम्रता बरुआ ने ये तकनीक विकसित की है। शिगेला संक्रमण से बचाने के लिए लगाई जाने वाली शिगोलोसिस वैक्सीन पर इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है।

प्रो. कट्टी के मुताबिक, इसके लिए वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अभी तक 'शैफ्रान' होने के कारण सभी वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखा जाता है। दो साल तक चले शोध के दौरान सबसे पहले शिगोलोसिस वैक्सीन से शैफ्रान को अलग कर दिया और इसे चार माह तक सामान्य तापमान में रखा। कोई असर न पड़ने पर चूहों पर अध्ययन किया गया। वैक्सीन लगाने के बाद शिगेला संक्रमण के पांच गुना अधिक डोज दिए गए, लेकिन वैक्सीन ने अपना काम किया और चूहों पर संक्रमण का कोई असर नहीं हुआ। इस तकनीक का प्रयोग अन्य वैक्सीन पर भी किया जा सकता है।

अभी वैक्सीन को विशेष डिब्बों में रखा जाता है। प्रतीकात्मक

क्या है शिगेला संक्रमण : दूषित खाना, दूषित पानी व साफ-सफाई का ध्यान न रखने पर शिगेला संक्रमण होता है। यह एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जिससे मरीज के पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन, बुखार, दस्त एवं उल्टी के लक्षण मिलते हैं।

गांव-गांव वैक्सीन पहुंचाने में होगी आसानी : इस तकनीक की मदद से ऐसी वैक्सीन तैयार की जा सकती हैं, जिन्हें बिना कोल्ड चेन के दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाने में आसानी होगी। अभी तक कोल्ड चेन की कमी के कारण अक्सर गांव में टीकाकरण अभियान प्रभावित होते हैं। आइआइटी कानपुर की इस खोज से कई दिन सामान्य तापमान में रखने के बाद भी वैक्सीन की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा कोल्ड चेन न होने से हर साल खराब होने वाली लाखों खुराक वैक्सीन को भी बचाया जा सकेगा।

प्रयागराज के एसआरएन लैब की रिपोर्ट अब 80 देशों में होगी मान्य

मनीष मिश्र, प्रयागराज

- एनएबीएए की मान्यता मिली, जांच के बाद मरीज रेफर होने पर दोबारा टेस्ट नहीं कराने होंगे

अभी यह गंभीर संकट था कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (एसआरएन) से मरीज रेफर किए जाने पर डॉक्टर यहां की पैथोलॉजी की ब्लड और यूरिन जांच को नकार कर पुनः जांच कराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे मरीजों का खर्च भी बचेगा और परेशानी भी। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध इस अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में होने वाली जांच रिपोर्ट अब दुनिया के 80 देशों में मान्य होगी। इस लैब की जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ लैबोरेट्री (एनएबीएल) ने मुहर लगा दी है।

आइएसओ की टीम ने गत सितंबर में प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की लैब की गुणवत्ता की जांच की थी। इसमें गुणवत्ता व मशीनों के बारे में जानकारी ली थी। लैब में सभी तरह की मशीनें व तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध पाई गई थीं। इसके बाद एनएबीएल ने मान्यता दी है। अब यदि इस लैब में कोई जांच होती है तो वह विश्वसनीय मानी जाएगी। यदि मरीज को किसी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है तो डॉक्टर पुनः इन जांचों के लिए अब नहीं कह सकेंगे।

क्या है एनएबीएल : क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक घटक है एनएबीएल। इसका उद्देश्य सरकार और संबंधित उद्योग से जुड़ी कंपनियों की सेवाओं और उत्पादों का परीक्षण एवं प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता व तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करना है। यह दुनिया के 80 देशों में मान्य है।

गर्व की बात

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. वत्सला मिश्रा ने बताया कि हमारी लैब को एनएबीएल की मान्यता मिलना सबके लिए गर्व की बात है। इसके पहले किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, राममनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ व कुछ निजी अस्पतालों की लैब को यह मान्यता मिली है।

लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं को अलग से नहीं पहनानी पड़ेगी पोशाक

मनोज जादौन, अलीगढ़

इस बार दीपावली पर लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं को अलग से पोशाक नहीं पहनानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनिंदा शोरूम पर पीतल की कलरफुल एंटीक मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें कपड़े की जगह जस्ता दाना का प्रयोग किया गया है। इसके ऑर्डर देशभर से ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों से भी मिल रहे हैं। दीपावली पर घर-घर लक्ष्मी-गणेश का पूजन होता है। इसके लिए बाजार में एंटीक पीतल की मूर्तियां पहली बार तैयार की गई हैं। इस डिजाइन की अन्य मूर्तियां जैसे राधा-कृष्ण, रामदरबार आदि भी उपलब्ध हैं।

बाजार में यह तकनीक पहली बार प्रयोग की जा रही है। अब तक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस साल बजरी (बारीक जस्ता का दाना) का प्रयोग किया गया है। यह दाना हर रंग में आता है। यह पीतल की मूर्ति पर चिपकाया जाता है। यह मूर्ति से छूटे न इसके लिए लेमीनेशन कोडिंग की जाती है। पीतल की मूर्तियों पर बजरी दाने का बारीक वर्क होता है। इसमें पोशाक के रंग के हिसाब से कलर का मेल किया जाता है। ब्रास कलेक्शन ने इस काम के लिए बिहार से कुशल कारीगर नसीम, इमरान व शाहिद बुलाए हैं।

500 करोड़ का सालाना कारोबार : आर्टवेयर का कारोबार पिछले सालों से ठिठका हुआ है। आधा दर्जन निर्यातक विदेश में मूर्तियों को

अलीगढ़ में लक्ष्मी-गणेश की वे मूर्तियां जिन्हें अलग से पोशाक पहनने की जरूरत नहीं। जागरण

पहले ब्रास की सादा मूर्तियां, फिर गोल्ड पॉलिश, जस्ता, फिर स्टॉन वर्क और अब बजरी दाना वर्क की मूर्तियों की डिमांड है। विदेशी बाजार में यह पसंद की गई हैं। कुछ ऑर्डर भी भेजे हैं।

– कपिल वार्ष्णेय, निर्यातक

निर्यात करते हैं। 500 करोड़ के इस कारोबार में भी तमाम चुनौतियां हैं। कारोबारी कमल वार्ष्णेय ने कहा कि पहले डिजाइन की मांग होती थी। अब सजावटी मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। ग्राहक की पसंद का दायरा बढ़ गया है।

फुटकर बाजार में पीतल की मूर्ति के भाव

वैरायटी	दाम
सादा	600 से 650
गोल्ड पॉलिश	700 से 800
कलर फुल	750 से 800
स्टोन वर्क	700 से 800
बजरी दाना	900 से 950

(नोट : दाम रुपये में)

महाप्रभु की चरणपादुका वृंदावन पहुंचीं, गूंजा हरिनाम संकीर्तन

आज नगर में निकलेगी रथयात्रा

चैतन्य महाप्रभु के चरण पादुकोत्सव में मंगलवार सुबह 11 बजे वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में चरण-पादुका का पुष्पाभिषेक होगा। शाम 4.30 बजे स्वर्ण रथयात्रा शुरू होगी।

वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में पहुंची चैतन्य महाप्रभु की चरणपादुका की आरती उतारते चंद्रोदय मंदिर के चेयरमैन मधु पंडितदास। जागरण

जागरण संवाददाता, मथुरा

- नवद्वीप स्थित धामेश्वर मंदिर से सोमवार शाम को पहुंचीं चंद्रोदय मंदिर

भक्ति आंदोलन के अगुवा चैतन्य महाप्रभु की चरणपादुका एक बार फिर सोमवार को वृंदावन पहुंचीं। भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन के साथ स्वागत किया। चंद्रोदय मंदिर के प्रवेश द्वार पर ढोल बजे, पुष्प वर्षा हुई। चंद्रोदय मंदिर में चरणपादुका को पालकी में विराजमान किया गया। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन 504 साल पहले आए थे।

छटीकरा मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की दिव्य चरण पादुका सोमवार शाम साढ़े पांच बजे रॉल्स रॉयस कार में पहुंचीं। संस्था प्रमुख मधु पंडित दास ने चरण पादुका का माल्यार्पण कर स्वागत किया। गौड़ीय वैष्णव संतों ने हरिनाम संकीर्तन कर महाप्रभु की चरणप्रादुका को पालकी में विराजित किया। यहां चरणपादुका का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचगव्य व पंचामृत से महाभिषेक किया। अनुयाइयों ने दामोदराष्टकम का गायन कर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के समक्ष दीपदान किया।

संस्था प्रमुख मधु पंडित दास ने कहा कि यह दिव्य पादुका नवद्वीप (पश्चिम बंगाल) के धामेश्वर मंदिर में निवास करती है। यह चैतन्य महाप्रभु की मूल पादुका है। बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने से पहले अपनी पत्नी विष्णुप्रिया देवी को यह पादुका भेंट की थी। जिनकी आजीवन सेवा विष्णुप्रिया देवी ने की। धामेश्वर महाप्रभु मंदिर में पादुका का प्रतिदिन पूजन होता है।

इंजीनियरिंग के साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई कराएगा आइआइटी खड़गपुर

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- ऐसा करने वाला देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान, अगले साल से एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत
- साल के अंत तक मरीजों के लिए आउटडोर और इंडोर सेवाएं शुरू होने की भी उम्मीद

आइआइटी खड़गपुर देश का पहला आइआइटी होगा जहां इंजीनियरिंग के साथ-साथ छात्रों के लिए मेडिकल की भी पढ़ाई की सुविधा होगी। आइआइटी के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि अगले साल से पहले चरण में यहां 50 छात्रों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में एमबीबीएस सीटों की संख्या का विस्तार कर 100 किया जाएगा। बाद में मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट (स्नातकोत्तर) डिग्री कोर्स भी शुरू किया जाएगा।

अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रबंधन आइआइटी की ओर से ही किया जाएगा। अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) की अध्यक्षता आइआइटी खड़गपुर के निदेशक करेंगे जबकि वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर इसके सदस्य होंगे। इसे नॉन प्रॉफिट मॉडल पर यानी बिना लाभ के चलाया जाएगा। अस्पताल के 10 फीसद बेड मुफ्त रहेंगे। 65 फीसद बेड के लिए केंद्र व राज्य सरकार के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार तय शुल्क लिए जाएंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि अस्पताल शुरू होने के बाद मरीजों की भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए संस्थान ने मोबाइल हेल्थकेयर इकाइयां भी स्थापित करने का फैसला किया है।

उल्लेखनीय है कि डॉ. बीसी राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का निर्माण आइआइटी खड़गपुर परिसर के पास 18 एकड़ जमीन में किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2017 में संस्थान को इसकी अनुमति दी थी। यहां इस साल के अंत तक मरीजों के लिए आउटडोर और इंडोर सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। संस्थान की ओर से सोमवार को बताया गया कि पहले चरण में 400 बिस्तरों के साथ इंडोर सेवाएं शुरू की जाएंगी। वहीं, इस साल की समाप्ति तक आउटडोर मरीजों के लिए अस्पताल को खोले जाने की उम्मीद है।

आइआइटी खड़गपुर। फाइल

नीली क्रांति के इतिहास में नया अध्याय जोड़ रहा टैंक में मछली पालन

शशि कुमार मिश्र, बेतिया : तालाब नहीं है तो क्या हुआ, टैंक में भी मछली पालन कर सकते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में यह तकनीक नीली क्रांति के इतिहास में नया अध्याय जोड़ रही है। यहां के कई मत्स्यपालक इसे अपना कर बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

थाइलैंड और मलेशिया में बॉयोफ्लोक टैंक में मछली पालन तकनीक काफी प्रचलित है। इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण में भी हुई है। चार मीटर लंबे टैंक में साल में दो बार छह क्विंटल मछली का उत्पादन हो सकता है। हेचरी चलाने वाले पीपरा के निर्भय मिश्रा ने बताया कि मछलियों का उत्पादन ऑक्सीजन एवं भोजन की नियमित व्यवस्था पर निर्भर है। इस विधि में मछलियों को निरंतर ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एयरेटर की आवश्यकता होती है। मछलियों को भोजन में प्रोबॉयोटिक दिया जाता है। इसकी खासियत है कि यह मछलियों के मल को भी भोजन में परिवर्तित कर देता है। जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि बेगूसराय के बाद पश्चिम चंपारण में इस तकनीक से किसान मछली पालन कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने के मामले में पुरुषों से आगे हैं महिलाएं

राजीव सोनी, भोपाल

- पासपोर्ट कार्यालय में हर दिन उमड़ रही महिलाओं की भीड़
- नियमों के सरलीकरण और 'स्टूडेंट कनेक्ट' से आया बदलाव

उच्च शिक्षा पाने, नौकरी करने अथवा पर्यटन के लिए विदेश जाने वाली महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। यह पहला मौका है कि जब इस साल पासपोर्ट बनवाने के लिए हर दिन तुलनात्मक रूप से महिलाओं की ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। सात महीने के दौरान पासपोर्ट बनवाने महिलाएं सबसे ज्यादा विदेश मंत्रालय पहुंचीं। पासपोर्ट कार्यालय ने हर महीने लगभग साढ़े सात हजार महिलाओं के पासपोर्ट जारी किए, जबकि पुरुषों की संख्या इससे कम रही। इस बदलाव से विदेश मंत्रालय भी हैरत में है और इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक बदलाव मान रहा है।

इस बदलाव की यह तस्वीर सात महीने के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आई। जनवरी से जुलाई 2019 के दौरान मप्र में एक लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। इनमें महिलाओं की संख्या 51 हजार 921 थी, जबकि पुरुषों की संख्या 48 हजार 261 ही रही। जुलाई महीने में कुल 8,234 महिलाओं को पासपोर्ट जारी किए गए, जबकि इस दौरान पासपोर्ट पाने वाले पुरुषों

की संख्या महज 5,355 थी। तुलनात्मक रूप से हर दिन पासपोर्ट कार्यालय में जितने आवेदन आ रहे हैं, उनमें महिला आवेदकों की संख्या ज्यादा है।

पिछले साल पीछे थीं महिलाएं : क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मप्र ने वर्ष 2018 के दौरान कुल दो लाख 24 हजार 53 पासपोर्ट जारी किए थे। इनमें पुरुषों की संख्या एक लाख 37 हजार 420 थी, जबकि महिलाओं के पासपोर्ट की संख्या 86 हजार 622 रही। 11 ट्रांसजेंडर की श्रेणी के भी पासपोर्ट जारी हुए।

नियमों का हुआ सरलीकरण : विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि महिला सशक्तीकरण का यह सबसे जीवंत उदाहरण है। दरअसल, इसके पीछे मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में किया गया सरलीकरण भी प्रमुख कारण है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चलाए गए कार्यक्रमों की भी भूमिका है। इसके अलावा शैक्षणिक परिसरों में 'स्टूडेंट कनेक्ट' जैसे कार्यक्रम, शासकीय एवं निजी संस्थानों में जागरूकता शिविर और प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन शहरों के मुख्य डाकघरों में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों का खुलना भी सहायक रहा।

बदली समाज की सोच : मप्र की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल कहती हैं कि नागरिकता के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट की अहमियत लोगों को समझ में आने लगी है। पासपोर्ट बनवाने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। समाज व नई पीढ़ी में उच्च शिक्षा को लेकर सोच भी बदल रही है। अब अभिभावक भी बेटियों को विदेश में जाकर उच्च शिक्षा एवं नौकरी करने की अनुमति देने में संकोच नहीं करते। यही वजह है समाज में महिलाओं में जागरूकता के साथ महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है।

अनदेखी

इस जगह को पर्यटन नगरी बनाना चाहते थे पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, राज्य गठन के 18 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई इस नगर के विकास की योजना

गुमनामी में खो गया उत्तराखंड के भरत नगर का सपना

अजय खंतवाल, कोटद्वार

उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए '13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डेस्टिनेशन' योजना तो शुरू की गई, लेकिन इस योजना में उस भरत नगर (उतिर्च्छा) को कोई स्थान नहीं दिया गया, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सपना पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने देखा था। यही वजह है कि राज्य गठन के 18 साल बाद भी भरत नगर अपनी पहचान को मोहताज है, जबकि यहां एक खूबसूरत पर्यटन नगर विकसित होने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं।

गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार से करीब 25 किमी की दूरी पर स्थित है घाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भरत नगर। समुद्रतल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण भरत नगर व इससे लगे चरेख का डांडा, शून्य शिखर आदि स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग दशकों पुरानी है। पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चाहते थे कि यह पूरा क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, लेकिन ऐसा न हो न सका। प्रदेश बनने के बाद भी भरत नगर व इससे लगे क्षेत्र को लेकर उत्तराखंड सरकार उदासीन रवैया ही अपनाए रही। आज भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस नगर की कोई सुध लेने वाला नहीं है।

हर साल 23 अप्रैल को पेशावर विद्रोह की याद में और 25 दिसंबर को गढ़वाली के जन्म दिवस पर जहां-जहां उनकी प्रतिमाएं हैं, कार्यक्रम आयोजित कर बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर बात आई-गई हो जाती है। पूर्व की भाजपा सरकार ने भरत नगर व इससे लगे क्षेत्र के विकास को कण्वाश्रम-भरत नगर-लैंसडौन पर्यटन सर्किट के नाम से जो योजना बनाई थी, वह भी आज तक फाइलों से बाहर नहीं आ पाई।

मसूरी जैसा भूगोल है इस नगर का : उत्तराखंड सरकार यदि भरत नगर क्षेत्र में पर्यटन विकास की योजनाएं शुरू करती तो इस क्षेत्र को मिनी मसूरी के रूप में विकसित किया जा सकता था। कोटद्वार से भरत नगर के मध्य घने जंगल से गुजर रहा 25 किमी का सड़क मार्ग पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं भरत नगर क्षेत्र से बिजनौर (उत्तर प्रदेश) जिले में स्थित गंगा का बालावाली पुल, कालागढ़ बांध व कोटद्वार शहर के साथ ही हरिद्वार क्षेत्र का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलता है।

उत्तराखंड के भरतनगर का दृश्य। जागरण

'भरत नगर' नाम से लिखी थी गढ़वाली ने पुस्तक : गढ़वाली ने भारत के नामदेव राजा भरत के नाम से उतिर्च्छा में भरत नगर बसाने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने पूरे शिवालिक क्षेत्र को मसूरी की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई। गढ़वाली के प्रयासों से सर्वे ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र को चिह्नित भी करा दिया गया था, लेकिन उनके निधन के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गढ़वाली ने 'भरत नगर' नाम से किताब भी लिखी थी। इसके विमोचन के बारे में गढ़वाली ने कहा था कि 'मेरे मरने के बाद मेरी छाती पर इसका विमोचन करना।' एक अक्टूबर, 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। उसके बाद दिल्ली में ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने किताब का विमोचन किया था।

ताइवानी 'रेड लेडी' ने किया बक्सर के किसानों को मालामाल

कंचन किशोर, बक्सर

बिहार के बक्सर में डुमरांव अनुमंडल के नया भोजपुर में खेतों में फल से लदे पपीते के पेड़ कृषि क्षेत्र में बदलाव की बानगी बयां कर रहे हैं। किसानों के घरों में यह खुशहाली ताइवानी पपीते के 'रेड लेडी' प्रजाति लाई है। खेत में ही हाथों-हाथ बिकने वाले इस फल में अच्छा मुनाफा देख कई किसान इसकी खेती कर रहे हैं। साथ ही नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। यहां तैयार पौधे लेने उत्तर प्रदेश और झारखंड के किसान आते हैं।

डुमरांव का असिंचित क्षेत्र आमतौर पर सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। नया भोजपुर के प्रगतिशील किसान आशुतोष पांडेय ने क्षेत्र में पपीते की खेती की अच्छी संभावना जगाई। चार साल पहले खुद खेती शुरू की। पहले प्रयोग के तौर पर 'रेड लेडी' प्रजाति के पौधे लगाए। राज्य स्तर पर किसान सम्मान योजना में सम्मानित हो चुके आशुतोष बताते हैं कि प्रति पेड़ 60 किलो फल आए और खर्च

काटकर सवा लाख रुपये का मुनाफा हुआ। पिछले तीन सालों से वह पौधे भी तैयार कर रहे हैं। प्रति पौधे 20 रुपये की दर से तैयार हो रहा है और इसकी आपूर्ति दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है। उनके अलावा जिले में कई किसानों ने बड़े स्तर पर उन्नत पपीते की खेती की है। इससे सिमरी के नागेंद्र पांडेय, डुमरांव के प्रकाश राय, नया भोजपुर के वीरेंद्र कुशवाहा आदि ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली है।

सोना टूटा, चांदी में मामूली उछाल

नई दिल्ली : सोमवार को सोने के भाव में 30 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान यह पीली धातु 38,955 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से बिकी। इससे पहले शनिवार के कारोबार में सोना 38,985 रुपये पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के मुताबिक घरेलू मांग में कमी और कमजोर ग्लोबल कीमत के चलते सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सोमवार के कारोबार में चांदी की कीमत में 150 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। इस दौरान यह 46,750 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिकी। (प्रेट्र)

विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ओवरहॉलिंग क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें भी कंपनियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी का बोझ है।

— अजय सिंह, चेयरमैन, स्पाइसजेट

कारपोरेट हलचल

बायोमेडिकल रिसर्च में आइसीएमआर अवार्ड

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में पुरस्कारों का वितरण किया। वर्ष 2017 और 2018 के लिए 46 वैज्ञानिकों को 39 पुरस्कार वितरित किए गए। इनमें 14 महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं। पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक आइसीएमआर, सीएसआइआर, एआइआइएमएस नई दिल्ली, पीजीआइ चंडीगढ़, एसजीपीआइ लखनऊ, आइआइटी आदि से संबंधित हैं।

इंडिया कारपेट एक्सपो को बढ़िया रिस्पांस

इस महीने वाराणसी में आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो में 400 करोड़ रुपये की बिजनेस पूछताछ हुई। एक्सपो में 45 देशों के 361 विदेशी कारपेट खरीदारों ने हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त खरीदारों के 322 प्रतिनिधियों ने एक्सपो का दौरा किया। एक्सपो 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किया।

एसपीएमसीआइएल का सीएसआर

एसपीएमसीआइएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत दिव्यांगजनों को एक करोड़ रुपये के विभिन्न उपकरण वितरित किए। कंपनी ने ये कार्यक्रम अपने नासिक, देवास, हैदराबाद और होशंगाबाद परिसरों में आयोजित किया। इस संबंध में एक एमओयू पर एसपीएमसीआइएल के निदेशक एसके सिन्हा और एएलआइएमसीओ के सीएमडी डीआर सरीन ने हस्ताक्षर किए।

वैद्य ने संभाला आइओसी निदेशक का पद

श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) में निदेशक (रिफाइनरीज) के पद पर कार्यभार संभाल लिया है। वे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी आधारभूत रिफाइनरी परियोजना के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। वैद्य इंडियन ऑयल की नौ रिफाइनरियों और पेट्रोरसायन संयंत्रों के कारोबार और प्रचालन का नेतृत्व कर रहे हैं।

डॉ. वर्मा बने एनएमसी में दिल्ली से सदस्य

दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. महेश वर्मा को नेशनल मेडिकल कमीशन में दिल्ली से सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से की गई है। अधिसूचना के मुताबिक वह कमीशन में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

कपूर बने भेल में निदेशक एचआर

अनिल कपूर को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह बतौर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर और कॉरपोरेट कम्यूनिकेशंस का कार्यभार देख रहे थे। कपूर आइआइटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं।

शर्मा बने डीटीएल में निदेशक

मुकेश कुमार शर्मा ने दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड में निदेशक (ऑपरेशन) पद का कार्यभार संभाल लिया है। शर्मा को महाप्रबंधक (टेक्निकल) के पद से पदोन्नत कर निदेशक बनाया गया है। शर्मा ने 1987 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से अपना करियर शुरू किया था।

आइएचजीएफ दिल्ली फेयर

आइएचजीएफ दिल्ली फेयर का 48वां संस्करण 16 से 20 अक्टूबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित किया गया। पांच दिवसीय इस मेगा इंटरनेशनल फेयर में चेयरमैन ईपीसीएच रवि के. पासी ने कहा क्लीनर प्लैनेट की मुहिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट को देखते हुए काउंसिल ने रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल का मंत्र अपनाया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स करीब 70 लाख हस्तशिल्पियों का संरक्षण करती है।

इलेक्ट्रिक कारों की सरकारी खरीद में हो रही देरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इलेक्ट्रिक कारों की सरकारी खरीद में विलंब होता दिख रहा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और दफ्तरों के लिए 10 हजार इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का फैसला किया था। पहले इनकी खरीद तुरंत की जानी थी। तीन हजार कारें तो खरीदी भी जा चुकी हैं। लेकिन अब बदली आर्थिक परिस्थितियों में इस प्रक्रिया को धीमा करने तथा बड़ी कारों की जगह छोटी कारें खरीदने का फैसला किया गया है। इसके बदले अब पहले ई-चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार का इरादा अगले तीन-चार वर्षों में सरकारी दफ्तरों के लिए पांच लाख इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का है। ये कारें मौजूदा पेट्रोल-डीजल कारों का स्थान लेंगी। अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से पेट्रोल-डीजल की खपत में सालाना 83 करोड़ लीटर, जबकि कार्बन उत्सर्जन में 22 लाख टन की कमी आएगी। यही नहीं, इससे 2030 तक देश में ऊर्जा खपत में 64 फीसद, कार्बन उत्सर्जन में 37 फीसद तथा पेट्रोलियम आयात बिल में 3.80 लाख करोड़ रुपये की कमी संभव होगी।

सरकार ने तीन-चार वर्षों में पांच लाख इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का लक्ष्य रखा है। प्रतीकात्मक

हालांकि बदली आर्थिक परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और उत्पादन पर भी पड़ा है। जिन राज्यों और विभागों ने पहले केंद्र सरकार की एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईसीएल) से इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के बड़े ऑर्डर देने का वादा किया था, वे अब पीछे हट रहे हैं। बिक्री घटने से निर्माता कंपनियां भी उत्पादन में विलंब कर रही हैं। ईईसीएल ने पहले चरण में 10 हजार इलेक्ट्रिक कारों की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धी निविदा के जरिये टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का चयन किया था। परंतु दोनो कंपनियां अब तक एक-तिहाई से कम कारों की ही आपूर्ति कर सकी हैं। इस कारण ईईसीएल ने दूसरे चरण के टेंडर जारी करने की योजना को फिलहाल टाल दिया है। ईईसीएल बिजली मंत्रालय की कंपनी है। सरकार ने इसे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के अलावा देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का जिम्मा सौंपा है। ईईसीएल अब तक कई राज्य सरकारों, नगर निगमों, राज्य परिवहन निगमों तथा पीएसयू के साथ अनुबंध कर चुकी है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र और पंजाब सरकारों के अलावा दिल्ली और अहमदाबाद नगर निगम, नोएडा अथॉरिटी, चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो रेल, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा बीएसएनएल शामिल हैं। अब तक देशभर में कुल 300 एसी तथा 170 डीसी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें 65 चार्जिंग स्टेशन अकेले दिल्ली-एनसीआर में स्थापित किए गए हैं। पंजाब में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ईईसीएल ने पिछले दिनो बीएसएनएल के साथ समझौता किया है।

केंद्र का मानना है कि एलईडी बल्बों की तरह बड़े पैमाने पर ई-वाहनों की खरीद से इनके दामों में कमी आएगी। इसके लिए राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां घोषित करने को कहा गया है। अब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा केरल ने ई-वाहन नीति का एलान किया है। गौरतलब है कि फेम-2 योजना के तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है।

गोल्ड बांड्स की छठी सीरीज जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : धनतेरस में सोने की खरीद को भुनाने के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड्स (एसबीजी) की छठी सीरीज जारी कर दी है। इसकी कीमत 3,835 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित की गई है। वर्ष 2019-20 के लिए एसबीजी की छठी सीरीज का सब्सक्रिप्शन धनतेरस यानी 25 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसकी सेटलमेंट डेट 30 अक्टूबर रखी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जा रही है। इस तरीके से बांड खरीदने वालों के लिए यह 3,785 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से पड़ेगा। इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने एसजीबी स्कीम की पांचवीं सीरीज जारी की थी।

गौरतलब है कि ठोस रूप से सोने की खरीद को कम करने के लिए सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम लांच की थी। इस योजना के तहत सोने को प्रति ग्राम के हिसाब से बांटकर बांड जारी किए जाते हैं। इस तरह कम से कम एक ग्राम सोने में निवेश किया जा सकता है। किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम, हिंदू अविभाजित परिवार अधिकतम चार किलोग्राम और ट्रस्ट को 20 किलोग्राम सोने में निवेश की इजाजत है।

टीस ▶ चेयरमैन ने कहा, भारी टैक्स के चलते ग्लोबल स्पर्धा में पिछड़ रहे

विमानन को टैक्स के बोझ से मुक्ति दे सरकार : स्पाइसजेट

सेक्टर लंबे समय से सरकार से कर रहा टैक्स में कटौती की मांग

वाशिंगटन, प्रेट्र : देश की अग्रणी निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने कहा है कि भारत नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा बाजार बनकर उभरा है। यह सही समय है जब सरकार को इस सेक्टर में टैक्स दरें घटाने सहित दूसरे सुधार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में सिविल एविएशन सेक्टर में टैक्स दरें बहुत अधिक हैं, जिससे यह ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पर रहा है।

सिंह ने कहा कि एविएशन सेक्टर को समग्र तौर पर नौकरियों के सृजन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। टैक्स घटाने से यह सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आ सकेगा। विश्व बैंक और आइएमएफ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई वाले डेलीगेशन में सिंह भी एक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर भारत सरकार से काफी समय से छूट की मांग कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी लागत ग्लोबल पैमाने पर दूसरी एयरलाइन्स के समकक्ष रहे। दुनिया

प्रतीकात्मक

में भारत एकमात्र देश है, जहां एविएशन फ्यूल पर 35 परसेंट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। एविएशन के क्षेत्र में कोई दूसरा बड़ा देश ऐसा नहीं करता। इस तरह भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है।

एविएशन सेक्टर की दूसरी बड़ी समस्या का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इस सेक्टर में रखरखाव और रिपेयर के लिए 18 परसेंट जीएसटी चुकानी पड़ती है, जबकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विमानों के रिपेयर से संबंधित कार्य भारत में ही किए जा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर और कुशल लोग मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय विमानों के रिपेयर का अधिकतर काम विदेशों में होता है। इसकी मुख्य वजह यहां टैक्स दर अधिक होना है, जिसकी वजह से रिपेयर मंहगा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसको ठीक से समझने की जरूरत है, अगर टैक्स ज्यादा होगा तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। जब काम नहीं तो टैक्स भी नहीं और फिर राजस्व भी नहीं जनरेट होगा। इसलिए यहां टैक्स कम करने की जरूरत है। इस तरह से भारत रिपेयर के लिए एक ग्लोबल बेस बन सकता है।

सिंह ने भारत में एयरपोर्ट हब बनाने की जरूरत की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत को दुबई, अबूधाबी, दोहा और सिंगापुर की तरह इंटरनेशनल हब बनाने की जरूरत है, ताकि यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व जाने वाले यात्री दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से सीधी उड़ाने भर सकें। गौरतलब है कि स्पाइसजेट ने पिछले कुछ समय के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक अपने परिचालन का विस्तार देने की बात कही है।

इंडस्ट्री के हितों का ध्यान रखेगी सरकार : गोयल

▶ आरसीईपी पर समझौता करने से पूर्व घरेलू उद्योग के हितों का होगा संरक्षण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित कारोबारी समझौते आरसीईपी पर हस्ताक्षर करने से पहले घरेलू उद्योग के हितों को संरक्षित किया जाएगा। इस समझौते पर बातचीत आखिरी चरण में है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले घरेलू उद्योगों के हितों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) 10 आसियान देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम के साथ साथ उनके छह मुक्त व्यापार समझौता सहयोगी देशों आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। सभी सदस्य देशों ने इस समझौते पर हो रही वार्ता को इस वर्ष नवंबर में समाप्त करने की समय सीमा तय की है। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए जून, 2020 की अवधि तय हुई है।

गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों का पहले ध्यान देगी और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में 2009-10 के दौरान हुए मुक्त व्यापार समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए मुक्त व्यापार समझौतों में देश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इन समझौतों में ऐसे प्रावधान थे जिनसे देश को नुकसान हुआ और सेवा क्षेत्र में कोई लाभ नहीं लिया गया। लेकिन अब न केवल सेवाओं में, बल्कि निवेश के संदर्भ में भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान न पहुंचे।

पीयूष गोयल

यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के एक कार्यक्रम में गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रस्तावित व्यापार समझौते के संबंध में कहा कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार की ऐसी असीमित संभावनाएं हैं जिनका लाभ लिया जाना अभी बाकी है। अमेरिका से भारत की उम्मीद टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल और क्वालिटी एजुकेशन में सहयोग की है। फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत में निवेश के लिए उनका मंत्रालय एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की कवायद में जुटा है।

सब्सिडी लेने के लिए देश में ही बनाना होगा सोलर पैनल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ रिन्युअल एनर्जी क्षेत्र में सरकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कई कंपनियां कर रही थीं चालाकी

नवीन ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने साफ किया है कि अगर ब्लू वेफर आयातित है और इसे कच्चा माल के तौर पर चिन्हित करके सोलर पैनल का निर्माण किया गया है तो इन्हें घरेलू तौर पर निर्मित सोलर पैनल नहीं माना जाएगा। इन कंपनियों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। भारत में पूरी तरह से तैयार सोलर पैनल को ही सरकार के कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा।

इस कदम के साथ ही सरकार ने घरेलू स्तर पर सोलर पैनल बनाने के नाम पर कुछ कंपनियों की गड़बड़ी पर अंकुश का इंतजाम कर लिया है। सौर ऊर्जा बनाने के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से सोलर पैनल के भारत में निर्माण के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रोत्साहन दिया जाता है। कुछ कंपनियां इस सब्सिडी का फायदा तो उठा रही थी लेकिन पूरी तरह से पैनल का निर्माण भारत में नहीं कर रही थी बल्कि विदेशों से आधी निर्मित सोलर पीवी सेल्स (ब्लू वेफर के नाम से प्रचलित) लाती थी और उनसे सोलर पैनल बनाती थी।

एमएनआरई ने इस फैसले के साथ यह भी कहा है

प्रतीकात्मक

कि इससे देश में सोलर पैनल निर्माण का काम तेज हो सकेगा। सरकार ने वर्ष 2023 तक देश में 1.75 लाख मेगावाट क्षमता की रिनीवल इनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि देश में एक लाख मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगने से देश में इससे संबंधित एक बड़ा उद्योग भी स्थापित होगा। इसी वजह से यहां सोलर पैनल निर्माण करने से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निवेशकों की मदद के लिए बन रहा नया सिस्टम

नई दिल्ली, प्रेट्र : डीपीआइआइटी ने कहा है कि वह भारत आने वाले निवेशकों की सुविधा के लिए सिस्टम विकसित कर रहा है। डीपीआइआइटी के सचिव गुरुप्रसाद मोहापात्रा ने बताया कि इसके मार्फत वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद देश में निवेश सुविधा के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इस एजेंसी का वित्तपोषण डीपीआइआइटी करेगा।

मोहापात्रा ने बताया कि नया सिस्टम किसी राज्य या जिले में प्लांट लगाने वालों की मदद करेगा। लेबर रिफॉर्म से संबंधित मुद्दे सरकार के लिए प्राथमिकता पर हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री और निवेशकों को लेबर कानूनों से संबंधित दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। हमें मजदूरों के हितों का ख्याल भी रखना है। इसलिए सरकार दोनों पक्षों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सरकार टैक्स संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाने की ओर भी ध्यान दे रही है। गौरतलब है कि पहले भी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खाका तैयार करने की बात कहती रही है। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चीन से निकलने वाले उद्योगपतियों को भारत लाने के लिए ब्लूप्रिंट बनाने की बात कही थी।

भारत को फिर बनना पड़ा रिफाइंड कॉपर का आयातक

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत 18 वर्षों के बाद रिफाइंड कॉपर के आयातक देशों में शामिल हो गया है। केयर रेटिंग के मुताबिक तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता कॉपर प्लांट बंद होने के चलते भारत को इसके आयात की जरूरत पड़ी है। रेटिंग एजेंसी केयर ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 तक भारत कॉपर कैथोड का शुद्ध निर्यातक हुआ करता था। लेकिन तूतीकोरिन प्लांट के बंद होने से स्थिति बदल गई है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के कॉपर निर्यात में 87.4 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई, वहीं इसी अवधि के दौरान आयात में 131.2 परसेंट का इजाफा हुआ। इस दौरान भारत ने जापान, कांगो, सिंगापुर, चिली, तंजानिया, यूएई और दक्षिण अफ्रीका से रिफाइंड कॉपर का आयात किया। हालांकि इसी अवधि में चीन, ताइवान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश को निर्यात किया गया। इस बीच चीन को होने वाले कॉपर निर्यात में 63 परसेंट का इजाफा हुआ, जबकि जापान से होने वाले आयात में 68 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई।

देश में कॉपर माइंस की कमी के चलते इस

18 वर्षों बाद फिर से कॉपर आयात की पड़ी जरूरत

प्रतीकात्मक

उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल आयात किया जाता था। भारत अपनी जरूरत का 90 परसेंट कच्चा माल आयात करता था। लेकिन तूतीकोरिन प्लांट बंद होने के बाद कच्चे माल के आयात में भी बड़ी गिरावट आई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मई में तमिलनाडु सरकार ने वेदांता के कॉपर स्मेल्टर प्लांट को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने यह कदम व्यापक तौर पर हिंसक प्रदर्शन के बाद उठाया था।

सोनालिका ट्रैक्टर ने बढ़ाया चीन के बाजार में कदम

मुंबई, प्रेट्र : भारत की ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार चीन में पहुंच गई है। सोनालिका ग्रुप ने बताया कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड (आइटीएल) चीन के शैनडांग लुयु हेवी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ मिलकर चीन में 40 करोड़ डॉलर की लागत से संयुक्त उपक्रम बनाएगी। इस समझौते के मुताबिक ट्रैक्टर्स के इंजन के लिए सोनालिका चीन में एक असेंबली प्लांट भी लगाएगी। सोनालिका भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्यातक कंपनी है।

सोनालिका आइटीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक मित्तल ने बताया कि चीन में हमारी रेंज के ट्रैक्टर्स की मांग बहुत अधिक है। हमें उम्मीद है कि हम अपने सहयोगी के साथ मिलकर चीन के किसानों को बेहतर तकनीकी और उचित मूल्य पर ट्रैक्टर उपलब्ध करा सकेंगे।

▶ भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्यातक कंपनी है सोनालिका

आइटीएल ने इस समय 120 देशों में अपनी मौजूदगी बना रखी है।

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लुयु ने चीन के स्मॉल लोडर, फोर्कलिफ्ट बाजार में अच्छी मौजूदगी बना रखी है। यह अपने उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात भी करती है। चीन दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है और धीरे-धीरे ग्लोबल ट्रैक्टर निर्माता के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, इसलिए सोनालिका के लिए यहां काफी मौके हैं। कंपनी ने कहा कि हम लुयु के अलावा दूसरे सहयोगी के साथ मिलकर कारोबार आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। इस संयुक्त उपक्रम के जरिये लियू के लोडर और दूसरी उपकरणों के लिए इंजन भी असेंबल किए जाएंगे।

तैयारी

रूस व जापान की यात्रा पर जाएंगे प्रधान, एलएनजी पर होगी खास बात, अमेरिकी कंपनियों को बायो गैस में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया

रूस- अमेरिका से मजबूत होंगे ऊर्जा सहयोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिका और रूस के साथ भारत अपने ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की शुरुआत में अपनी रूस की यात्रा के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में दोनो देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एनर्जी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में निवेश करने की पेशकश की थी। अब इस बारे में बातचीत को आगे बढ़ाने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। रूस के बाद प्रधान जापान की भी यात्रा पर जाएंगे। प्रधान दोनो देशों से गैस आयात करने के मुद्दे पर खासतौर पर बात करेंगे। भारत रूस से गैस आयात बढ़ाना चाह रहा है जबकि जापान के साथ भी एलएनजी की खरीद को लेकर एक समझौता किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था में अभी गैस की हिस्सेदारी महज 6.5 फीसद है जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 15 फीसद करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत को बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस आयात करनी होगी। सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने यूएस-इंडिया स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए

भारत ने हाल ही में रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के हाइड्रोकार्बन भंडार में निवेश की घोषणा की है। प्रतीकात्मक

कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया का ऊर्जा कारोबार बहुत हद तक भारत की जरूरत के हिसाब से तय होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दिया है और इसका असर दुनिया के गैस बाजार पर दिखाई देगा। उन्होंने हाल ही भारतीय व अमेरिकी कंपनियों के बीच एलएनजी आयात करने और एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए हुए समझौते का भी जिक्र किया। प्रधान ने कहा कि अमेरिका भारत का एक बड़ा ऊर्जा साझेदार बन रहा है। वर्ष 2014 में भारत अमेरिका से कोई ऊर्जा उत्पाद आयात नहीं करता था, जबकि पिछले वित्त वर्ष सात अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा उत्पादों का आयात किया गया। प्रधान ने अमेरिकी कंपनियों को भारत के बायो गैस सेक्टर में निवेश करने के लिए खासतौर पर आमंत्रित किया।

प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभा रहा डिजिटल इंडिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : कम्यूनिकेशंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत उठाए जा रहे कदमों से ग्रामीण भारत का कायाकल्प होना चाहिए। इसके माध्यम से छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए नए मौके पैदा होने चाहिए। वे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइटी स्टार्ट-अप समिट के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने डिजिटल पेमेंट सिस्टम भीम के दूसरे वर्जन सहित कुछ अन्य प्रोग्राम को लांच किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया एक प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभा रहा है।

इस दौरान प्रसाद ने भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री को भी लांच किया। यह भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों को रजिस्टर कराने हेतु सिंगल विंडो पोर्टल का काम करेगी। प्रसाद ने कहा कि स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे वह डिजिटल इंडिया को मजबूत करने में सहायक हो सकें।

कुपोषण से लड़ाई में भारत के प्रयासों को यूएन ने सराहा

- कहा, भारत में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के सभी कारक मौजूद
- कुपोषण के आंकड़ों में आई कमी, लेकिन प्रयास तेज करने की जरूरत

नई दिल्ली, आइएएनएस : संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (यूएनडब्ल्यूएफपी) ने भुखमरी व कुपोषण से लड़ाई और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। भारत में यूएनडब्ल्यूएफपी के प्रतिनिधि बिशो प्रजॉली ने कहा कि यहां वह सभी कारक व संभावनाएं मौजूद है, जिससे भारत एसडीजी 2 के लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। एसडीजी 2 के तहत दुनियाभर के देशों को 2030 से पहले भुखमरी खत्म करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार का लक्ष्य हासिल करना है।

भारत समेत दुनियाभर के देशों ने 2015 में सतत विकास के एजेंडे से जुड़े घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस एजेंडे में 17 लक्ष्य को शामिल किया गया था, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। प्रजॉली का कहना है कि बीते कुछ दशकों में भारत ने आर्थिक विकास, गरीबी से मुक्ति व खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। कुपोषण के आंकड़ों में भी कमी आई है। हालांकि, भारत को इस दिशा में अपने प्रयास और तेज करने की जरूरत है।

भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) 2013 की सराहना करते हुए

प्रतीकात्मक

प्रजॉली ने कहा, 'भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए नीति के स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। एनएफएसए से 80 करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।' एनएफएसए के अलावा उन्होंने एनीमिया और जन्म के समय बच्चों के कम वजन की समस्या दूर करने के लिए चलाए जा रहे पोषण अभियान को भी सराहा है।

बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान में अपना कार्यकाल पूरा करने की क्षमता नहीं

- विपक्षी नेता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर फिर की तल्ख टिप्पणी
- कहा-जनता और सियासी पार्टियां सरकार की नीतियों से नाखुश

कराची, प्रेट्र : इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पाकिस्तान के विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री पर फिर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान में अपना कार्यकाल पूरा करने की क्षमता नहीं है।

डॉन अखबार के अनुसार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल ने कराची जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में पत्रकारों से कहा, 'मुल्क की जनता और सियासी पार्टियां इमरान सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। यह सरकार मुल्क को सही दिशा में ले जाने में सक्षम नहीं है। इस वजह से हर कोई इस कठपुतली सरकार से परेशान है।' 31 वर्षीय बिलावल ने गत शुक्रवार को भी इमरान सरकार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शन का एलान करते हुए कहा था, 'जनता के बीच इमरान सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, क्योंकि इस सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। हमारी मांग है कि मुल्क में लोकतंत्र को बहाल किया जाए। बनावटी लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सभी विपक्षी पार्टियों ने इमरान सरकार को

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी। फाइल फोटो

हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है।' उन्होंने बताया था कि पीपीपी इमरान खान पर इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।

इमरान सरकार के खिलाफ हड़ताल करेंगे कारोबारी

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान के विपक्षी दलों के बाद अब कारोबारियों ने भी इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की नुकसानदेह आर्थिक नीतियों के खिलाफ कारोबारियों के संगठन ने दो दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल 29 और 30 अक्टूबर को होगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, कारोबारियों के संगठन ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजरन के केंद्रीय महासचिव नईम मीर ने रविवार को कहा, 'हमारा एजेंडा प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाना नहीं है। हम सिर्फ नीतियों में सुधार कराना चाहते हैं।' वह मीरपुरखास में कारोबारियों एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर सरकार कारोबारियों को रियायतें दे तो वे सभी बकाया करों का भुगतान करने के इच्छुक हैं।

गुप्ता परिवार पर शिकंजा कसेगा दक्षिण अफ्रीका

- अमेरिका, ब्रिटेन व यूएई में जमा अरबों की रकम जब्त की जाएगी
- सरकारी विभागों की मिलीभगत और गैरकानूनी तरीके से कमाई का आरोप

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं के अरबों रेंड (दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा) की धनराशि को जब्त करने के प्रयास नए सिरे से शुरू किए हैं। बताया जाता है कि गुप्ता बंधुओं ने यह रकम कथित तौर पर सरकारी विभागों की मिलीभगत से गैरकानूनी सौदों से कमाये और फिर देश से गैरकानूनी ढंग से बाहर भेज दिया था।

'संडे टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, असेट फोरफीटर यूनिट (एएफयू) ने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने का जिक्र किया है। इससे पहले अमेरिकी वित्त विभाग ने गुप्ता बंधुओं अजय, अतुल और राजेश तथा उनके सहयोगी सलीम एस्सा पर पिछले हफ्ते पाबंदियां लगाई थीं।

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि गुप्ता परिवार एक भ्रष्ट नेटवर्क के सदस्य हैं और उन्होंने सरकारी ठेकों, रिश्वत तथा अन्य भ्रष्ट गतिविधियों के जरिए अधिक भुगतान लिया तथा उसका इस्तेमाल राजनीतिक भुगतानों के लिए तथा सरकारी गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए किया गया। गुप्ता परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है।

दक्षिण अफ्रीका में बीते दो दशक में उसने आइटी, मीडिया और खनन उद्योगों के जरिए काफी पैसा कमाया। आरोप है कि कमाई के लिए गुप्ता परिवार ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा से नजदीकी का कथित तौर पर फायदा उठाया। जुमा खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। गुप्ता भाई दुबई भाग चुके हैं और अब कर्जदाताओं को भुगतान के लिए दक्षिण अफ्रीका में उनकी संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है। लेकिन एएफयू की नजर उस पैसे पर है जो गुप्ता बंधुओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई भेजा।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि एएफयू गैरकानूनी ढंग से अमेरिका भेजी गई रकम को वापस पाने की दिशा में काम कर रहा है और इसमें अमेरिकी अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। एएफयू ब्रिटेन की कानून प्रवर्तक एजेंसियों की मदद भी ले रहा है।

भारत के दावे का पाक ने किया खंडन, कहा-गुलाम कश्मीर में कुछ नहीं हुआ

इस्लामाबाद, प्रेट्र : चोट खाया पाकिस्तान कराह भी नहीं पा रहा। इसी वजह से वह भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में बर्बाद हुए आतंकी ठिकानों में नुकसान नहीं कर रहा। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारत की सेना ने आतंकी शिविरों को नष्ट करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की। उसने विदेशी राजनयिकों और मीडिया से मौका मुआयना कराने की भी चुनौती दी है। पाकिस्तान का यह दावा वैसा ही है जैसा कि उसने फरवरी में बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारत के हवाई हमले के बाद किया था। लेकिन मुआयने के लिए महीनों बाद विदेशी मीडिया को ले गया था और नए बने मदरसे में घुमाकर वापस ले आया था।

रविवार को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि गुलाम कश्मीर में हुई सैन्य कार्रवाई में छह से दस पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और तीन आतंकी शिविर नष्ट कर दिए गए हैं। भारत ने यह हमला पाकिस्तानी सेना के जम्मू-कश्मीर के तंगधार और केरन सेक्टरों में अकारण गोलीबारी के जवाब में किया था। जनरल रावत के बयान पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने रविवार की मध्य रात्रि में ट्वीट कर नाइत्तेफाकी जाहिर की। गफूर ने कहा, भारतीय सेना प्रमुख का यह बयान कि तीन आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया है, स्तब्धकारी है। पाकिस्तान में कोई भी शिविर निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास किसी भी विदेशी राजनयिक या मीडिया को लेकर मौके पर जाए और उन्हें वह स्थान दिखाए जहां पर भारतीय सेना की कार्रवाई में कोई शिविर नष्ट हुआ हो।

चेतावनी ▶ एशियाई रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन के रक्षा मंत्री फेंगहे ने दुनिया को किया आगाह

ताइवान के एकीकरण को कोई रोक नहीं सकता

1949 में गृहयुद्ध के बाद चीन से अलग हो गया था यह द्वीपीय क्षेत्र

बीजिंग, एएफपी : चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे ने ताइवान के एकीकरण को लेकर दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने चीन के साथ ताइवान के एकीकरण का आह्वान करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता।

चीन स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। गृहयुद्ध के बाद यह द्वीपीय क्षेत्र 1949 में चीन से अलग हो गया था। बीजिंग यह धमकी भी दे चुका है कि ताइवान अगर चीन में नहीं मिला तो बल प्रयोग कर हासिल किया जाएगा।

फेंगहे ने यहां सोमवार को एशियाई रक्षा मंत्रियों और अधिकारियों के एक सम्मेलन में कहा, 'चीन के साथ ताइवान के पूर्ण एकीकरण के प्रयास को रोका नहीं जाएगा। यह ऐसा कुछ है, जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह राष्ट्रीय हित का सबसे बड़ा मामला है।' चीन के ताइवान के साथ संबंध साल 2016 में तब बिगड़ गए, जब राष्ट्रपति साई इंग-वेन सत्ता में आईं। उनकी पार्टी ने ताइवान को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता देने से इन्कार कर दिया था।

बता दें कि चीन ताइवान को हमेशा एक ऐसे राज्य के रूप में देखता है जो उससे अगल

बीजिंग में सोमवार को चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहे ने एशियाई रक्षा मंत्रियों और अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। एपी

हो गया। चीन को विश्वास है कि एक दिन ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। जबकि ताइवन की एक बड़ी आबादी स्वयं को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है।

दबाव बनाने के लिए किए सैन्य अभ्यास : ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन उसके समीप वाले इलाके में कई बार सैन्य अभ्यास कर चुका है। उसने ताइवान के पास पूर्वी चीन सागर में गत अगस्त और जुलाई में तीन बार सैन्य अभ्यास किए थे।

अमेरिका से रक्षा करार से नाराजगी : ताइवान और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंध चीन को पंसद नहीं है। गत अगस्त में अमेरिका ने ताइवान को 66 एफ-16 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी दी थी। इस पर चीन ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी।

हांगकांग में प्रदर्शन के दौरान मस्जिद में नुकसान के लिए कैरी लैम ने माफी मांगी

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में रविवार रात प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष में महानगर की सबसे बड़ी मस्जिद को नुकसान हुआ और बौछार में छोड़े गए रंगीन पानी ने मस्जिद की दीवारों को खराब कर दिया। सोमवार को स्वायत्त क्षेत्र की शीर्ष अधिकारी कैरी लैम और पुलिस प्रमुख ने घटना के लिए मस्जिद के पदाधिकारियों से खेद जताया। शीर्ष अधिकारियों के खेद व्यक्त करने से संतुष्ट हांगकांग में मुस्लिम नेताओं ने भी लोगों से शांत रहने और संयम बरतने की अपील की है।

रविवार को हांगकांग में पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने जुलूस निकालने और जनसभा करने की कोशिश की थी। इसके चलते दोनों पक्षों में जमकर टकराव हुआ था। यह टकराव देर रात तक जारी रहा। इस दौरान कोवलून इलाके में मस्जिद के बाहरी हिस्से को मामूली नुकसान हुआ और आंदोलनकारियों पर छोड़ा गया गाढ़ा रंगीन पानी मस्जिद की दीवारों पर भी गिर गया। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए कुछ श्रद्धालुओं पर भी रंगीन पानी गिरा। सोमवार सुबह जब मस्जिद की दीवारों की

हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। एएफपी

सफाई का कार्य चल रहा था, उसी समय चीन की प्रतिनिधि शीर्ष पदाधिकारी कैरी लैम वहां सिर तक शाल ओढ़कर पहुंचीं। उन्होंने मस्जिद के पदाधिकारियों और मुस्लिम नेताओं से मिलकर घटना के लिए खेद जताया। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि कैरी लैम ने मुस्लिम नेताओं को मामले को शांति से निपटाने के लिए धन्यवाद दिया जिससे पांच महीने से अशांत हांगकांग में हालात और नहीं बिगड़े। इस बीच आंदोलनकारियों ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदर्शन के दौरान मस्जिद की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा गया। कोई भी प्रदर्शनकारी उधर नहीं गया। अगर रंगीन पानी उधर की ओर फेंका गया तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है।

प्रदर्शन के दौरान फिर हिंसा : हांगकांग में सोमवार को देर शाम प्रदर्शन के दौरान फिर हिंसा हुई। यूएन लांग इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन को जब रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके जाने लगे और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार में आग लगा दी गई।

प्रत्यर्पण मामले में लंदन की अदालत में पेश हुए जूलियन असांजे

लंदन, रायटर : अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे सोमवार को लंदन की एक अदालत में पेश हुए। अदालत पहुंचने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन भी किया। उन पर जासूसी का मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका उनका प्रत्यर्पण करना चाहता है। असांजे को अमेरिकी सरकारी कंप्यूटर हैक करने की साजिश रचने और जासूसी कानून के उल्लंघन समेत 18 मामलों में आरोपित किया गया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें कई साल कैद की सजा हो सकती है।

असांजे ने 2010 में अमेरिका से संबंधित कई गोपनीय दस्तावेज व वीडियो सार्वजनिक कर दिए थे। इनमें एक वीडियो 2007 में अमेरिका द्वारा बगदाद में किए गए हवाई हमले का भी था। अपाचे हेलीकॉप्टर द्वारा हुए उस हमले में रायटर न्यूज एजेंसी के दो पत्रकार समेत करीब एक दर्जन लोगों की मौत हुई थी।

लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में सात साल रहे असांजे : यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर 2010 में स्वीडन ने असांजे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय वारंट जारी किया था। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों से इन्कार किया है। उन्होंने यह आशंका जताई थी कि स्वीडन से उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। स्वीडन प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए उन्होंने 2012 में लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। सात साल वह वहीं पर रहे। बीते अप्रैल में उन्हें जमानत के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 50 हफ्तों की जेल की सजा सुनाई गई थी।

लेबनान में मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन...

लेबनान में अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण देशभर में सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने- प्रदर्शन जारी हैं। सोमवार को हजारों लोगों ने त्रिपोली में मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना विरोध जताया। असल में सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए वाट्सएप कॉल पर टैक्स लगा दिया था। इसके बाद लोगों को गुस्सा भड़क गया तथा हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। टैक्स वापस लेने की घोषणा के बावजूद लोगों को गुस्सा थमा नही है। रायटर

बैलिस्टिक मिसाइल दागने में विफल रही रूसी पनडुब्बी

मॉस्को, रायटर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निगरानी में हो रहे सैन्य अभ्यास के दौरान एक परमाणु पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल दागने में विफल हो गई। यह नाकामी 15 से 17 अक्टूबर तक चले सैन्य अभ्यास के दौरान देखने को मिली।

बोदोमास्ती अखबार ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय के दो अधिकारियों के हवाले से बताया कि ओखोत्स्क सागर में चल रहे सैन्य अभ्यास के दौरान परमाणु पनडुब्बी के-44 रियाजान से दो आर-29आर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जानी थीं। यह पनडुब्बी सफलतापूर्वक सिर्फ एक मिसाइल ही दाग पाई, जबकि दूसरी ट्यूब में ही अटकी रह गई। यह पनडुब्बी रूस के प्रशांत बेड़े का हिस्सा है। यह घटना सैन्य अभ्यास के अंतिम दिन तब हुई, जब राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को स्थित रक्षा मंत्रालय के कमान केंद्र से खुद इस सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे थे। रूस के सशस्त्र बलों के लिए यह सैन्य अभ्यास वार गेम्स के तहत हो रहा था। इसे 'थंडर 2019' नाम दिया गया था। इस सैन्य अभ्यास के जरिये परमाणु युद्ध से निपटने में देश के सामरिक बलों की तैयारियों को आंकना था।

पाबंदी के विरोध में ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने पहले पन्ने किए काले

- गोपनीयता के नाम पर पत्रकारों के उत्पीड़न पर जताया विरोध
- मीडिया की आजादी सुनिश्चित करने की मांग की
- अखबारों की मुहिम को मिला टीवी-रेडियो का समर्थन

ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने काले कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। रायटर

सिडनी, एएनआइ : ऑस्ट्रेलिया में सरकारी गोपनीयता के नाम पर पत्रकारों के उत्पीड़न के विरोध में प्रमुख अखबारों ने सोमवार को अपने पहले पन्ने काले कर दिए।

अल जजीरा चैनल के मुताबिक 'द ऑस्ट्रेलियन', 'द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' और 'ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू' समेत ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने पहले पन्ने पर छपे शब्दों को काली स्याही से पोत दिया और उन पर एक लाल मुहर लगा दी जिस पर लिखा था - सीक्रेट ।

अखबारों की इस मुहिम का कई टीवी, रेडियो और ऑनलाइन समूह भी समर्थन कर रहे हैं। टीवी पर विज्ञापन चल रहे हैं, जिसमें दर्शकों से इस सवाल पर विचार करने को कहा जा रहा है, 'जब सरकार सच दूर रखती हो, वे क्या कवर करेंगे?'

अखबारों ने सरकार पर मीडिया पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अखबारों ने यह तरीका अपनाया। मीडिया समूह का कहना है कि संवेदनशील जानकारी तक पत्रकारों की पहुंच को रोकने के लिए लगाई पाबंदियां हटाई जाएं, प्रेस को आजादी सुनिश्चित की जाए, और ऐसे प्रावधान भी हों जिससे पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के केस आसानी से दर्ज न हों। चैनल नाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ह्यूज मार्क्स ने एक बयान में कहा, 'यह आम नागरिकों का हक है कि उन्हें सरकार के हर फैसले की पूरी जानकारी मिले।'

दरअसल, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने मीडिया को यौन शोषण के दोषी कार्डिनल (पादरी) जॉर्ज पेल के बारे में रिपोर्ट छापने से रोक दिया था। इसके चलते ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने पेल का नाम छापे बिना ही उनके दोषी पाए जाने की खबरें चलाई थीं। जबकि, विदेशी मीडिया ने कार्डिनल का पूरा नाम छापा था। इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) मीडिया समूह के संपादक के घर पर छापा मारा था। उन पर राष्ट्रीय महत्व की गुप्त जानकारी रखने का आरोप लगा था।

छापे की इस कार्रवाई की दुनियाभर में मीडिया संगठनों ने निंदा की थी। बीबीसी ने इसे गंभीर परेशान करने वाली कार्रवाई बताया था।

ब्रेक्जिट फिर पड़ा खटाई में

- संसद में दोबारा प्रस्ताव पेश नहीं कर सके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन
- स्पीकर जॉन बरको ने कहा, एक ही प्रस्ताव को दूसरी बार पेश करने की नहीं दी जा सकती अनुमति

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ब्रेक्जिट मामले में सोमवार को एक और झटका तब लगा जब संसद में स्पीकर ने उन्हें दूसरी बार यूरोपीय यूनियन से समझौते का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी। सरकार 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन (ईयू) छोड़ने की घोषणा कर चुकी है।

हाउस ऑफ कॉमंस में स्पीकर जॉन बरको ने कहा, प्रधानमंत्री को एक ही सत्र में एक ही प्रस्ताव को दूसरी बार पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उल्लेखनीय है कि शनिवार को प्रधानमंत्री ने यही प्रस्ताव पेश किया था लेकिन उन्हीं की कंजरवेटिव पार्टी के सांसद ओलिवर लेटविन ने संशोधन पेश कर दिया था।

लेटविन के प्रस्ताव में ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) को तीन महीने के लिए टालने और बिना शर्त अलगाव न करने के बिंदु थे। लेटविन का संशोधन प्रस्ताव 322-306 मतों के अंतर से पारित हो गया था। इसके चलते प्रधानमंत्री का ईयू से समझौते का प्रस्ताव लटक गया। चूंकि समझौते को क्रियान्वित करने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है, इसलिए प्रधानमंत्री सोमवार को फिर से प्रस्ताव पेश करने के लिए स्पीकर से अनुमति मांगी लेकिन स्पीकर ने इससे इन्कार कर दिया। किसी भी प्रस्ताव को उसी सत्र में दोबारा पेश करने की अनुमति सिर्फ स्पीकर ही दे सकते हैं।

अब 31 अक्टूबर को ब्रेक्जिट का मामला फिर अटकता दिख रहा है। जॉनसन के लाख प्रयासों के बावजूद यूरोपीय यूनियन (ईयू) से ब्रिटेन का अलगाव परवान नहीं चढ़ पा रहा है। पता चला है कि अब गेंद ईयू के पाले में है। उसके बाकी 27 सदस्य देश अगर ब्रेक्जिट को टालने का फैसला करेंगे तो नई तारीख का एलान होगा, अन्यथा वे ब्रेक्जिट को प्रक्रिया को सिरे से खारिज करने के लिए भी ब्रिटेन से कह सकते हैं। जून 2016 से चल रही उहापोह को खत्म करने के लिए ईयू ने पिछली बार ब्रिटेन को ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अक्टूबर की आखिरी तारीख दी थी।

एफएटीएफ के लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे : कुरैशी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की 'ब्लैक लिस्ट' में डलवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कुरैशी ने कहा कि उनका देश एफएटीएफ की तरफ से रखे गए सभी लक्ष्यों को तय समय में हासिल कर लेगा।

कुरैशी की यह टिप्पणी पेरिस स्थित एफएटीएफ की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि अगर उसने (पाकिस्तान ने) फरवरी, 2020 तक आतंकवाद को मुहैया कराए जा रहे धन पर लगाम नहीं लगाई तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डलवाने में भारत विफल रहा। सरकार सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करेगी और देश को 'ग्रे' सूची से बाहर लाएगी। उन्होंने दावा किया कि एफएटीएफ ने धनशोधन और आतंक के वित्त पोषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को संज्ञान में लिया।

चिली में मेट्रो किराए में वृद्धि को लेकर हिंसा भड़की, आठ लोगों की मौत

सैंटियागो, आइएएनएस/रायटर : लैटिन अमेरिकी देश चिली में मेट्रो किराए में वृद्धि के विरोध में भड़की हिंसा में अभी तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को राजधानी सैंटियागो के रेंका इलाके में अग्निशमन दस्ते ने राख में तब्दील हो चुके कपड़े की एक दुकान से पांच शव निकाले। इससे पहले तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। चारों तरफ भड़की हिंसा को देखते हुए देश में आपातकाल को बढ़ा दिया गया है। राजधानी समेत पांच शहरों में शनिवार सुबह से आपातकाल लागू है। चिली में पिछले कुछ दिनों से हिंसा, लूट व आगजनी की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। रविवार को भी प्रदर्शनकारियों व सुरक्षाबलों के बीच खूनी झड़पें देखने को मिलीं।

मीडिया से मुखातिब चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पीनेरा ने रविवार को कहा, 'हमारी जंग एक शक्तिशाली व निर्मम दुश्मन से है, जो हिंसा के जरिये तबाही मचाने पर आमदा है। इन लोगों (दुश्मन) ने लोकतांत्रिक देश चिली के

दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में बीते दिनों से मेट्रो के किराए में वृद्धि के विरोध में व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी जारी है। रायटर

नागरिकों के विरूद्ध युद्ध छेड़ रखा है।' देश में भड़की हिंसा के मद्देनजर रविवार शाम को चिली की संसद के निम्न सदन ने बढ़े मेट्रो किराए को वापस लिए जाने का बिल पास कर दिया है। बता दें कि मेट्रो प्रशासन ने किराया 1.13 डॉलर (करीब 80 रुपये) से बढ़ाकर 1.17 डॉलर (करीब 83 रुपये) कर दिया था, जिसके बाद देश में हिंसा का दौर शुरू हो गया।

नेपाल की सेना को 148 करोड़ की मदद देगा चीन

काठमांडू, रायटर : नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीते कुछ साल से चीन लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में उसने एक और कदम बढ़ाया है। अब वह आपदा राहत सामग्री के नाम पर अगले तीन साल में नेपाल सेना को 2.1 करोड़ डॉलर (करीब 148 करोड़ रुपये) की मदद देगा। नेपाल सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

नेपाल के रक्षा मंत्री इस वक्त चीन की यात्रा पर है। इसी दौरान उन्होंने अपने समकक्ष वेई फेंग्हे के साथ आपदा राहत सामग्री को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी संता बहादुर ने कहा कि अगले तीन साल तक सेना की जरूरत के हिसाब से उन्हें चीन की मदद पहुंचाई जाएगी।

बता दें कि नेपाल में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन ने यहां बड़ा भारी निवेश किया है, जिससे भारत की चिंता बढ़ी है। बीते 12 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी नेपाल की यात्रा पर आए थे। पिछले दो दशक में चीन के किसी राष्ट्रपति की नेपाल में यह पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों पक्ष में कई करार भी हुए।

ये भी जानिए
दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 162 रनों पर ऑल आउट हुई, जिसमें अश्विन ने कोई विकेट नहीं लिया। इससे साफ है कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने बहुत सुधार किया है।

जोश में मुहम्मद शमी ● एपी

मुट्ठी में आया रांची टेस्ट

तेज गेंदबाजों का जादू चला क्लीन स्वीप से दो विकेट दूर भारतीय टीम

संजीव रंजन ● रांची

जेएससीए स्टेडियम की जिस पिच को स्पिनरों के लिए मुफीद माना जा रहा था उसी पिच पर भारतीय तेज गेंदबाजों की जोड़ी मुहम्मद शमी व उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी कर भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जीत के द्वार पर ला खड़ा किया। दोनों तेज गेंदबाजों का ऐसा खौफ रहा कि मेहमान टीम के बल्लेबाज दोनों पारियों में खुलकर नहीं खेल पाए। इस मैच में अभी तक भारतीय तेज गेंदबाजों की जोड़ी ने 10 विकेट झटके हैं जबकि स्पिन गेंदबाजों ने छह विकेट चटकाए।

तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में आठ विकेट खोकर 132 रन बना संघर्ष कर रही है। अभी भी मेहमान टीम को पारी की हार से बचने के लिए 203 रन बनाने हैं जबकि उसके पास दो विकेट ही हैं। पहली पारी में भारत ने नौ विकेट पर 497 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर 335 रनों पिछड़ी दक्षिण अफ्रीका की टीम की दूसरी पारी में भी वही कहानी रही और उसके बल्लेबाज सस्ते में आउट होते चले गए। खेल समाप्त होने तक एल्गर के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए थेउनिस डि ब्रूएन (30) व एनरिक नोर्टजे (05) खेल रहे हैं। भारत की ओर से मुहम्मद शमी ने तीन, उमेश यादव ने दो, रवींद्र जडेजा व अश्विन ने एक-एक विकेट लिए।

भारत ने दिया फॉलोऑन: दक्षिण अफ्रीका टीम को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में दूसरी बार फॉलोऑन खिलाया। यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक सीरीज में दो-दो बार फॉलोऑन खेलनी पड़ा। फॉलोऑन खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारतीय तेज गेंदबाजों की जोड़ी उमेश व शमी ने मेहमान टीम के पांच बल्लेबाजों को 36 रन पवेलियन भेज बैकफुट पर धकेल दिया। उमेश ने दूसरी पारी की अपनी पहली ही गेंद पर डिकॉक को बोल्ड कर दिया। डिकॉक पांच रन बनाकर आउट हुए। मेहमान टीम अभी इस झटके से उबरी भी नहीं थी कि दूसरे छोर से शमी ने जुबैर हमजा (00) की गिल्लियां बिखेर कर टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद दोनों गेंदबाज ज्यादा आक्रामक हो गए। दो विकेट 10 रन पर गिरने के बाद मेहमान टीम के बल्लेबाज आउट होते चले गए। विशेषकर शमी की धारदार गेंदबाजी के आगे उनका कोई भी शीर्ष बल्लेबाज टिक नहीं पाया। शमी ने 18 के कुल योग पर कप्तान डुप्लेसिस (04) को एलबीडब्ल्यू किया। भारत ने दूसरी पारी में आठ विकेट झटक लिए हैं।

पहली पारी में 166 पर सिमटे मेहमान: इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 166 रनों पर आउट हो गई। मैच के तीसरे दिन नौ रनों पर दो विकेट से आगे खेलने उतरी मेहमान टीम उमेश यादव की अच्छी गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आई।

मेहमानों के 12वें खिलाड़ी ने की बल्लेबाजी

रांची: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर को तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में चोट के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। दूसरी पारी की 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह चोटिल हो गए। यादव की उछलती गेंद से एल्गर ने नजरें हटा लीं, जिस कारण गेंद उनके हेल्मेट पर लगी। वह पिच पर ही बैठ गए। फिर वह पवेलियन चले गए। आइसीसी के नए नियमों के तहत सिर पर चोट लगने पर टीम का 12वां स्थानापन्न खिलाड़ी बल्लेबाजी भी कर सकता है। पहले चोटिल खिलाड़ी की जगह सिर्फ क्षेत्ररक्षण किया जा सकता था। इस कारण एल्गर की जगह थेउनिस डि ब्रूएन बल्लेबाजी करने आए। ऐसा टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार हुआ है। इसी साल एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ की जगह लाबुशाने बल्लेबाजी करने आए थे जबकि जमैका में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज के बल्लेबाज डेरेन ब्रावो के चोटिल होने पर ब्लैकवुड बल्लेबाजी करने उतरे थे।

चोटिल होने के बाद मैदान पर बैठे डीन एल्गर। पेट्र

नदीम को मिला करियर का पहला टेस्ट विकेट

रांची: शाहबाज नदीम ने भारत को पांचवीं सफलता दिलाई। 29वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर नदीम ने तेंबा बावुमा को टेस्ट क्रिकेट का अपना पहला शिकार बनाया। नदीम की गेंद को बाहर निकलकर हिट करना चाहते थे बावुमा, लेकिन गेंद साहा के हाथों में चली गई। उन्होंने बिना समय गंवाए गिल्लियां उड़ा दी। जडेजा ने क्लासेन को आउट कर भारत को एक और सफलता दिलाई। शमी ने लंच के तुरंत बाद भारत को सातवीं सफलता दिलाई और डेल पीट को पवेलियन की राह पकड़ा दी।

स्कोर बोर्ड

टॉस: भारत (बल्लेबाजी)
भारत (पहली पारी): 497/9 (पारी घोषित, 116.3 ओवर)

दक्षिण अफ्रीका (पहली पारी) 162 (56.2 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
डीन एल्गर का. साहा बो. शमी	00	02	00	00
क्विंटन डिकॉक का. साहा बो. उमेश	04	06	01	00
जुबैर हमजा बो. जडेजा	62	79	10	01
फाफ डुप्लेसिस बो. उमेश	01	09	00	00
तेंबा बावुमा स्टं. साहा बो. नदीम	32	72	05	00
हेनरिक क्लासेन बो. जडेजा	06	10	01	00
जॉर्ज लिंडे का. रोहित बो. उमेश	37	81	03	01
डेन पीट एलबीडब्ल्यू बो. शमी	04	14	00	00
कैगिसो रबादा रन आउट	00	06	00	00
एनरिक नोर्टजे एलबीडब्ल्यू बो. नदीम	04	55	00	00
लुंगी नगिदी नाबाद	00	05	00	00

अतिरिक्त: 12 (बा–8, लेबा–3, नोबॉ–1),
कुल: 56.2 ओवर में 162 रनों पर सभी आउट
विकेट पतन: 1–4 (एल्गर, 0.2), 2–8 (डिकॉक, 1.6), 3–16 (डुप्लेसिस, 5.5), 4–107 (हमजा, 27.4), 5–107 (बावुमा, 28.2), 6–119 (क्लासेन, 31.4), 7–129 (पीट, 36.4), 8–130 (रबादा, 37.5), 9–162 (लिंडे, 55.1)
गेंदबाजी: शमी 10–4–22–2, उमेश 9–1–40–3, नदीम 11.2–4–22–2, जडेजा 14–3–19–2, अश्विन 12–1–48–0

दक्षिण अफ्रीका (दूसरी पारी) 132/8 (फॉलोऑन, 46 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
क्विंटन डिकॉक बो. उमेश	05	06	01	00
डीन एल्गर रिटायर्ड हर्ट	16	29	03	00
जुबैर हमजा बो. शमी	00	06	00	00
फाफ डुप्लेसिस एलबीडब्ल्यू बो. शमी	04	10	00	00
तेंबा बावुमा का. साहा बो. शमी	00	03	00	00
हेनरिक क्लासेन एलबीडब्ल्यू बो. उमेश	05	24	00	00
जॉर्ज लिंडे रन आउट	27	55	05	00
डेन पीट बो. जडेजा	23	73	02	01
थेउनिस डि ब्रूएन नाबाद	30	42	04	01
कैगिसो रबादा का. जडेजा बो. अश्विन	12	16	03	00
एनरिक नोर्टजे नाबाद	05	12	01	00

अतिरिक्त: 5 (बा–5),
कुल: 46 ओवर में आठ विकेट पर 132 रन
विकेट पतन: 1–5 (डिकॉक, 1.1), 2–10 (हमजा, 2.3), 3–18 (डुप्लेसिस, 6.6), 4–22 (बावुमा, 8.3), 4–26 (एल्गर, रिटायर्ड नॉटआउट), 5–36 (क्लासेन, 16.1), 6–67 (लिंडे, 28.3), 7–98 (पीट, 37.4), 8–121 (रबादा, 42.5), गेंदबाजी: शमी 9–5–10–3, उमेश 9–1–35–2, जडेजा 13–5–36–1, नदीम 5–0–18–0 अश्विन 10–3–28–1

विकेट लेने के बाद खुश उमेश यादव ● प्रेट्र

कोहली ने तोड़ा अजहर का रिकॉर्ड

रांची: कोहली विपक्षी टीम को सबसे ज्यादा बार फॉलोऑन देने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने मुहम्मद अजहरुद्दीन के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने सात बार विपक्षी टीम को फॉलोऑन दिया था। कोहली का कप्तान के रूप में यह 51वां टेस्ट मैच है। वहीं अजहर ने 47 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। महेंद्र सिंह धौनी ने 60 मैचों में पांच बार और सौरव गांगुली ने 49 मैचों में चार बार फॉलोऑन दिया।

पंत ने की कीपिंग

रांची: विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान दायें हाथ की अंगुली में गेंद लग गई थी। इसके बाद तीसरे दिन आखिर के एक घंटे तक साहा की जगह रिषभ पंत ने कीपिंग की। साहा की चोट फिलहाल ठीक है लेकिन मंगलवार की सुबह मैच से पहले उनकी चोट की जांच फिर की जाएगी।

मुझे गेंदबाजी एक्शन में करना होगा सुधार : शाहबाज नदीम

रांची: बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम ने सोमवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण टेस्ट की सिर्फ पहली तीन गेंदों तक ही वह नर्वस थे। इसके बाद वह सहज हो गए। हालांकि नदीम ने माना कि उन्हें बेहतर नतीजों के लिए अपने गेंदबाजी एक्शन में सुधार करना होगा। नदीम ने कहा कि मैं रोमांचित था और भावुक भी लेकिन मैंने अपने प्रदर्शन पर फोकस किया। मैं पहली तीन गेंद तक नर्वस रहा खासकर रनअप के दौरान। चौथी गेंद से मैं सहज हो गया। इस बायें हाथ के स्पिनर ने कहा कि मैं अपने फॉलो थ्रू पर काम कर रहा हूं। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे एक्शन और शरीर के वजन में तालमेल रहे। उन्होंने कहा कि इतने साल की मेहनत का फल मिलना अच्छा लग रहा है।

14 4, 2, 0, 4, 5 रनों की ओपनिंग साझेदारी अब तक दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाजों ने इस सीरीज में की है

11 भारतीय खिलाड़ियों में शाहबाज नदीम ने सबसे पहले 2004 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका पदार्पण इस मैच के जरिये हुआ। वर्तमान एकादश में शामिल खिलाड़ियों में प्रथम श्रेणी में सबसे देरी से पदार्पण मयंक अग्रवाल (2013) का हुआ था

16 विकेट मैच के तीसरे दिन गिराए भारत ने। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सबसे ज्यादा 20 विकेट 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ लिए हैं

03 या उससे ज्यादा विकेट लगातार पांच पारियों में घरेलू मैदान पर लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं उमेश यादव

एक नजर में

जीत के इरादे से उतरेंगी सिंधू

पेरिस: विश्व चैंपियन पीवी सिंधू मंगलवार से यहां शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में जब अपने अभियान की शुरुआत करेंगी तो उनकी नजरें फॉर्म हासिल करने पर टिकी होंगी। अगस्त में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के बाद से सिंधू खराब फॉर्म से जूझ रही हैं और इस दौरान वह तीन टूर्नामेंट में दूसरे दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रहीं। सिंधू पिछले महीने चीन ओपन के दूसरे जबकि कोरिया ओपन के पहले दौर में हार गई जबकि पिछले हफ्ते उन्हें डेनमार्क ओपन में भी दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। दुनिया की आठवें नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल भी फिटनेस को लेकर जूझ रही हैं और पिछले तीन टूर्नामेंट में पहले दौर में ही बाहर हो गईं। पुरुष सिंगल्स में 2017 के चैंपियन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत की राह आसान नहीं होगी। (प्रेट्र)

टीम सफल होगी : चानू

भुवनेश्वर: मिडफील्डर सुशीला चानू को विश्वास है कि भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहेगी क्योंकि पिछले तीन वर्षों में टीम ने काफी सुधार किया है। भारतीय टीम ने 36 साल बाद रियो ओलंपिक 2016 में जगह बनाई थी। अगले साल टोक्यो में होने वाले खेलों में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को एक और दो नवंबर को अमेरिका से भिड़ना है। सुशीला ने कहा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अहसास कैसा होता है क्योंकि हम 36 साल बाद रियो में खेले थे। हालांकि हम जब वहां से वापस लौटे थे तो सभी का मानना था कि हमें अपने खेल में लगातार सुधार करने और निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है जिससे हमें अगले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में मदद मिले। पिछले ओलंपिक के बाद हम काफी आगे बढ़ गए हैं और अब हम सभी टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। (प्रेट्र)

तैयार हैं गोल्फर वुड्स

चिबा (जापान): दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स ने सोमवार को पुष्टि की कि हाल ही में उन्होंने अपने घुटने की सर्जरी कराई थी और अब वह टूर्नामेंटों में खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वह इस सप्ताह से शुरू होने वाले जोजो चैंपियनशिप में खेल सकते हैं। वह चोट के कारण दो महीने तक गोल्फ कोर्स से दूर रहे थे। उनके 21 अगस्त को बायें घुटने की सर्जरी हुई थी और वह गुरुवार को होने वाले चैंपियनशिप के पहले दौर में खेलने के लिए तैयार हैं। वुड्स ने कहा कि मैं इस चैंपियनशिप में खेलने को लेकर उत्साहित हूं। मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूं। मैं इस चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। (रायटर)

बांग्लादेश के भारत दौरे पर संकट के बादल

ढाका, प्रेट्र: बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के भारत दौरे पर संशय के बादल छा गए हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने भारत दौरे से ठीक पहले क्रिकेट का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक उनका क्रिकेट बोर्ड उनकी मांगे नहीं मानता है तब तक वह किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे।

बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने इसकी घोषणा सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में की, जिसमें बांग्लादेश की टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान शाकिब अल हसन और महमुदुल्लाह जैसे सीनियर क्रिकेटर भी शामिल थे। खिलाड़ियों के बहिष्कार करने से राष्ट्रीय क्रिकेट लीग, भारत सीरीज के लिए जारी ट्रेनिंग कैंप और अंतरराष्ट्रीय टीम का भारत दौरा खटाई में पड़ता दिख रहा है। क्रिकेटरों के विरोध की शुरुआत पिछले महीने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस फैसले से हुई, जिसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल को समाप्त कर दिया गया था।

खिलाड़ियों की 11 मांग: खिलाड़ियों ने अपनी मांगों की सूची बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थमा दी है, जिसमें कुल 11 मांग की गई है। इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल को फिर से लाने की मांग भी शामिल है। खिलाड़ी इसलिए बोर्ड के फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल के समाप्त करने के विरोध में आ गए थे, क्योंकि इससे उनकी कमाई पर असर पड़ा था।

इस वजह से भी बढ़ी नाराजगी: खिलाड़ियों की नाराजगी उस समय और बढ़ गई जब बोर्ड ने इस महीने शुरू हुई प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता की मैच फीस में भी इजाफा नहीं किया। पेशेवर खिलाड़ी बीते एक महीने से भी अधिक समय से इस बारे में आवाज उठा रहे हैं।

क्रिकेटरों को कप्तान शाकिब का समर्थन: कप्तान शाकिब अल हसन ने भी बोर्ड के रवैये से नाराजगी जताई थी। हसन ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि खिलाड़ियों को दबाया जा रहा है और उनके साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। शाकिब ने कहा था कि प्रथम श्रेणी खेलने वाले क्रिकेटरों को एक लाख (बांग्लादेश टका) मिलना चाहिए जो अभी सिर्फ 35 हजार रुपये है। वहीं प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों का भत्ता भी 50 प्रतिशत बढ़नी चाहिए। शाकिब ने कहा कि अभी प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को सिर्फ 1500 टका दैनिक भत्ता मिलता है। मुझे लगता है कि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए यह रकम बेहद कम है। हम खुश होंगे अगर बोर्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को देश भर में मैच खेलने के लिए हवाई टिकट मुहैया कराए। बोर्ड के एक सूत्र की मानें तो टीम का भारत दौरा नहीं टलेगा, क्योंकि 22 नवंबर को ईडन गार्डेंस में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहुंचने का वादा किया है। अगर बांग्लादेश यह दौरा छोड़ता है, तो आइसीसी भारत को सीरीज में जीत देगा।

बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने किया क्रिकेट के बहिष्कार का ऐलान

यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का निजी मामला है, लेकिन मेरे क्षेत्र से बाहर है। हालांकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश भारत दौरा रद नहीं करेगा।
– सौरव गांगुली, बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष

यह मामला अभी हमारे सामने आया है और हम इसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि भारत का दौरा रद करने की जरूरत है। खिलाड़ियों ने अभी तक आधिकारिक रूप से हमसे बात नहीं की है, लेकिन हम इस मामले को देख रहे हैं।
– निजामुद्दीन चौधरी, सीईओ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड

भारत को फैसले का इंतजार

नई दिल्ली: बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले पर करीब से निगाह बनाए हुए हैं। यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अंदरूनी मामला है। हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ऐसे में हमें इस मामले में अभी कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है।

किस्मत से हारकर बाहर हुई मुंबई

विजय हजारे ट्रॉफी

छत्तीसगढ़ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया

अलुर (कर्नाटक), प्रेट्र: छत्तीसगढ़ ने यहां जारी विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सोमवार को प्रवेश कर लिया। छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच सोमवार को यहां क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना था, लेकिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और मैच का कोई परिणाम नहीं आया।

छत्तीसगढ़ की टीम ने लीग चरण में मुंबई से ज्यादा मैच जीते थे और इसी के आधार पर उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। छत्तीसगढ़ की टीम ने लीग चरण में पांच मैच जीते थे जबकि मुंबई ने चार ही मैच जीते थे। बारिश के कारण क्वार्टर फाइनल मैच में ओवरों की संख्या में कटौती की गई। छत्तीसगढ़ ने 45.4 ओवर में छह विकेट पर 190 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में मुंबई ने बिना किसी नुकसान के 11.3 ओवरों में 95 रन बना लिए थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश खत्म होने के बाद मुंबई को 40 ओवर में 192 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। इसके जवाब में मुंबई ने 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 79 रन बना लिए थे और उसे अभी मैच जीतने के लिए 113 रन और बनाने थे कि तभी फिर बारिश शुरू हो गई और आगे का खेल संभव नहीं हो पाया।

छत्तीसगढ़ की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर पहले सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहले सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ का सामना बुधवार को बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेजबान कर्नाटक से होगा।

तमिलनाडु सेमीफाइनल में पहुंचा: तमिलनाडु और पंजाब के बीच यहां सोमवार को खेला जाने वाला चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। लीग चरण में ज्यादा मैच जीतने के आधार पर तमिलनाडु सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। सेमीफाइनल में तमिलनाडु का सामना बुधवार को गुजरात के साथ होगा। विजय हजारे ट्रॉफी के लीग चरण में तमिलनाडु ने नौ मैच जीते थे जबकि पंजाब को पांच मैचों में जीत मिली थी। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तमिलनाडु की शुरुआत खराब रही और मुरली विजय के साथ ही अभिनव मुकुंद भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद बाबा अपराजित ने 56 और वाशिंगटन सुंदर ने 35 रनों का योगदान दिया। बारिश की वजह से मैच को 39 ओवरों का कर दिया गया और तमिलनाडु ने छह विकेट पर 174 रन का स्कोर बनाया।

पंजाब के लिए मयंक मार्कंडेय ने दो विकेट चटकाए। पंजाब को वीजेडी नियम के तहत 39 ओवरों में जीत के लिए 195 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। पंजाब की शुरुआत खराब रही और टीम ने जल्द ही अभिषेक शर्मा (6) और अनमोलप्रीत सिंह (9) का विकेट गंवा दिया। पंजाब ने इसके बाद 12.2 ओवर में दो विकेट पर 52 रन बना लिए थे कि तभी बारिश आ गई और मैच को रद करना पड़ा।

आइसीसी में भारत के अच्छे दिन लाएगी जय–गांगुली की टीम : शुक्ला

सौरव गांगुली की अगुआई वाली बीसीसीआइ की नई टीम भारतीय क्रिकेट के भविष्य की रूप रेखा संवारने के लिए तैयार है। टीम नई है लेकिन चुनौतियां वहीं पुरानी हैं। इस टीम को बनाने में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व बीसीसीआइ अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन और पूर्व आइपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला का योगदान रहा। आइसीसी से लेकर घरेलू क्रिकेट को संवारने का माद्दा रखने वाली इस नई टीम से इन अधिकारियों को बहुत उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के दबदबे के बाद भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर राजीव शुक्ला से अभिषेक त्रिपाठी ने विस्तार में बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:

साक्षात्कार

● **सीओए के कार्यकाल के दौरान कई चीजें देखने को मिलीं। अब नया बीसीसीआइ आ रहा है। ऐसे में आप क्रिकेट प्रशासक के रूप में किस तरह के बदलाव की उम्मीदें कर रहे हैं?**

-देखिए जो बदलाव होने जा रहे हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट को मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीओए को नियुक्त किया था और उसने करीब तीन साल तक देश में क्रिकेट का संचालन देखा। अब जो नई टीम आने जा रही है, वे मूल रूप से क्रिकेट प्रशासक हैं। इन लोगों के आने से बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि वे क्रिकेट की बारीकियों को जानते हैं। सौरव गांगुली की गिनती सबसे सफल कप्तानों में होती है और बंगाल क्रिकेट संघ को भी उन्होंने चलाया है। जय शाह बीसीसीआइ की बैठकों में कई वर्षों से आ रहे हैं और अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवा रहे हैं। इसी तरह से अरुण सिंह धूमल भी कई वर्षों से हिमाचल क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। ब्रजेश पटेल आइपीएल की देखरेख करेंगे और सभी को पता है कि उनका भी क्रिकेट में कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा भी लोगों को मौका मिल रहा है, चाहे वह उपाध्यक्ष माहिम वर्मा हों या फिर संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज।

● **सीओए के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं। क्या आप उनके कार्यकाल से खुश हैं ?**

-देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। डायना इडुल्जी को छोड़कर सीओए के बाकी लोगों को क्रिकेट का अनुभव नहीं था। तो उन्होंने अपने हिसाब से प्रशासक का काम देखा। जब उन्हें क्रिकेट संचालन का जिम्मा सौंपा गया तो उन्होंने अपनी क्षमताओं के हिसाब से उसे किया लेकिन उन लोगों के पास क्रिकेट की बारीकियों का ज्ञान नहीं था। भारत में कैसे हजारों मैच होते हैं, कैसे उनका आयोजन होता और कैसे चयन प्रक्रिया होती, उनको इन सभी बातों की जानकारी नहीं थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनके कामकाज का विश्लेषण कोई मायने रखता है। सौरव गांगुली ने अपने नामांकन के दौरान कहा था कि यह बीसीसीआइ में आपात स्थिति थी और अब उसमें बदलाव होगा।

● **आइसीसी में बीसीसीआइ की साख कमजोर हुई है। अब जय और गांगुली की जोड़ी के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी?**

-हमें फिर से आइसीसी में बीसीसीआइ का प्रभुत्व कायम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आइसीसी में भारत की आवाज कमजोर हुई है। अब हमें उस आवाज को बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत है। जब एक चुना हुआ बोर्ड बैठेगा तो उसका आत्मविश्वास अलग ही नजर आएगा। उस आधार पर सौरव गांगुली और जय शाह की जोड़ी अच्छा काम करेगी।

● **मैच आवंटन की प्रक्रिया की बात करें तो अब नॉर्थ ईस्ट और छोटे-छोटे राज्यों को भी मैच मिलने लगे हैं। ऐसे में राज्य क्रिकेट संघों की वर्तमान हालत को आप कैसे देखते हैं ?**

-देखिए यह निर्णय लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद हुआ, जहां तमाम राज्य संघों को नई सदस्यता दी गई। मेरे हिसाब से यह अच्छा कदम है। इससे वहां धीरे-धीरे क्रिकेट का विकास होगा और वे अच्छा क्रिकेट ढांचा तैयार कर लेंगे।

● **बीसीसीआइ में यूपीसीए से आपके प्रतिनिधित्व को चुनाव अधिकारी ने रद किया। क्या इससे यूपीसीए की राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति कमजोर हुई है?**

-यूपीसीए का प्रभुत्व वैसे ही पूरी तरह से कायम है। बीसीसीआइ की नई टीम भी यूपीसीए के साथ निश्चित रूप से भरपूर सहयोग करेगी क्योंकि उनके चयन में यूपीसीए का पूरा समर्थन था। उपलब्ध लोगों में यह सबसे अच्छा पैनल है। रही बात मेरी तो उन्होंने आइपीएल में मेरे चेयरमैन रहने को आधार बनाते हुए कूलिंग ऑफ का हवाला दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वह सिर्फ बीसीसीआइ के पदाधिकारियों पर लागू होता है लेकिन फिर भी इसको चुनाव अधिकारी ने नहीं माना। यह सिर्फ एक एजीएम और एक चुनाव की बात है। अब नया बोर्ड तय करेगा कि आगे क्या होना है। उत्तर प्रदेश को मैच मिलेंगे।

● **यूपीसीए और दूसरे कई राज्य संघ भी आपको बीसीसीआइ के अध्यक्ष के तौर पर देख रहे थे। क्या चुनाव अधिकारी के फैसले के बाद आपको निजी तौर पर निराशा हुई ?**

-देखिए मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं था। ना तो मैंने यह बात कही और ना ही मैंने ऐसी कोई उम्मीद की। चुनाव अधिकारी ने मेरे नामांकन को ही अयोग्य करार दे दिया तो ऐसे सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में ना तो मेरी ऐसी कोई योजना थी और ना ही मुझे इससे कोई दुख है।

● **आप लंबे समय तक यूपीसीए के सचिव रहे हैं। ऐसे में मौजूदा समय में आप उत्तर प्रदेश में क्रिकेट की हालत को कैसे देखते हैं ?**

-उत्तर प्रदेश के आज हर जिले में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। हमने यहां के जिलों में यह व्यवस्था लागू की कि मैचों के जरिये टीम का चयन किया जाए। इसके लिए मंडल में उनका ट्रायल होता है और फिर वह फाइनल ट्रायल के लिए कानपुर जाते हैं। जो प्रतिभाशाली लड़के हैं वहीं आगे जाते हैं। हमारी अंडर-19 टीम तो बहुत ही अच्छा कर रही है। इतना ही नहीं अंडर-16 और अंडर-23 में भी हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन सीनियर टीम की नाव फाइनल में पहुंचकर फंस जाती है। इसको सुधारना है।

● **यूपीसीए ने कानपुर का ग्रीनपार्क स्टेडियम लीज पर ले रखा है। इकाना स्टेडियम प्राइवेट है जबकि गाजियाबाद में एक स्टेडियम बन रहा है। ऐसे में इनके बीच सामंजस्य बना पाना कितना मुश्किल काम है?**

-उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है इसलिए हमारी तीन स्टेडियम की परिकल्पना है। ग्रीनपार्क एक ऐतिहासिक स्टेडियम है जहां 75 वर्षों से क्रिकेट मैच होते आ रहे हैं। एक समय में वहां नियमित रूप से टेस्ट मैच आयोजित कराए जाते थे। इसके साथ हमारा 30 साल का अनुबंध है। दूसरा अतिआधुनिक इकाना स्टेडियम लखनऊ में है जहां 50000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। तीसरा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में गाजियाबाद में एक स्टेडियम बनाने की हमारी योजना है क्योंकि प्रदेश का वह हिस्सा खाली रह जाता है।

● **बीसीसीसीआइ के नए चयन पैनल में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?**

-निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का वहां ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। जो नई टीम आ रही है उसका रुख भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सकारात्मक है। पुराने हम सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। चाहे वह अनुराग ठाकुर हों या फिर एन श्रीनिवासन या फिर डालमिया परिवार हो, इन सभी का भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान है। इनके अलावा दूसरे कई लोगों ने भी उत्तर प्रदेश को अपना सहयोग दिया है। ऐसे में मुझे लगता है कि बोर्ड में सभी लोग भारतीय क्रिकेट और उत्तर प्रदेश क्रिकेट को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं।

● **लोढ़ा समिति की सिफारिशों की वजह से बाहर हो चुके पुराने दिग्गजों की बोर्ड में भूमिका को आप कैसे देखते हैं?**

-चाहे वह अनुराग हों या श्रीनिवासन या दूसरे लोग, इन सभी की भूमिका बहुत सकारात्मक है। बीसीसीआइ की इस नई टीम को लाने में उनकी भूमिका बहुत सकारात्मक रही है। उन सभी के योगदान से एक नई टीम बनी है और चुनाव के बाद ये नए लोग अपने-अपने पद ग्रहण करने जा रहे हैं। इनको लगातार हमारा सहयोग बना रहेगा। कैसे अच्छी तरह से क्रिकेट संचालित करें और कैसे भारतीय क्रिकेट की पुरानी शान-ओ-शौकत वापस आए इसके लिए यह टीम प्रयास करेगी।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

मंगलवार 22 अक्टूबर 2019

स्पोर्ट्स

www.jagran.com

कोहली को लेना है बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का फैसला

कोलकाता, जेएनएन : बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ तीन नवंबर से शुरू हो रही टी-20 सीरीज खेलने का फैसला कप्तान विराट कोहली को लेना है। ऐसी अटकलें हैं कि कोहली टी-20 सीरीज से बाहर रह सकते हैं लेकिन इंदौर और कोलकाता में दो टेस्ट खेलेंगे। कोहली ने विभिन्न प्रारूपों में पिछले 56 में से 48 मैच खेले हैं। गांगुली ने यहां बंगाल क्रिकेट संघ मुख्यालय पर पत्रकारों से कहा कि मैं 24 अक्टूबर को उनसे मिलूंगा।

कूल्हे की सर्जरी के बाद यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं यूरोपियन ओपन जीतकर खुश हूं।
– एंडी मरे, ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी

कादिर का बेटा उस्मान पाक टी-20 टीम में

क्रिकेट डायरी ▶ पूर्व कप्तान सरफराज को टेस्ट सीरिज और टी-29 से किया बाहर

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में टी-20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट सीरीज के लिए अपने जमाने के दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के पुत्र सहित पांच नए चेहरे टीम में शामिल किए हैं जबकि हाल में बर्खास्त किए गए कप्तान सरफराज अहमद को दोनों ही टीम से नजरअंदाज किया गया है।

लेग स्पिन आलराउंडर 26 वर्षीय उस्मान को टी-20 टीम में चुना गया है। वह पिछले सत्र में ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में खेले थे। यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर उन्हें पाकिस्तानी टीम में नहीं चुना जाएगा तो वह ऑस्ट्रेलिया में बस जाएंगे। सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक, मुहम्मद हफीज और अहमद शहजाद को भी टी-20 टीम में नहीं चुना गया है। पूर्व कप्तान सरफराज की जगह पर दोनों प्रारूपों में विकेटकीपर बल्लेबाज मुहम्मद रिजवान को रखा गया है। मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने टीम की घोषणा की जिसमें बल्लेबाज खुशदिल शाह, तेज गेंदबाज मूसा खान और उस्मान को टी-20 टीम में पहली बार जगह मिली है। मूसा खान और नसीम शाह के अलावा बायें हाथ के स्पिनर कासिफ भट्टी को टेस्ट टीम में लिया गया है। तेज गेंदबाज इमरान खान सीनियर की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है।

उस्मान कादिर। (फाइल)

टेस्ट टीम : अजहर अली (कप्तान), आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम, हैरिस सोहेल, इमाम उल हक, इमरान खान सीनियर, इफ्तिखार अहमद, काशिफ भट्टी, मुहम्मद अब्बास, मुहम्मद रिजवान, मूसा खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, यासिर शाह।

टी-20 टीम : बाबर आजम (कप्तान), आसिफ अली, फखर जमां, हैरिस सोहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मुहम्मद आमिर, मुहम्मद हसनैन, मुहम्मद इरफान, मुहम्मद रिजवान, मूसा खान, शादाब खान, उस्मान कादिर, वहाब रियाज।

टी-10 लीग में भारतीय खिलाड़ियों को देखना अच्छा होगा : रॉबिन सिंह

अबूधाबी : भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी रॉबिन सिंह अबूधाबी टी-10 लीग में नॉर्दर्न वॉरियर्स के कोच होंगे। यह टीम बीते सत्र विजेता रही थी और रोबिन टीम के साथ खिताब बचाने को लेकर तैयार हैं। लीग का आगामी संस्करण 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। रॉबिन ने कहा कि हमारे पास एक संतुलित टीम है और हम इस सत्र अपना खिताब बचाने की कोशिश करेंगे। हमने बीते साल जिस तरह की किकेट खेली थी, उसे खेलना जारी रखेंगे और उम्मीद है कि हम सफल होंगे।

हमारा टीम प्रबंधन बीते सत्र से ही हमारे लिए उत्साह का स्त्रोत बना हुआ है। भारतीय किकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) अपने अनुबंधित खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति नहीं दे रहा है। भारत के मौजूदा खिलाड़ी टी-10 लीग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। रॉबिन ने कहा कि अगर भारतीय खिलाड़ियों को यहां खेलने की अनुमति मिलती, तो यह अच्छा होता।

रोहित अपने आप से बदला ले रहे हैं : अख्तर

नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि भारत के नए टेस्ट सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बीते कुछ वर्षों में टेस्ट में अच्छा न कर पाने का बदला अपने आप से ले रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है जिसका तीसरा मैच रांची में खेला जा रहा। रोहित इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने विशाखापत्तनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था। रांची में पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा। इस सीरीज में रोहित पारी की शुरुआत कर रहे हैं जबकि इससे पहले वे टेस्ट में मध्य क्रम में खेला करते थे। अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अब, हर कोई मानेगा कि रोहित शर्मा महान बल्लेबाज थे और महान हैं। उन्होंने सीमित ओवरों में अपनी इच्छा के मुताबिक रन बनाए, उन्हें पता था कि वह एक बड़े मंच टेस्ट क्रिकेट पर कुछ खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहित को अब पता चल रहा है कि उनकी काबिलियत क्या है।

क्रिस गेल और मलिंगा को द हंड्रेड में नहीं मिला खरीददार

लंदन, आइएएनएस : क्रिस गेल और लसित मलिंगा को टी-20 प्रारूप के बड़े खिलाड़ियों में गिना जाता है, लेकिन नई लीग द हंड्रेड के पहले सत्र के प्लेयर ड्राफ्ट में इन दोनों दिग्गजों को खरीददार नहीं मिले। इतना ही नहीं, लीग के पहले राउंड के प्लेयर ड्राफ्ट में टी-20 की मौजूदा रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा जमाए हुए पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को भी कोई भी टीम खरीदने को राजी नहीं हुई। दिग्गजों के तिरस्कार की यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। इसमें क्विंटन डिकॉक, कीरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो और तमीम इकबाल जैसे खिलाड़ियों के नाम भी हैं।

आइसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, गेल और मलिंगा ने अपना आधार मूल्य 125,000 पाउंड (करीब एक करोड़ 15 लाख रुपया) रखा था। मिशेल स्टार्क, डेविड वार्नर और कैगिसो रबादा ने भी इतनी ही बेस प्राइस रखी थी। ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गजों स्टार्क और स्मिथ को वेल्स फायर ने खरीदा। वार्नर को साउथर्न ब्रेव ने। स्मिथ ने ट्वीट किया कि अगले साल होने वाले द हंड्रेड में वेल्स फायर का हिस्सा बनकर खुश हूं। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान को सबसे पहले खरीदा गया। वह ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से खेलेंगे। इस टीम में राशिद के साथ इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट होंगे। पहले राउंड के प्लेयर ड्राफ्ट में आंद्रे रसेल को साउथर्न ब्रेव, आरोन फिंच, मुजीब उर रहमान को नॉर्थन सुपरचार्जर्स, सुनील नरेन को ओवल इनविंसिवल, इमरान ताहिर, डेन विलास को मैनचेस्टर ओरिजनल्स, ग्लेन मैक्सवेल को लंदन स्प्रिट, और लियाम प्लंकट को बर्मिंघम फोनिक्स ने खरीदा। कुल 570 खिलाड़ी रविवार को हुए पुरुषों के प्लेयर ड्रॉफ्ट में शामिल रहे जिसमें 239 विदेशी और 331 घरेलू खिलाड़ी थे। पहले राउंड में कुल 96 खिलाड़ियों को खरीदा गया। द हंड्रेड प्रारूप अगले साल जुलाई में लांच होने वाला है।

एंड्रयू मैक्डोनाल्ड बने राजस्थान रॉयल्स के कोच

मुंबई : आइपीएल के पहले सत्र का खिताब अपने नाम करने वाली राजस्थान रॉयल्स ने ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू बैरी मैक्डोनाल्ड को अगले तीन साल के लिए अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

ऑस्ट्रेलिया के लिए चार टेस्ट मैच खेलने वाले एंड्रयू ने सीनियर कोच के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में विक्टोरिया को ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड का खिताब दिलाया था। इसके अलावा वह इंग्लैंड की काउंटी टीम लीसेस्टशर और ऑस्ट्रेलियाई क्लब मेलबर्न रेनेगेड्स के कोच भी रह चुके हैं। एंड्रयू का आइपीएल से पुराना नाता है। वह 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेल चुके हैं। दिल्ली के बाद वह 2012-13 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर में भी गए थे लेकिन बेंगलूर के साथ उनका करार गेंदबाजी कोच का था। एंड्रयू ने कहा कि रॉयल परिवार का हिस्सा बनकर मैं काफी खुश हूं। मेरे लिए इस जिम्मेदारी को लेना सम्मान की बात है। राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए नई और रोमांचक चुनौती है। मैं इस टीम में मौजूद विश्व स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं। एंड्रयू का चयन टीम के हेड ऑफ क्रिकेट जुबीन बरूचा सहित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले अन्य लोगों ने मिलकर किया है।

मैच देखने नहीं पहुंचे माही, सेना की जीप का ले रहे आनंद

जागरण संवाददाता, रांची

▶ भारत के पूर्व कप्तान धौनी के काफिले में सेना की पुरानी जीप जोंगा भी जुड़ी

▶ धौनी प्रशंसकों से मिले, ऑटोग्राफ भी दिया व फोटो भी खिंचवाई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी रांची में है लेकिन मैच देखने जेएससीए स्टेडियम नहीं जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि रांची में रहते हुए आखिर धौनी क्या कर रहे हैं? धौनी रांची में सेना के जोंगा वाहन की सवारी का आनंद ले रहे हैं। इंग्लैंड में हुए विश्वकप के बाद से धौनी क्रिकेट से दूर हैं। सितंबर माह में उन्होंने ग्रैंड चेरोकी गाड़ी खरीदी थी अब सेना के पुराने वाहन जोंगा को कारों के काफिले में शामिल कर लिया है।

पिछले दो दिनों से सिमलिया से इस गाड़ी से निकल रहे हैं और धुर्वा, मेकॉन कॉलोनी का चक्कर लगा कर वापस चले जा रहे हैं। रविवार को धौनी अपनी इस गाड़ी से एक पेट्रोल पंप पहुंचे वहां उन्हें प्रशंसकों ने देख लिया। गाड़ी का शीशा चढ़ा हुआ था लेकिन पहचान लिए जाने के बाद धौनी प्रशंसकों से मिले और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया तथा फोटो भी खिंचवाई।

धौनी का कार व बाइक प्रेम किसी से छुपा नहीं है। उनके पास कार व बाइक का काफी अच्छा क्लेक्शन है। बाइक व कार रखने के लिए उन्हें अपने सिमलिया स्थित घर में शोरूम की तरह हॉल बना रखा है।

महेंद्र सिंह धौनी। (फाइल)

धौनी के पास कारों के कलेक्शन में जोंगा, चेरोकी के अलावा हमर, ऑडी क्यू सेवन, लैंड रोवर, जीएमसी , फेरारी 599, पजेरो, कोरेला व स्कॉर्पियो आदि शामिल हैं।

टॉटनहम के सामने नई चुनौती

यूएफा चैंपियंस लीग

लंदन, एएफपी : इंग्लिश फुटबॉल क्लब टॉटनहम हॉट्सपर की इस सत्र की शुरुआत बेहद खराब रही है लेकिन अब यूएफा चैंपियंस लीग में मंगलवार को रेड स्टार बेलग्रेड के रूप में उसके सामने एक नई चुनौती होगी। हालांकि तमाम परेशानियों के बीच 12 महीने पहले वाली स्थिति से टॉटनहम बेहतर स्थिति में है और इसका फायदा वह इस घरेलू मुकाबले में उठा सकता है।

पिछले साल इंटर मिलान और बार्सिलोना से हार के बाद पीएसवी के खिलाफ होने वाले मुकाबले को टॉटनहम के मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो ने करो या मरो का मुकाबला बताया था। पीएसवी के खिलाफ नीदरलैंड्स में 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद पोचेटिनो ने कहा था कि चैंपियंस लीग में उनका सफर करीब करीब समाप्त हो गया लेकिन उसके आठ महीने बाद पोचेटिनो ने पहली बार टॉटनहम को चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचाया।

हालांकि फाइनल में लिवरपूल से हारने का असर टॉटनहम पर अभी तक देखने को मिल रहा है। टॉटनहम की टीम सभी प्रतियोगिताओं में खेले अपने पिछले 12 मुकाबलों में से केवल तीन में जीत दर्ज कर पाई है। टीम का लीग कप में सफर समाप्त हो गया है। उसे चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 2-7 की झकझोर देने वाली हार झेलनी पड़ी थी। वाटफोर्ड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ छूटे पिछले लीग मुकाबले के बाद पोचेटिनो ने स्वीकार किया था कि बायर्न के खिलाफ हार के बाद टीम का आत्मविश्वास जमीन पर आ गया। हालांकि ग्रुप-बी में मंगलवार को टॉटनहम ने सर्बियाई क्लब रेड स्टार को हरा दिया तो वह ग्रुप तालिका में दूसरे स्थान पर आ जाएगा।

एक सच्चाई यह भी है कि कप्तान हुगो लॉरिस के चोटिल होकर बाहर होने से टॉटनहम की परेशानी बढ़ चुकी है और उनकी अनुपस्थिति में गोलकीपिंग की जिम्मेदारी पाउलो गाजानिगा संभालेंगे। हालांकि डेले अली के फॉर्म में आने से हैरी केन से थोड़ा दबाव कम होगा।

सिटी चैंपियंस लीग जीतने के लिए तैयार नहीं : गॉर्डियोला

लंदन : इंग्लिश प्रीमियर लीग में शनिवार को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 2-0 की जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गॉर्डियोला ने कहा था कि सिटी तब तक चैंपियंस लीग का खिताब नहीं जीतेगी जब तक वह गोल के सामने ज्यादा प्रभावशाली खेल नहीं दिखाएगी। गॉर्डियोला ने कहा कि हमने वाटफोर्ड के खिलाफ बहुत मौके गंवाए।

हमें प्रभावशाली खेल दिखाना होगा। चैंपियंस लीग की बात करें तो हम अभी तैयार नहीं हैं लेकिन हम सुधार कर सकते हैं। चैंपियंस लीग के ग्रुप-सी में मंगलवार को मैनचेस्टर सिटी का सामना अपने घरेलू मैदान पर इटालियन क्लब अटलांटा से होगा।

आज के मुकाबले

- एटलेटिको मैड्रिड बनाम बायर लेवेरकुसेन
- शाख्तार डोनेस्क बनाम डायनमो जाग्रेब
- क्लब ब्रूग बनाम पीएसजी
- गालातसारी बनाम रीयल मैड्रिड
- जुवेंटस बनाम लोकोमोटिव मॉस्को
- मैनचेस्टर सिटी बनाम अटलांटा
- ओलंपियाकोस बनाम बायर्न म्यूनिख
- टॉटनहम हॉट्सपर बनाम रेड स्टार बेलग्रेड

बीसीसीआइ के एजीएम बैठक की अध्यक्षता करेंगे गांगुली : राय

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) मुख्यालय में बुधवार को होने वाली बैठक एक आम बैठक है। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष सौरव गांगुली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की अध्यक्षता करेंगे।

विनोद राय

राय ने कहा कि बुधवार को होने वाली बैठक के लिए सदस्यों को जो नोटिस भेजे गए थे, उसे लेकर कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वास्तव में यह एक आम बैठक है कि न कि एजीएम, जैसा कि कुछ इसे कह रहे हैं। राय ने कहा कि यह एक आम बैठक है क्योंकि इसमें पदाधिकारियों का चयन होता है। यह सीओए द्वारा चुनाव आयोजित कराने के लिए बुलाई गई एक आम बैठक है। सीओए ने कभी भी वार्षिक आम बैठक या विशेष बैठक नहीं बुलाई है। सीओए का आदेश बीसीसीआइ के प्रशासन को चलाने और लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन में मदद करने के लिए था। आम बैठक में विभिन्न राज्यों के सभी उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा था कि बीसीसीआइ के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन राय ने पुष्टि की कि प्रशासकों की समिति ही बैठक की अध्यक्षता करेगी। उन्होंने कहा कि सीओए की अध्यक्षता में ही बैठक होगी।

राय ने कहा कि गांगुली और नए अधिकारियों की उनकी टीम एजीएम की बैठक बुलाएगी और यह बीसीसीआइ के संविधान के अनुसार 21 दिनों के नोटिस के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, वह एजीएम के लिए बैठक करेंगे। इस बैठक का केवल दो एजेंडा है, इसलिए उन्हें एजीएम बैठक बुलाना होगा क्योंकि उन्हें बहुत सारी नियुक्तियां करनी है। यह अध्यक्ष (गांगुली) और सचिव (जय शाह) का विशेषाधिकार है। उन्हें 21 दिन के नोटिस की जरूरत पड़ेगी। वह इससे पहले ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे बुधवार को आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही ऐसा करेंगे।

विविध

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा उड़ान भर रहे भारतीय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया भारतीय हवाई यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अकेले आइजीआइ एयरपोर्ट से ही प्रतिवर्ष करीब आठ लाख यात्री ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भर रहे हैं। वहां जाने वाले यात्रियों की वार्षिक वृद्धि दर 16 फीसद तक पहुंच गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के करीब नौ शहर ऐसे हैं जहां जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा हो रहा है। जाने वालों का मुख्य उद्देश्य वहां रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है। वहीं, पढ़ाई और पर्यटन भी इसके प्रमुख कारण हैं।

इंटनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आइएटीए) के आंकड़ों के मुताबिक गत वित्तीय वर्ष में भारत से 19 लाख लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया। इनमें अकेले आइजीआइ एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों की भागीदारी 41 फीसद रही। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट से क्रमशः 16, 8, 7 और 3 फीसद यात्री ऑस्ट्रेलिया गए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुताबिक, भारतीय यात्रियों की पहली पसंद ऑस्ट्रेलिया का मेलबॉर्न शहर है। यहां पर 33 फीसद यात्री जाते हैं। 25 फीसद भारतीय सिडनी का रुख करते हैं। वहीं 10 फीसद ब्रिसबेन, 6 फीसद पर्थ और पांच फीसद एडिलेड जाते हैं।

डायल के सीइओ विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि भविष्य में भी इस मार्ग में अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद है बढ़ते यात्रियों की संख्या के मद्देनजर आने वाले समय में यहां से कई हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं। आइजीआइ एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं।

छह लाख भारतीय रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में

ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में वहां करीब छह लाख भारतीय निवास करते हैं। इसके अलावा करीब एक लाख भारतीय छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ाई और करियर के अच्छे साधन होने के कारण भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं।

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कुछ दिन नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिवाली व छठ पूजा की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर 25 अक्टूबर से दो नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यह प्रतिबंध केवल तीन दिन 25 से 27 अक्टूबर तक रहेगा। महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंद यात्रियों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इनकी सहायता के लिए रेलवे स्टेशन पर आने वालों को प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय भी बनाए जा रहे हैं। वैध टिकट वाले ही स्टेशन परिसर में दाखिल हो सकें, इसके लिए प्रवेश द्वार पर टिकट की जांच की जाएगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा आनंद विहार टर्मिनल पर 25 अक्टूबर से एक नवंबर तक सभी प्रकार के पार्सल के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान न तो पार्सल की बुकिंग होगी और न ही बाहर से आने वाला सामान यहां उतारा जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया कदम। (फाइल)

यात्रियों को सामान अपने साथ ही लेकर जाना होगा। प्लेटफॉर्म पर पार्सल को इकट्ठा करने और प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रालियां चलाने पर भी रोक रहेगी। हालांकि रजिस्टर्ड समाचार-पत्र/पत्रिकाओं की बुकिंग स्वीकार की जाएंगी।

पूर्व दिशा की ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म निर्धारित : नई दिल्ली से बिहार की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर-16 से रवाना होंगी। जरूरत के अनुसार कुछ ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर-15 से भी चलेंगी। यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) पर नहीं चढ़ना पड़े इसे ध्यान में रखा जाएगा। अजमेरी गेट की तरफ से आकर यात्री प्लेटफार्म नंबर 16 से ट्रेन में सवार होंगे तो एफओबी पर भीड़ नहीं लगेगी। सिर्फ प्रवेश व निकास गेट से ही आवाजाही होगी।

रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे टिकट काउंटर

नई दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर जनरल टिकट काउंटरों को की संख्या बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली में 120 टिकट काउंटर व 60 पूछताछ केंद्र होंगे। यात्रियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए अजमेरी गेट की तरफ टेंट लगाकर अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है जिसमें टिकट काउंटर व पूछताछ काउंटर भी बनेंगे। आनंद विहार टर्मिनल पर भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। पुरानी दिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर भी अस्थाई टिकट काउंटर खोले जाएंगे।

वाराणसी में उड़ान भरने के दौरान विमान का टायर फटा, 84 यात्री सुरक्षित

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▶ एटीसी की तत्परता और पायलट की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टली

▶ स्पाइसजेट का विमान जा रहा था अहमदाबाद

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 84 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद जा रहा विमान सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। रन-वे पर रफ्तार भरने के दौरान विमान के एक पहिये का टायर फट गया। विमान उस समय तक रन-वे छोड़ चुका था, लिहाजा क्रैश होने से बच गया। पायलट की सूझबूझ एवं एटीसी के एहतियात से अहमदाबाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

स्पाइस जेट एयरलाइंस का विमान एसजी 972 सुबह 9.10 बजे उड़ान भरने को रन-वे पर रफ्तार भर रहा था। इसी बीच अचानक तेज धमाके साथ टायर फटकर बिखर गया। यात्री चीखने-चिल्लाने लगे तो केबिन क्रू मेंबर ने यात्रियों को शांत कराया। न घबराने की नसीहत देते हुए घटना को सामान्य बताया। उस समय तक विमान रन-वे छोड़ चुका था। एटीसी को सूचना मिली तो वाराणसी से अहमदाबाद तक अलर्ट जारी हो गया।

एयरपोर्ट निदेशक आकाशदीप, एटीसी के सीनियर अधिकारी आरपी निगम रन-वे पर पहुंचे तो लैंडिंग पहिये के पार्ट्स बिखरे पड़े थे। एटीसी ने पायलट एवं अहमदाबाद एयरपोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी दी। विमान अहमदाबाद पहुंचा तो वहां आपातकालीन सेवा से जुड़े अधिकारियों ने सुरक्षित लैंडिंग कराई। यात्रियों ने बताया कि विमान के पहिए से धुआं निकलने पर वह डर गए थे। उन्हें घबराहट होने लगी थी।

रनवे से फिसलकर नाले में जा घुसा ट्रेनी विमान

अमेठी : अमेठी के फुरसतगंज स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में एक प्रशिक्षु विमान उतरते समय रनवे से फिसलकर नाले में जा घुसा, जिससे उसमें आग लग गई। प्रशिक्षु पायलट ने सूझबूझ से विमान से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सोमवार दोपहर ट्रेनी पायलट जसप्रीत ने जीलिन (विमान का नाम) विमान से सेकंड सोलो उड़ान भरी थी। दोपहर तीन बजकर 20 मिनट पर विमान को नीचे उतारते समय विमान रनवे पर फिसल गया और कच्चे मार्ग से होते हुए नाले में जा घुसा। इसी बीच विमान में आग लग गई। ट्रेनी पायलट ने आपातकाल प्रशिक्षण में दिए गए टिप्स को अपनाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंचे दमकल वाहन की मदद से विमान में लगी आग पर काबू पाया गया

संत थ्रेसिआ के चमत्कार का प्रमाण देने वाले डॉक्टर से आइएमए ने जवाब मांगा

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : हाल ही में पोप फ्रांसिस ने केरल की नन मरियम थ्रेसिया को संत घोषित किया था। एक नवजात बच्चे के स्वस्थ होने में उनके चमत्कार का प्रमाण देने वाले केरल के डॉक्टर संकट में घिर गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की केरल इकाई ने अपनी आचार समिति से डॉ. वीके श्रीनिवासन द्वारा दिए गए प्रमाण की जांच करने को कहा है। त्रिचूर स्थित अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ श्रीनिवासन से आइएमए ने आचार का उल्लंघन पर विचार करने के बारे में जवाब मांगा है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, नवजात क्रिस्टोफर सांस लेने की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। 2009 में उसकी दादी ने मरियम थ्रेसिया का स्मारक उसकी बेड पर रख दिया जिसके बाद उसकी हालत में सुधार आ गया।

कोलकाता में हवाई अड्डे पर दिव्यांग महिलाओं के साथ सुरक्षाकर्मियों ने किया दुर्व्यवहार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ दिव्यांगता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल होने जा रही थीं दिल्ली

▶ नहीं मिली व्हीलचेयर, कैलिपर्स पहनने के कारण पैंट उतारकर दिखाने को कहा गया

▶ जीजा घोष पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की पोस्टर गर्ल थीं

▶ कुहू डिस्एबिलिटी एक्टीविस्ट फोरम की सचिव थीं

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को दो दिव्यांग महिलाओं को घंटेभर सुरक्षाकर्मियों और एयरलाइंस के कर्मचारियों के असंवेदनशील रवैये का सामना करना पड़ा। उनके नाम जीजा घोष व कुहू दास हैं। दोनों कोलकाता से उन चार प्रतिनिधियों में शामिल थीं, जो नई दिल्ली में दिव्यांगता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में शामिल होने जा रही थी।

जीजा घोष को पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की पोस्टर गर्ल थी, ताकि मतदान के लिए दिव्यांगों को प्रेरित किया जा सके। वहीं कुहू डिस्एबिलिटी एक्टीविस्ट फोरम की सचिव थीं। वह पोलियोग्रस्त हैं, इसलिए कैलिपर्स (पैरों को सहारा देने के लिए पहना जाना वाला उपकरण) पहनती हैं। सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहीं जीजा को हवाई अड्डे पर व्हील चेयर के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वहां तैनात सीआइएसएफ के एक कर्मी ने उनसे कहा कि वे अकेले यात्रा नहीं कर सकतीं। वहीं मेटल डिटेक्टर जांच के दौरान कुहू ने बताया कि वह पैरों को सहारा देने के लिए धातु के कैलिपर्स पहनती हैं। इस पर उनसे अपनी पैंट उतारकर दिखाने को कहा गया। जब दोनों के समझाने पर सुरक्षाकर्मी और एयरलाइंस के कर्मचारी नहीं माने तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मसले को उठाया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और उनके हस्तक्षेप से सभी को उड़ान भरने की इजाजत मिली।

इस मामले में एयरलाइंस ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि व्हीलचेयर में इसलिए देर हुई क्योंकि पहले से इसका उल्लेख नहीं किया गया था और सभी व्हीलचेयर भरी हुई थीं। दूसरी ओर सुरक्षा जांच पर अधिकारियों का कहना था कि फूलप्रूफ सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा था। उन्होंने असुविधा के लिए खेद जताया।

नक्सलियों के भय से गांव छोड़ने को मजबूर हुआ परिवार

जेएनएन, भुवनेश्वर : ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक आदिवासी परिवार ने नक्सलियों के डर से अपना गांव-घर छोड़ दिया है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराने के साथ पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद घटना की छानबीन कर रही है। घटना जिले के डाबूगुड़ा गांव की है। नक्सलियों की धमकी मिलने के बाद अब तक इस गांव के लगभग 100 लोग अपना घर छोड़ कर अन्य जगहों पर चले गए हैं।

बताया गया कि माओवादी नेता राकेश पिछले 28 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इस मुठभेड़ के पीछे इस परिवार का हाथ होने का संदेह प्रकट कर कुछ दिन पहले 50 से अधिक नक्सली गांव में पहुंचे और उक्त परिवार के घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद प्रजा कोर्ट (जनता अदालत) में उन्हें गांव छोड़ने का फरमान जारी किया।

© Copyright Skymet Company 2019: All rights reserved.

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में मुख्यतः साफ आसमान के साथ सुहावनी सुबह में धुंध रहेगी। दिन हल्का गर्म रहेगा। दोपहर में हल्की से मध्यम पश्चिमोत्तर हवा चलेंगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह ठंडी और दिन सहज रहेगा। रात का मौसम ठंडा बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/23/व	अहमदाबाद	33/21/व
कोलकाता	34/25/आंबा	बड़ौदा	33/21/व
चेन्नई	31/24/व	नागपुर	31/21/व
हैदराबाद	30/23/आंबा	इन्दौर	29/19/आंबा
बंगलूरू	27/21/आंबा	राँची	30/22/व
त्रिवेन्द्रम	30/24/आंबा	पटना	32/24/आंबा
गुवाहाटी	29/23/व	जमशेदपुर	32/23/व
गंगटोक	12/-1/व	पुणे	27/22/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
मंगलवार 22 अक्टूबर 2019
16
www.jagran.com

भारत का पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 लांच किया गया

2008 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने देश के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 को लांच किया था। महज 386 करोड़ रुपये लागत वाला यह अंतरिक्ष यान अगस्त, 2009 तक सक्रिय रहा। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान-1 ने ही लगाया था।

दुनिया की पहली रिकॉर्डेड पैराशूट जंप सफलतापूर्वक हुई

1797 में आज ही फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर के ऊपर एक किलोमीटर की ऊंचाई से आंद्रे जैक्स पैराशूट लेकर कूद गए थे। यह पहली रिकॉर्डेड पैराशूट जंप थी और उनका यह पैराशूट सिल्क यानी रेशम का बनाया हुआ था।

आजादी के परवाने थे क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां का जन्म 1900 में आज ही शाहजहांपुर में हुआ था। 1925 में उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्ला खां ने रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और बनवारी लाल जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 19 दिसंबर, वर्ष 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले अशफाक उल्ला खां ने वारसी और हसरत के नाम से हिंदी और उर्दू में कई कविताएं और गजलें भी लिखी थीं।

इधर-उधर की

यूएई में आठ हजार साल पुराना मोती मिला

अबु धाबी, एजेंसी : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबु धाबी के मारवाह द्वीप में खोदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 8000 साल पुराना एक मोती मिला है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मोती है। हालांकि, इसकी कीमत कितनी है, इसका आकलन अभी नहीं किया गया है। 30 अक्टूबर को अबु धाबी में ही इसे प्रदर्शित किया जाएगा। यहां के इतिहास विशेषज्ञों के मुताबिक, 16वीं सदी में अबु धाबी के तटों पर मोती मिलते थे। इसका जिक्र उस समय के कारोबारी रहे गासपारो बाल्बी ने भी किया था। एक समय था जब यूएई की अर्थव्यवस्था मोतियों के कारोबार पर ही टिकी हुई थी, लेकिन 1930 में जापानी किस्म के मोतियों के आगमन के साथ ही यहां का व्यापार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया।

कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा ईंधन

तकनीक ▶ अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया उत्प्रेरक

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को काफी हद तक किया जा सकेगा कम

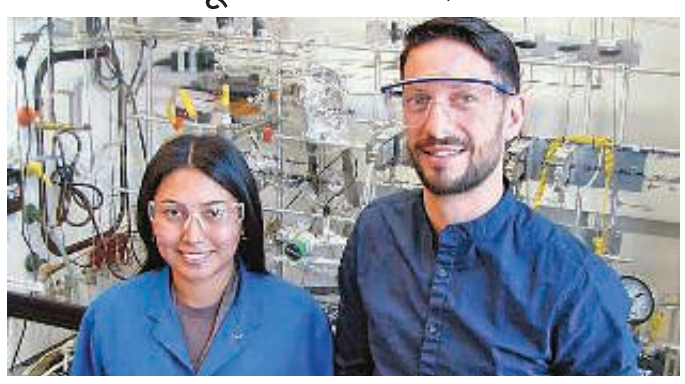

शोधकर्ता के साथ स्टैनफोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर मैटेओ कारगेल्लो। फाइल

बोस्टन, प्रेट्र : कल्पना कीजिए कि हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं उसे ईंधन में बदल सकें तो क्या होगा? इससे न केवल हम कई बीमारियों से बच सकेंगे, बल्कि हमारे पास प्राकृतिक गैस के विकल्प भी मौजूद होंगे। भले ही यह एक कल्पना लगे, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत में बदल दिया है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) विकसित किया है, जो कार के पाइप और अन्य स्रोतों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में बदल सकता है।

हाल के कई अध्ययनों में वैज्ञानिकों को इस दिशा में कुछ हद तक सफलता भी मिली थी, लेकिन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों के नवीनतम दृष्टिकोण से मौजूदा तरीकों की तुलना में चार गुना अधिक इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का उत्पादन किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसे तैयार करने का तरीका भी अन्य प्रक्रियाओं जैसा ही है। अंगेवांडटे केमी नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह तरीका प्रदूषित जलवायु को पूरी तरह साफ नहीं कर सकता, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

प्रयोगशाला में मिली सफलता : स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और इस अध्ययन के नेतृत्वकर्ता मैटेओ कारगेल्लो ने कहा, 'अब हम कार्बन के एक ऐसे चक्र की कल्पना कर सकते हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड से ईंधन का उत्पादन कर उसे जलाया जा सकता है और उससे दोबारा नए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और उसे फिर से ईंधन में बदला जा सकता है।' हालांकि, शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को प्रयोगशाला में सिद्ध किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इसका उपयोग पर्याप्त मात्रा में ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

जहरीले उत्पादकों में कमी लाना लक्ष्य : शोधकर्ताओं ने कहा, 'अब उनका अगला कदम ईंधन के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले उत्पादकों में कमी लाना है। इस तरीके से शोधकर्ताओं की टीम ईंधन के साथ-साथ अन्य लाभदायक उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इन उत्पादों में एक है एल्कीन, जिसका औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रयोग होता है। इसका मुख्य घटक प्लास्टिक होता है।

दो चरणों में बनाया जाता है ईंधन : शोधकर्ताओं ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में बदलने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड कम करता है। दूसरे में हाइड्रोकार्बन ईंधन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि इन ईंधनों में मीथेन बनाना सबसे सरल था, लेकिन अन्य ईंधनों का उत्पादन ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की मदद से किया गया।

गैसों का इन क्षेत्रों में होता है प्रयोग: शोधकर्ताओं ने कहा कि ईथेन का प्राकृतिक गैसों से करीबी संबंध है। इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले एथिलीन के लिए किया जा सकता है। प्रोपेन का प्रयोग सामान्यतः बिजली संयंत्रों में किया जाता है, जबकि ब्यूटेन का प्रयोग स्टोव जलाने के लिए किया जाता है।

ऐसे तैयार किया उत्प्रेरक: कार्गेलो ने बताया, ' ईंधन बनाने के लिए चरणों में काम करने की बजाय हम एक ही प्रक्रिया में दोनों चरणों को पूरा कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रभावी भी है। इसके लिए हमने एक नया उत्प्रेरक बनाया, जो एक ऑक्सीजन अणु को कार्बन डाइऑक्साइड से अलग कर सकता है और इसे हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकता है।'

प्रिंस हैरी ने माना, विलियम के साथ उनकी राहें जुदा

ब्रिटेन के शाही परिवार के भाइयों में मनमुटाव की बात पुख्ता हो गई है। फाइल फोटो /एएफपी

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने यह मान लिया है कि उनकी और उनके बड़े भाई प्रिंस विलियम की राहें अब जुदा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके संबंधों में अच्छे और खराब दोनों दिन आते रहे हैं। हैरी और विलियम के बीच मनमुटाव की खबरें हाल के महीनों में सामने आई थीं। इन खबरों पर प्रिंस हैरी ने दक्षिण अफ्रीका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान कहा, 'हम भाई हैं और हमेशा रहेंगे। यकीनन हमारे रास्ते अब अलग हैं, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और मैं यह जानता हूं कि वह भी ऐसा ही करेंगे। हम व्यवस्तता के चलते एक-दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं।' प्रिंस हैरी ने अपनी पत्नी मेघन मर्केल के साथ दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। मेघन को लेकर भी ऐसी अफवाह उड़ी थी कि प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन के साथ उनकी अनबन चल रही है।

शोध अनुसंधान

वैज्ञानिकों ने तैयार की कृत्रिम त्वचा

टच टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसी कृत्रिम त्वचा तैयार की है, जो मनुष्य की त्वचा की तरह स्पर्श का अनुभव करने में सक्षम है। इसे कई परत में सिलिकॉन मेंब्रेन से तैयार किया है। यह देखने में भी मनुष्य की त्वचा जैसी ही है। इसकी मदद से उपकरण अपने यूजर की पकड़ महसूस कर सकेंगे। रोबोट के मामले में यह त्वचा बेहद कारगर साबित हो सकती है। इस त्वचा की मदद से रोबोट यह समझ सकेंगे कि उन्हें कब कितने दबाव से छुआ गया है। ऐसा होने से रोबोट इंसानों जैसा बनाना संभव हो सकता है। शोधकर्ता एन रॉडॉट ने कहा, 'त्वचा की क्षमता से हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आश्चर्य की बात है कि अब तक रोजाना इस्तेमाल वाले उपकरणों में त्वचा की इस खूबी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? फिलहाल नया शोध इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।' -एएनआइ

कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स खेलना बच्चों के लिए फायदेमंद

खेलना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन यह फायदा और बढ़ जाता है, जब बच्चे ऐसा खेल खेलते हैं, जिसमें उन्हें अन्य बच्चों से टकराते हुए खेलना पड़े। इस तरह के खेलों को कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स कहा जाता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल इस श्रेणी में आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन खेलों में शामिल रहने वाले बच्चों की समझ बेहतर तरीके से विकसित होती है। ऐसे बच्चों में आगे चलकर अवसाद की आशंका भी कम रहती है। वैज्ञानिकों ने 11,000 बच्चों पर 14 साल तक अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि जो बच्चे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं उनमें युवावस्था में दिमागी परेशानियों की आशंका बहुत कम रहती है। शोधकर्ता एडम बोर ने कहा, 'आम धारणा है कि कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में सिर में चोट लगने और दिमागी परेशानी की आशंका रहती है। शोध में ऐसा नहीं पाया गया। बल्कि ऐसे बच्चे दिमागी रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं।' - आइएएनएस

जीन में छेड़छाड़ के बगैर बढ़ाई चूहे की जिंदगी

लंदन, प्रेट्र : वैज्ञानिक पहली बार जीन में कोई भी छेड़छाड़ किए बगैर चूहे की जीवन अवधि बढ़ाने में सफल हुए हैं। दरअसल, अब तक जीवों के दीर्घ आयु के निर्धारण में जीन को ही एक मात्र घटक माना जा रहा था। हालांकि, स्पैनिश नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर (सीएनआइओ) ने अपने प्रयोग से इस धारणा को बदला दिया है। उन्होंने एक ऐसा चूहा विकसित किया है, जिसके टेलोमर्स की लंबाई अन्य की तुलना में काफी अधिक है।

- उम्र के साथ छोटे होते टेलोमर्स बनते हैं बुढ़ापे का कारण
- वैज्ञानिकों ने विकसित किया ज्यादा लंबे टेलोमर्स वाला चूहा
- इस तरह के जीवों का स्वास्थ्य रहता है बेहतर

यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

टेलोमर्स डीएनए के प्रत्येक छोर पर मौजूद एक टोपीनुमा संरचना है, जो क्रोमोजोम की सुरक्षा करता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ इनकी लंबाई घटती जाती है। यही वजह है कि व्यक्ति एक समय के बाद बूढ़ा होने लगता है। बुढ़ापा व टेलोमर्स के इसी संबंध को ध्यान में रखकर सीएनआइओ के शोधकर्ताओं ने हाइपर-लांग टेलोमर्स (अत्यधिक लंबा) वाला चूहा विकसित किया। खास बात यह रही कि वह चूहे की प्रत्येक कोशिका में हाइपर-लांग टेलोमर्स विकसित करने में कामयाब हुए हैं। नेचर कम्युनिकेशन नामक जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक इस तरह के टेलोमर्स वाले जीवों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वह लंबा जीवन जीते हैं। इसके अलावा उनमें कैंसर व मोटापे का खतरा घट जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'इस अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमें एक ही प्रणाली पर विश्वास करने की बजाए समस्याओं के समाधान के अन्य रास्ते भी खोजने चाहिए।'

पहले भी हुए थे प्रयोग : टेलोमर्स के लंबाई कम होने से रोकने के लिए पूर्व में भी कई प्रयोग हुए थे। इनमें ज्यादातर मौके पर टेलोमर्स की लंबाई के लिए जिम्मेदार टेलोमरीज नामक प्रोटीन को सक्रिय किया गया था। सीएनआइओ समूह ने भी पहले एंजाइम को सक्रिय करने के लिए जीन थेरेपी विकसित की थी। हालांकि, ताजा अध्ययन में उन्होंने जीन से छेड़छाड़ के बगैर ही टेलोमर्स की लंबाई बढ़ाने में सफलता हासिल कर ली।

दुबई में टैक्सी ड्राइवरों पर नजर रखेंगे कैमरे

दुबई, एएनआइ : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई शहर में अब सारे टैक्सी ड्राइवर कैमरे की निगरानी में काम करेंगे। इसके लिए शहर में चलने वाली सभी 10,648 टैक्सी वाहनों में निगरानी कैमरा लगा दिया गया है। इन गाड़ियों में एक खास तरह का ऑटोमेटिक सेंसर फिट किया गया है, जिससे यात्री के सवार होते ही कैमरा चालू हो जाता है और वहां की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होने लगती हैं।

दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के निदेशक खालिद अल अवदी ने बताया कि टैक्सी वाहनों में कैमरे लगने से सवारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और टैक्सी ड्राइवर को पेशेवर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टैक्सी वाहनों में कैमरे लगाने का काम दो साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। कई चरणों में चला यह कार्य अब जाकर पूरा हो गया है। इससे दुबई सरकार के स्मार्ट सिटी अभियान को भी बल मिला है। आरटीए ग्राहकों की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वजनदार शिशुओं में ज्यादा होती है एलर्जी की संभावना

कैनबरा, आइएएनएस : जिन शिशुओं का वजन ज्यादा होता है उनमें फूड एलर्जी या एक्जिमा से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया गया है।

15,000 अध्ययनों की स्क्रिनिंग करने के बाद शोधार्थियों ने 42 की पहचान की है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा एलर्जी पीड़ितों का डाटा शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता कैथी गैटफोर्ड ने कहा, 'हमने जन्म के समय बच्चों का वजन और वयस्कों की एलर्जी संबंधी बीमारियों का विश्लेषण किया।' इस दौरान उन्होंने पाया कि जन्म के समय वजन में वृद्धि से बच्चे में फूड एलर्जी का 44 फीसद खतरा बढ़ता है और एक्जिमा होने का 17 फीसद खतरा होता है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'यदि बच्चे का वजन

प्रतीकात्मक

लगातार बढ़ रहा है तो हमें इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। यदि बच्चे फूड एलर्जी के शिकार हो जाएंगे तो उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाएगा और वे कई अन्य बीमारियों के घिर सकते हैं।' शोधकर्ताओं ने बताया कि इस अध्ययन में ज्यादातर विकसित यूरोपीय देशों के बच्चों को शामिल किया गया था।

डिजिटल म्यूजियम में सेल्फी का क्रेज

चीन के झेजियांग प्रांत में वुझेन शहर में आयोजित विश्व इंटरनेट कान्फ्रेंस के लिए बनाए गए खास म्यूजियम में सेल्फी लेती महिलाएं। इस सम्मेलन में 76 देशों के दो हजार से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह डिजिटल म्यूजियम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सम्मेलन में इंटरनेट के विकास, नई तकनीक और उत्पादों के बारे में जानकारी दी जाती है। कान्फ्रेंस में इंटरनेट के समक्ष भावी चुनौतियों पर भी चर्चा होनी है। एएफपी

रोशनी से जगमग हुआ बुर्ज खलीफा

दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। आसमान छूती इस इमारत का सौंदर्य देखते ही बनता है। अगले साल होने वाले वैश्विक व्यापार मेले के लिए बुर्ज खलीफा पर रोशनी की गई है। दुनियाभर से प्रतिनिधि शिरकत करने दुबई आते हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुर्ज खलीफा आठ अरब डॉलर की लागत से छह साल में बनकर तैयार हुई थी। 828 मीटर ऊंची और 168 मंजिला बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में शुमार है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'टर्मिनेटर' सीरीज में महिला किरदार हमेशा दमदार रहे हैं : टिम मिलर

हॉलीवुड लगातार महिला केंद्रित फिल्में बनाता आया है। 'डार्क फीनिक्स', 'चार्लीज एंजेल्स', 'इजंट इट रोमांटिक', 'हसलर्स', 'कैप्टन मार्वल' जैसी फिल्मों में अभिनेत्रियों का दबदबा रहा है। टर्मिनेटर सीरीज की फिल्मों में भी महिला किरदारों को तवज्जो दी गई है। टर्मिनेटर की छठवीं फिल्म 'टर्मिनेटर : डार्क फेट' के निर्देशक टिम मिलर का कहना है कि इस फिल्म की तीनों अभिनेत्रियां लिंडा हैमिल्टन, नटालिया रेयेस और मैंकेजी डेविस मुख्य किरदार हैं और उन्हें दमदार रखा गया है। यह फिल्म भी महिला केंद्रित होगी। टिम मिलर का मानना है कि जिस तरह से टर्मिनेटर सीरीज में लिंडा हैमिल्टन ने एक्शन किया था, उससे महिला केंद्रित किरदारों का बढ़ावा मिला है। उनकी वजह से फिल्मों में महिलाओं के एक्शन करने को बल मिला है। मूल फिल्म में जबरदस्त एक्शन कर चुकीं 63 वर्ष की लिंडा हैमिल्टन 'टर्मिनेटर : डार्क फेट' में हाथों में बंदूक थामे एक बार फिर जबरदस्त एक्शन कर रही हैं। टिम मिलर का कहना है कि लिंडा ने इस किरादर के लिए एक साल तक तैयारी की है। फिल्म की तैयारी के लिए जो उन्होंने पुशअप्स और पुलअप्स किए हैं, वे देखने में मुश्किल लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से लिंडा ने उसे किया है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने इस फिल्म के लिए हर एक दिन ट्रेनिंग की है। टिम के मुताबिक लिंडा ने जिस तरह का काम किया है, वह दूसरी अभिनेत्रियां भी अगर चाहें तो कर सकती हैं। उनका कहना है कि वह फिल्मों में महिला और पुरुष दोनों के लिए एक जैसा एक्शन ही डिजाइन करते हैं। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'द टर्मिनेटर' वर्ष 1984 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया था। अर्नोल्ड श्वार्जनेगर अभिनीत फिल्म 'टर्मिनेटर : डार्क फेट' भारत में 1 नवंबर को हिंदी समेत 6 भाषाओं में रिलीज होगी।

अगर एक्टर नहीं होतीं तो सिंगर होतीं इलियाना डिक्रूज

अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने अनुराग बासु की फिल्म 'बर्फी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि इलियाना एक्टर नहीं, बल्कि सिंगर बनना चाहती थीं। इलियाना कहती हैं, 'एक्टिंग को करियर के रूप में चुनना अचानक हुआ। मैं तो हमेशा से सिंगिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत में शायद इसी फील्ड में आना लिखा था।' शो 'द लव लाफ लाइव' के एक एपिसोड में होस्ट शिवानी दांडेकर ने जब उनसे उनके मॉडलिंग से बॉलीवुड तक के सफर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह सिंगिग में करियर की संभावनाएं तलाश रही थीं। वह अगर एक्टिंग में नहीं आतीं तो सिंगर ही होतीं। इलियाना ने बॉलीवुड से पहले तेलुगु फिल्म 'देवदास' से करियर शुरू किया था। हिंदी फिल्म 'बर्फी' में उनके रोल को प्रशंसा मिली थी। उसके बाद की फिल्मों 'रुस्तम', 'मैं तेरा हीरो', 'बादशाहो' और 'रेड' में उन्होंने अपनी पहचान इंडस्ट्री में बनाई। जब उनसे पूछा गया कि वे किस को-स्टार के साथ काम करना पसंद करती हैं, तो इलियाना ने कहा मेरी सबसे अच्छी बांडिंग नरगिस फाखरी के साथ है। उनके अलावा अरशद वारसी और वरुण धवन के साथ भी अच्छा लगता है। इलियाना को फोटोशॉप इमेजेज और इंस्टाग्राम फिल्टर्स पसंद नहीं हैं। वह कहती हैं, 'आप जैसे दिखते हैं, वैसी ही तस्वीरें होनी चाहिए। फिल्टर करके अपने आप से झूठ बोलने फायदा नहीं है।'

'होटल मुंबई' के असल हीरो ने की अनुपम खेर की मदद

अनुपम खेर अपनी 501वीं फिल्म में असली हीरो का किरदार निभा रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'होटल मुंबई' होगी। फिल्म में अनुपम खेर शेफ हेमंत ओबेरॉय का किरदार निभाएंगे। 'होटल मुंबई' फिल्म वर्ष 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए आंतकी हमले पर आधारित है। होटल के शेफ हेमंत ओबेरॉय ने अपनी

जान की परवाह न करते हुए आंतकी हमले के दौरान होटल में घुसे आंतकवादियों के बीच होटल में रह रहे कई मेहमानों और स्टाफ की जान बचाई थी। फिल्म में अनुपम खेर के किरदार की तैयारी के लिए हेमंत ओबेरॉय ने खुद उनकी मदद की है। अपने व्यक्तित्व को समझाने के साथ ही हेमंत ने उन्हें उस घटना की हर छोटी-बड़ी जानकारियों से रूबरू कराया था। अनुपम खेर का कहना है कि हेमंत का किरदार फिल्म में निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ऐसे इंसान का किरदार निभाना, जो इस बात में दृढ़ता से यकीन रखता हो कि उसे किसी भी तरह से अपने होटल में रह रहे मेहमानों की जान बचाना है, आसान नहीं है। अनुपम बताते हैं कि हेमंत ने इस किरदार को निभाने की प्रक्रिया में उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि हेमंत के लिए उसे काले और भयानक अध्याय को याद करना आसान नहीं था।

एक दिन में रिलीज हुए दो अलग फिल्मों के पोस्टर

प्रमोशन के इस जमाने में कोई अपनी फिल्मों से जुड़ी हर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करता रहता है। सोमवार के दिन दो फिल्मों के पोस्टर रिलीज किए गए। एक ओर सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म 'दबंग 3' का नया पोस्टर जारी किया है, वहीं दूसरी ओर अजय देवगन ने अपनी पीरियड फिल्म 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' का पहला पोस्टर जारी किया है। 'दबंग 3' के पोस्टर पर सोनाक्षी सिन्हा बुलेट मोटरसाइकिल के साथ दबंग स्टाइल में नजर आ रही हैं। पोस्टर साझा करते हुए सलमान ने लिखा, 'हिंदुस्तानी सभ्यता की चक्की से बनी हमारी सुपर सेक्सी रज्जो...।'

अध्ययन

आइआइटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने विकसित की सूरजमुखी के पौधे की कोशिकाएं, अब दस गुना ज्यादा हो सकेगा विटामिन ई का उत्पादन

सूरजमुखी में विटामिन की मात्रा बढ़ाएंगी कोशिकाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास के वैज्ञानिकों ने सूरजमुखी के पौधे की कोशिकाएं विकसित की हैं, जो सामान्य सूरजमुखी के मुकाबले दस गुना ज्यादा विटामिन ई का उत्पादन कर सकते हैं। नई तकनीक से विटामिन ई का प्रभावी और कुशल व्यावसायिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि विटामिन ई का सबसे सक्रिय रूप 'अल्फा-टोकोफेरॉल' शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ विषैले रसायनों से ऊतकों को बचाने में मदद करता है, जिन्हें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पिशीज के रूप में जाना जाता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रयोगशालाओं में रासायनिक रूप से संश्लेषित 'अल्फा-टोकोफेरॉल' पौधों में पाए जाने वाले अपने प्राकृतिक रूप से कम सक्रिय होता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक पर काम शुरू किया, जिसमें विटामिन ई का उत्पादन बढ़ाया जा सके। शोधकर्ताओं ने कहा, 'सूरजमुखी के फूल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके पौधे की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयोगशाला में सूरजमुखी के पौधे की कोशिकाओं में बदलाव कर एक नई कोशिका विकसित की, जो तेजी से अल्फा-टोकोफेरॉल का उत्पादन कर सकती है।'

विटामिन ई का भंडार है सूरजमुखी। प्रतीकात्मक

ऐसे तैयार की कोशिका : अध्ययन में बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने सूरजमुखी से विटामिन ई का उत्पादन करने वाले जीनों को अरबिडोप्सिस नामक पौधे में डाला। कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि दोनों का मेल होने से अल्फा-टोकोफेरॉल का उत्पादन काफी बढ़ गया था।

कारगर है नया दृष्टिकोण : शोधकर्ताओं ने कहा कि विटामिन ई का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग और सेलुलर इंजीनियरिंग का उपयोग करना फायदेमंद साबित हुआ। विज्ञान की भाषा में इसे तर्कसंगत दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके जरिये उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यदि अरबिडोप्सिस कोशिकाओं में थोड़ा बदलाव किया जाए तो कौन से एंजाइम अधिक अल्फा-टोकोफेरॉल का उत्पादन करते हैं। जब शोधकर्ताओं ने प्रयोगात्मक रूप से कोशिकाओं में एक एंजाइम की मात्रा को बढ़ाया, तो सामान्य कोशिकाओं की तुलना में प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं ने दस गुना अधिक अल्फा-टोकोफेरॉल का उत्पादन किया।

समय और धन की बचत : आइआइटी मद्रास के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक कार्तिक रमन ने कहा, 'नया तरीका पारंपरिक 'हिट एंड ट्रायल' तरीकों के काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह प्रक्रिया मूल्यवान संसाधनों के साथ-साथ समय और धन की बचत कर सकती है।' इस अध्ययन की सह-लेखिका स्मिता श्रीवास्तव ने कहा, 'मॉडल आधारित तकनीक एक प्लेटफॉर्म तकनीक के रूप में काम कर सकती है, जिसमें हम किसी भी पौधे से जैव ईंधन जैसे वांछित उत्पाद तैयार कर सकते हैं।'